

Ho 37]

नई विरुली, शनिवार, सितम्बर 12, 1987 (भाष्रपद 21, 1909)

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1987 (BHADRA 21, 1609)

इस मान में भिश्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह असन संकलन के कप में रखा का सकी। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग Ш—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा कारी की गई विविध अधिस्चनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और सूर्वनी यम्मिलत हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-14, विनांक 14 अगस्त 1987

सं० एडीएम/35570—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्न-लिखित ियुक्ति ग्रधिसूचित की जाती है:

श्री एस० व्ही० चंट्टी, ग्रधिकारी, शीर्ष प्रबन्धतः श्रेणीमान-6 ने 8 ग्रगस्त 1987 को कार्यकाल की समाप्ति से उप महा-प्रबन्धक (भविष्य िधि), केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

> सी० प्रारं विजयराघवन, मुख्य महाप्रबन्धक, (कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास) (3111)

इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय

REGISTERED NO. D-(DN)-128

कलकता-700 001, दिनांक 19 भ्रगस्त 1987

सं विधि/1/87--सा० का० नि०--वैंककारी कम्पनी (उपकमों का ग्रधिग्रहण ग्रौर ग्रन्तरण) ग्रधिनियम 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहा-बाद बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ग्रीर केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इलाहाबाद बैंक (श्रधि-कारी) मेवा विियम, 1979 में और भागे संशोधन करने के लिए. एतद्द्वारा िम्दलिखित विभियम बनाता है।

- 2. संक्षिप्त शीर्थंक श्रीर प्रारम्भ :--(1) इन विनियमों का नाम इलाहाबाद बैंक (प्रधिकारी) सेवा (संगोधन) विनियम, 1986 होगा ।
 - (2) ये 25-7-1986 से लाग हैं।

1-239 GI/87

3112	भारत का राजपत्र, सित्म्बर	12, 198	७ (भाद्रपद	21 , 190	09) । ।भाग 11	[——ख उड ४
विनियम 19 के उप	वैंक (श्रधिकारी) सेवा विनियम 1ः विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के बाद जोड़ा गया है, यथा :—		1 4.	2 82032	3 श्री सतजीत सिंह, ए० सी० ए०	1-4-87
''बशर्ते यह भी कोई मधिकारी , उप सार, श्रादे श जारी ह	कि सक्षम प्राधिकारी के द्यादेश से ाकिनियम (2) में दिए गए प्रावधान होने के एक माह के श्रन्दर सक्षम प्रा में निदेशक मंडल को लिखित रूप में	के ग्रनु- धिकारी	•	92002	हैंसी फाइट लि०, हैंसी हाऊस, एस्कोर्ट रोड, बेडफोन्ट, फेल्याम मिडलसैंक्स टी० डब्ल्यू० 148 क्यू० एच०	
प्राप्त होने पर निदेश तथा तीन माह की श मंडल यह निर्णय ले	संबंधित अधिकारी से इस प्रकार का शक मंडल उसके आवेदन पर विचार प्रविधि के श्रन्वर कोई निर्णय लेगा। यदि ताहै कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जा	: करेगा निदेशक री किया	5.	82444	श्री पंक्रज गुप्ता, ए० सी० ए०, सी- 60, एन० डी० एस० ई० पार्ट, 1, नई विल्ली	4-5-87
	गत नहीं है तो संबद्ध श्रधिकारी को ! जैसे कि सक्षम प्राधिकारी ने कोई श्रादेश		6.	83018	श्री राजन चौघरी, ए० सी० ए०, ए-3/68, पश्चिम विहार,	1-4-87
	एम० श्रार० सर्वा सहायक महाप्रबन्धक		7.	83280	नई दिल्ली-110063 श्री राहुल सेनन,	1-4-87
न ई दि ल्ली-1 सं० 3-एन० सी	। चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 10002,दिनांक 21 भ्रगस्त 1987 (चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स) ० ए० (8)/2/87–88—चार्टर्ड प्राप्				ए० सी० ए०, मैसर्स हीम बिल्डर्स सिडीकेट, 1/8बी, जिंदल ट्रस्ट बिल्डिंग, झासफ झली रोड, नई दिल्ली 110002	
श्रनुसरण में एतद्द्वार सदस्यों को जारी वि	64 के वितियम 10 / (1) खण्ड (त रायह सूचित किया जाता है कि तिस् केए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्न उनके भागे र दिए गए हैं क्योंकि वे श्रपने प्रैक्टिस च्छुक नहीं हैं।	तिलिखित दीगई	8.	84667	श्री बिमल कुमार लूथरा, ए० सी० ए०, 2-बी/10, भाई० ए० भार० भा पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली 110012	1-4-87 €∘,
क० सदस्यता सं० सं०	नाम एवं पता	दिनांक	9.	84822	श्री गुलगन कुमार सेठी, ए० सी० ए०, ए-55, सुभद्रा कोलोनी,	6-3-87
1 2	3	4			सराद्व रोहिल्ला, दिल्ली 110035	
1. 17785	श्री प्रतीग नारायन भट्टाचारजी, एफ० सी० ए० 7371, ई० एन० घटाक सर्कल, ग्रनाहीन 92807, कोलीफोनिया (यू०एस०ए०)	1-4-87	10.	84864	श्री तबीत भषत गुप्ता, ए० सी० ए०, 862, विकास कुंज, विकास पुरी, तई दिल्ली 110018	9-4-87
2. 24562	श्री वद्दीपार्ती भास्कर, ए० सी० ए०, केयर श्रोफ फेरो श्रल्लोयस कारपोरेशन लि०, श्री राम नगर 532101,	1-4-87	11.	84899	मिसिज भ्रनीता भ्राप्तन्य, ए० सी० ए०, बी-93, भ्रमर कोलोनी, लाजपन-गर 4, पर्द विल्ली 110024	1-4-87
3. 70064	डिस्ट० विजियावग्राम (ए०पी०) श्री मुक्तिल कुमार गुप्ता, ए०सी०ए०, कोठीनं० 3348,सैक्टर 23-डी,	1-1-87	12.	85108	मिसिज नीरज घेई, ए० सी० ए०, डी-232, डिफेंस कोलोनी, नई दिल्ली-110024	1-3-87

चण्डीगढ़ 160023

1 2	3	4
13. 85 357	श्री संजीव कमल, ए० सी० ए०,	1-4-87
	35ए, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली	
14. 85725	श्री मनोहर लाल, ए० सी० ए०,	18-2-87
	सी-6/75ए, ला <i>रैं</i> स रो ड ,	
	वि ल्ली-110035	

नं० 3-एन० सी० ए० (8)/3/87-88--रेगूलेशन 10-(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतव्झारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्न 1 अगस्त 1986 से रह् समझे जायेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1986-87 के लिए कार्य प्रमाण पत्न हेत् वार्षिक मुल्क का भुगतान नहीं किया था।

ऋ० स दस्य ता	नाम एवं पता	
संख्या सं०		_
1. 81284	श्री गुरमीत सिंह अरोड़ा,	
	एफ० सी० ए०,	
	डी-305, आनन्द विहार,	
	विल्ली-110092	
2. 83057	श्री चन्द्रा प्रकाश बाहरी,	
	ए० सी० ए०,	
	152, शक्ति विहार,	
	विल्ली-11003 4	
3. 83991	श्री पुर्नेश्वरश्रेष्ठा,	
	ए० सी० ए०,	
	8/199, मखन तोले,	
	काठमांडू, नैपाल	
4. 84546	श्री आर० रमानी,	
<u>-</u>	ए० सी० ए०,	
	রী 658, ত্তী ০ আ ई০ <mark>গীত</mark> ,	
	एरिया, मंदिर मार्ग,	
	नई विल्ली-110001	
		-

दिमांक 24 अगस्त 1987

नं० 3-एम० सी० ए० (8)(4)/87-88--- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनयम 1964 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्निचित सदस्यों का जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई

तिथियों से रद्द	कर दिए गए हैं	क्योंकि वे अपने	प्रैक्टिस प्रमाण
पत्न को रखने व			

ऋ० सदस्यता संख्या संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1. 81438	श्री राजेश कुमार सक्सेना, एफ० सी० ए०, पी० ओ० बोक्स 50584, लुसाका, जाम्बिया	1-4-87
2. 85571	श्री संजीव सूद, ए० सी० ए० ए-2/297, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	1-2-87

सं० नं० 3-एन० सी० ए० (8)/5/87-88—रेगूलेशन 10-(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतव्दारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्न 1 अगस्त 1986 से रद्द समझे जायेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1986-87 के लिए कार्य प्रमाण पत्न हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था:

क० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	2	3
1. 80	0079	श्री करन आनन्द, ए० सी० ए०,
		ई-160, मस्जिद मोठ
		नई दिल्ली-110048
2. 81	211	श्री कृष्णास्वामी श्रीनिवासन,
		ए० सी० ए०,
		9ए/51, डब्ल्यू० ई० ए०,
		करोक्ष बाग,
		नई दिल्ली-110005
3. 81	661	श्री निर्भया लोढ़ा,
		एफ० सी० ए०,
		785, मुकर्जी नगर,
		नियर बन्ना सिनेमा,
		नई विल्ली
4. 81	721	श्री राकेश कुमार, ए०सी०ए०,
		डी-23, होज खा स,
		नई दिल्ली
5. 81	825	श्री राज पाल गांधी,
		ए० सी० ए०,
		9/26, मोती नगर,

नई दिल्ली

जायेगी ।

3114	भारत का राजपत्र, सितम्बर 12, 198	
i 2	3	1 2 3
6. 82005	श्री संजीव कुमार सिंघल, ए० सी० ए०,	15. 84713 श्री हरष कुमार अरोड़ा, ए० सी० ए०, 10-आर, मॉडल टाऊन,
	4726, डिप्टी गंज, सपर बाजार,	अम्बाला सिटी
7. 82543	दिल्ली-110006 श्री चविजीत सिंह बावा,	16. 85161 श्री सुवेश कुमार, ए०सी० ए०,
7. 62343	ए० सी० ए०, 532, सैक्टर 8-बी	बी-19, 228, सिबिल स्ट्रीट, घुनार मंडी, सिबिल लाइन्स, लुधियाना 141001
8. 82654	चण्डीगढ़ 160008 श्री राजेश कुमार अरोड़ा,	नं 3-एन सी ए (8)/9/87-88रेगूलेशन 10
o. 02004	ए० सी० ए०, 44-ए, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015	(1) की घारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अघिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतव्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यो का कार्य करने का प्रमाण पन्न 1 अगस्त, 1981 से रह समझा
9. 82858	श्री राजेश बंसल, ए० सी० ए०, बी-364, बाबा बालक नाथ मन्दिर,	आएगा क्योंकि उसने वर्ष 1981–82 के लिए कार्य प्रमाण पक्ष हेतुवार्षिक शुरूक का भुगतान नहीं किया था। ————————————————————————————————————
	धुमर मंडी, लुधियाना	ऋ० सदस्यता नाम एवंपता संख्या संख्या
10. 82905	श्री सुनिल दत्त उप्पल, ए० सी० ए०, एफ-5, निजामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली-110013	1. 11759 श्री वोरशाल हान्डा, ए० सी०ए०, पी०ओ० बोक्स 9,
11. 83036	श्री राज कमल गोयल, ए० सी० ए०, 14ए/79, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली-110005	1, केजा (लागोस्र), नाइजिरिया ————————————————————— नं 28-आर०सी - (2)/25/87——चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट्
12. 83353	श्री मधु बेन्नालागंती, ए० सी० ए०, 74, डी०डी०ए० एम०आई० जी० फ्लैट्स,	रेगूलेशन 1964 के रेगूलेशन 136(1) के अनुसरण में वि काउंसिंग आफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया व 18 जुलाई, 1987 से क्यूइलोन में दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिष की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नसा है।
	प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005	यह शाखा दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की क्यूइलोन शाख मानी जायेगी।
13. 83438	श्री राकेश कुमार अरोड़ा, ए० सी० ए०, डीए/115ए, एल० आई० जी० फ्लैट्स, जी० बी० एरिया,	रेगूलेशन 136 (3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है य शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पाल करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे
	हरी नगर, नई विल्ली-110064	नं 28-आर सी (5)/7/87—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् रेगूलेशन 1964 के रेगूलेशन 136(2) के अनुसरण में
14. 83998	श्री भूपिन्दर सिंह, ए० सी० ए०, केयर ओफ़ अर्नस्ट एण्ड व्हीनी, पी० ओ० बोक्स 9267,	कार्जिसल आफ दि इंस्टीट्यूट अफ्र चार्टर्क एकाउन्टेन्ट्स आ इंडिया को 18 जुलाई, 1987 से जम्मू में उत्तर भारत क्षेत्री परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नर है।
	दुबई इन्ट.ः ट्रेड सैन्टर टर्न्ड (स्ट.स.)	्यह शाखा उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद की जम्मू शाखा मा

दुबई (यू० ए० ई०)

रेगूलेशन 136 (3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषव के माध्यम से पस्थिव के नियन्त्रण, पर्य-वेक्षण एवं निर्वेशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्वेशों का पालन करेगी जो कि परिषव द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे।

नं० 3-एन० सी० ए० (4)/1/87-88--- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधि-नियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सस्दयता रिजस्ट्र में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

ऋ ० संख्या	स द स्यता संख्या	नाम् एवं पताः	दिनांक
1,-	190	श्री किशन प्रसाद सोनी, मैसर्स सोनी, चत्ररथ एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्रस, 15, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	17-1-87
2.	2906	श्री मोहिन्बर पाल पुरी, 118, माल्चा मार्ग, नई दिल्ली	28-6-87
3.	81443	श्री अविन्द चौधरी, 47-सी/सी, गांधी नगर, जम्मू 180004	3-7-87
4.	82823	श्री नरेश कुमार सूद, 90, गोरफ लिक्स; (1फ्लोर), नई दिल्ली-110003	17-4-87
5.	85904	श्री विनोद कुमार अरोड़ा, जे-2, 112बी, डी०डी०ए० पर् कालकाजी, मई दिल्ली-110019	14-6-87 ट्स

नं 3-एन सी ए (5)/1/87-88— इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एन० सी० ए० (4)/9/85-86 दिनांक 31-3-86, 4-सी० ए०(1)/19/72-73 दिनांक 17-1-83, 3-एन० सी० ए० (4)/3/86-87 दिनांक 27-2-87, 3-सी० ए० (4)/15/82-83 दिनांक 30-3-83 और 4-सी० सी० ए० (7)/79-80 दिनांक 31-3-80, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विस्तिस्स 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतव्हारा यह सूचित किया जादा है कि उक्त

विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय बार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

ऋ सं ख् या	स द स्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	1709	श्री राम चरन दास, एफ.० सी० ए०, 6, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	1-5-87
2.	4053	श्री विद्या भूषण चढ़ा, ए०सी० ए०, ई/27ए, राजौरी मार्डन्स, नई विल्ली-110027	13-4-87
3.	17008	श्री देवेन्दर पाल कन्यर, ए० सी० ए०, ई-3/51, अरोड़ा कालोनी, भोपाल-462014	16-4-87
4.	15934	श्री शिव नारायन शर्मा, एफं॰ सी॰ ए॰, 502, कट्टा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006	8-5-87
5.	16411	श्री नरसिंह देव शारदा, एक० सी० ए०, सी-77, पुष्पांजली एन्कले <i>व</i> , नर् <u>क</u> ्षिल्ली	18-7-86
6.	70093	श्री वरिन्दर कुमार, ए० सी० ए०, मैसर्स इंडेको लि० पी० बोक्स 31935, लुसाका—जाम्बिया श्री वरिन्दर कुमार ए० सी० ए०, केयर श्रोफ श्री यस पाल वर्मा, गांधी गेट, दीना नगर 143531 (पंजाब)	1 4- 5- 87

3116	भारत का राजपत्र, वि	सतम्बर 12, 19	987 (भाद्रपंच 21, 1	909) [भाग 11]	—-खंण्ड ४
1 2	3	4	1 2	3	4
7. 80968	श्री राकेश कुमार गुप्ता, एफ०सी०ए०, एस०सी०ओ० 1116, सैक्टर 22बी, चण्डीगढ़ 160022	21-4-87	14. 83716	श्री क्रुष्टन कुमार गुप्ता, ए० सी० ए०, बी-4, लाजपत नगर 2, नई विरुली 110024	2- 6- 87
8. 81362	श्री मसोहर लाल, ए० सी० ए०, एस० सी० ओ०, 104-95, सैं ग्टर 22— थी, चण्डीगढ़-160022	4-5-87	15. 83759	श्री रोहित कपूर, ए० सी० ए०, 191, फ्लाइओवर मार्किट, डिफ़्रैन्स कालोनी, नई दिल्ली।	1-8-86
9. 82009	श्री राकेश कुमार मंगला, ए० सी०ए०, 8/11, साउथ पटेल नगर, नई विल्ली	18-5 87	16. 83760	श्री राहुल कपूर, ए०सी० ए०, 191, प्लाईग्रोवर मार्किट, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	1-8-86
0. 82874	श्री अरुन तुली, ए० सी०ए०, जे-37, (जी/एफ़), एन० डी० एस० ई० पार्ट 1, नई विल्ली-110049	16-6-87	17. 84224	श्री राजीव कुमार गुप्ता, ए० सी० ए०, ई-7/8, कुष्त नगर, दिल्ली-110051	1-5-87
11. 82877	श्री राजन सोनी, ए० सी० ए०, 18/3, शक्ति नगर, दिल्ली-110007	11-5-87		आर√ एल	० चोपड़ा, सचिव
	श्री राजन सोनी, ए० सी० ए०, 4710, अरबोर ड्राइब, अपीटी 203, रोलिंग मिडोज, आईएल 60008(यू०एस०ए०	·)		क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र कर्मेचारी राज्य बीमा निगम 100013,दिनांक 4 अगस्त 1987	
12. 82889	श्री अग्रवनी कुमार, ए० सी० ए०, बी-1/103, लाजपत नगर, नई विस्ली-110024	27-2-87	सूचित किया जाता 34-11(51) स गठित कर्मचारी	ही-34-11(51)—समन्वय एकक है कि इस कार्यालय की अधिसूचना ति प्र 3 दिनांक 10-12-8 राज्य बीमा सामान्य विनियम ा ार्थी निम्नलिखित सदस्यों के साथ	31—ध्ही— 0 के द्वारा 1950 की
3, 83621	श्री आलोकटंडन; ए०सी०ए०, मैसर्स्,आर०के० शर्मा	23-4-87	की तारीख से पुनर्ग		जायसू बना
	एण्ड एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स,		1. विनियम 10	-ए-1 (अ) के अनुसार	
	126, गोल्फ लिक्स,		सहायक श्रम		

नई दिल्ली-110003

1. विनियम 10-ए-1 (अ) के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त सोलापुर

सबस्य

विनियम 10-ए-1(व) के अनुनार

 वरिष्ठ प्रणासकीय अधिकारी चिकित्सा प्रणासन अधिकारी का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्रींद कैम्प, पुणे

विनियम 10-ए-1(क) के अनुसार

 वैधकीय बीमा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना दवाखाना, सोलापुर।

विनियम 10-ए-1 (ख) के अनुसार

- श्री अमिल भिमाशंकर बंडेवार, डायरेक्टर बाशीं तालुका उद्योग विकास को अा० सोसायटी लि०, बाशीं।
- श्री सुरेश भगवंतराय सुलावे, मैनेजिंग डायरेक्टर, वि लोकमान्य मिल्स बार्मी लि०, बार्मी, टाउन, बार्मी, जिला-सोलापुर, पिन कोड-413401

विनियम 10-ए-1(ग) के अनुसार

- 6. श्री कमलाद्यास मदमलाल लोहे जनरल सेकेटरी जनता मिल्स मजदूर यूनियन, बार्शी, द्वारा सस्कार होटेल, हस्य गली, सराफ कट्टा, बार्शी, जिला-सोलापुर।
- श्री श्रिकांत भगवान काणिद खिजनदार राष्ट्रीय गिरणी कामगारसंघ (इंटक) बार्णी, घरनं ० 2068, दाणे गली, बार्णी, जिला-सोलापुर

विनियम 10-ए-1(घ) के अनुसार

 प्रबन्धक स्थानीय कार्यालय, वार्गी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

> आदेशानुसार, बी०के० गुप्ता, क्षेत्रीय निदेशक

दिनांक 28 अगस्त 1987

शुद्धि-पत्न

भारत के राजपत्न दिनांक 16-5-87 के भाग-3 खण्ड-4 में पाई गई तृटियां

- हिन्दी के राजपल के पेज नं० 2447 पर शुरू के हैडिंग में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थान पर कर्मचार राज्य बीमा निगम लिखा है।
- 2. हिन्दी के राजपन्न के पेज नं० 2448 पर स्थानीय समिति बहादुरगढ़ के श्री एन० डी० शर्मा के स्थान पर श्री डी० एन० शर्मा छापा जाए।

आदेशानुसार आर० एस० रावत, क्षे<mark>त्रीय निदेशक</mark>

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई विल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 1987

सूचनाएं

सं० 25-16/86-एल० आई०--विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पा-लिसियों के बारे में लेने-देन न करें:---

 क्रम सं०	पालिसी नं० व दि	नांक बीमाकर्ताकानाम	राणि (रुपए में)
1. :	231296-पी	श्री सुनका राम	2,000/-
2.	564046-सी 6-3	-1985 श्रीओम प्रकाश	5,000/-

सं० 25-7/87-एल० आई०---विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को, बीमाकर्ताओं के नाम दहरी पालिसियों जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

सर्वं साबारण को चेतावभी की जाती है कि वे मूल पालिसियों के ब बारे में लेन-धेन न करें।

क्र ं ० सं०	पा लि सी सं० श्री र दिनांक	बीमाक्षतिश्री का नाम	राशि (रु० में)
1.	331850-सी वि॰	श्री बाई गनपतिराव	
	18-12-80		10,000/-
2.	456-125-सी दि०21-1- 83	श्री करणा माथुर (एफ)	20,000/-
3.	184372-पी दि० 8-7-71	श्री वी० अंजमप्पा	1,000/-

सं • 25-31/87-एल० आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतवृद्धारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेताबनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेम-देन न करें।

ऋ० पालिसी सं० ग्रौर सं० दिनॉक	बीमाकर्ताध्रों का नाम	राणि (रु० में)
1. 524336-पी वि० 19-10-83	श्री बी० के० विश्वास	10,00 0/-
2. 426743-सी वि० 8-7-82	श्री हाली राम शर्मा	10,000/-

विनांक 28 अगस्त 1987

सं॰ 25-10/87-एलआई--नीचे जिन बीमा पालिसियों का क्यीरा विया गया है वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतव्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक विया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत

किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है।

ऋ ध सं०	पालिसी सं० एवं तारीख		राशि (रुपए)
1.	49257-एनएम 15-6-81		B,000/-
2.	ए 7976 1-4-77	श्री बद्री नाथ	2,000/-

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1987

सं० रा० स० वि० नि०: 1-4/83-प्रशा०--राष्ट्रीय सह-कारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास मिगमे अधिनियम 1962 (1962 की सं० 26) की धारा 23 (I) ब्रॉरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतव्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियम, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:--

- 1 (1) ये विनियम रा० स० वि० नि० सेवा (दूसरा संशोधन) विनियम, 1987 कहलाएंगे।
 - (2) ये विनियम भारत के राजपत्न में उनके प्रकाशंम की तारीख से लागू होंगे ।
- II बिनियम 32 (3) में, "रु० 2,000/-" तथा "रु० 1,000/-" संक्षिप्त रूप तथा आंकड़ों के स्थान पर क्रमशः "रु० 5,000/-" तथा "रु० 2,500/-" संक्षिप्त रूप तथा आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाए।

रवि बीर गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1987

सं० अधिसूचना सं० 10/87—अवर सचिव, भारत सरकार से उनके पत्न संख्या एक 2(6)87-आई०एफ० 1 दिनांक 23 अप्रैल, 1987 द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 से प्राप्त निदेश के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43(1) के अधीन बनाए गए भा०औ०वि०नि० कर्मचारिवृन्द विनियम, 1974, 27 अक्तूबर, 1986 तक यथा संशोधित, शासकीय राजपत्न में एतबुद्वारा प्रकाणित किए जाते हैं।

एम**० एल० क**पूर, सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन व कार्मिक)

भारत/य श्रीद्योगिक वित्तनिगम

प्रौद्योगिक जिल्ला निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के अधीन नियमित]

भारतीय **प्रौद्योगिक वित्त** निगम कर्मेणारिवृन्दे विनियम, 1974

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनु-मोदन से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड द्वारा निर्मित।

भारतीय श्रीद्योगिक वित्त निगम,

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 43 की उप-धारा 2 के खण्ड (ट) के साथ पठित धारा 43(1) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का संचालक बोर्ड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से, एतद् द्वारा निगम के कर्मचारिवृन्द के कर्त्तव्यों तथा आचरण, वेतन, भसों एवं सेवा गतौं के नियन्त्वण के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय-1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त गाँषी हितथा श्रारम्भ :

2-239 GI/87

- (1) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारिबन्द) विनियम, 1974 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम पहली अप्रैल, 1974 से लागू होंगे। 2. प्रयोज्यता:
- (1) उप-विनियम (2) के उपबन्धों के अधीन, ये विनियम निगम के उस प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर लागू होंगे:--
 - (क) जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को निगम की सेवा में था, अथवा

- (ख) जो इन विनियमों के लागू होने की तारीख या उसके बाद से निगम की सेवा में है अथवा नियुक्त किया गया या लिया गया है।
- (2) ये विनियम निम्नलिखित पर, तब तक अन्यथा लागू नही होंगे जब तक कि इन विनियमों द्वारा या उनके अनुसरण में ऐसा प्रावधान न किया जाए अथवा बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अथवा सामान्यतः इस प्रकार विहित न किया जाए :—
 - (क) अंशकालिक आधार अथवा विशेष संविदाओं के अधीन नियुक्त कर्मचारिवृन्द,
 - (ख) शिक्षु, सामयिक कर्मचारी, वैनिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी तथा कार्य-मजदूर,
 - (ग) वे कर्मचारी जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य निकाय से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं एवं उनके परिदाता प्राधिकारियों के साथ करार में उनके (कर्मचारियों) लिए विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसा भी मामला हो, तथा*
 - (घ) निगम का अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति औ० खि॰ नि॰ अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (क) की शर्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है तथा जिसका वेतन तथा भत्ते उसकी नियुक्ति की शर्तों में निर्धारित सीमा, यदि कोई हो, के सिवाय औ० वि० नि० अधिनियम, 1948 की धारा 10 क(1) की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
- (3) इन विनियमों में से कोई भी विनियम, नियम द्वारा अपने किसी कर्मचारी/कर्मचारियों के साथ किए गए किसी विशेष करार पर अभिभावी नहीं होगा।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो—

- (क) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है विनियम 66 में उल्लिखित उपर्युक्त प्राधिकारी,
- (ख) ''बोर्ड'' में अभिप्रेत है निगम का संचालक बोर्ड,
- (ग) "कैलेन्डर मास" से अभिप्रेत है, किसी भी वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक कोई भी सम्पूर्ण मास,
- (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है निगम के संचालक बोर्ड या अध्यक्ष और उसमें उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार, किसी भी कारण से उसकी अस्थायी अनुपस्थिति की अवधि में

- (इसमें उसके पद की स्थायी रिक्ति सम्मिलित नहीं है) उसके (अध्यक्ष के) स्थान पर वाम करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 13क की शर्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके नियक्त करें।
- (ङ) जब तक कि इन विनियमों में विशेष रूप से अन्यथा उल्लिखित न किया जाए प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त अधिकारियों के लिए "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं अध्यक्ष तथा अन्य कर्मकारियों के लिए "महा प्रबन्धक" तथा इस प्रकार का निगम का कोई अन्य अधिकारी अथवा अधिकारीगण जिन्हें मामलों का निपटान करने हेतु बोर्ड ने प्राधिकार प्रदान किया हो अथवा इन प्रयोजनों हेतु अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किया हो.
- (च) ''निगम'' से अभिप्रेत है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
 - (छ) "ड्यूटी" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
 - (i) परिवीक्षाधीन कर्मचारी के रूप में सेवा, बणतें कि ऐसी परिवीक्षाधीन सेवा की भविष्य में पुष्टि की जाए;
 - (ii) बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति की अविध में की गई ड्यूटी;
 - (iii) कर्मचारी की कार्य-ग्रहण अवधि;
 - (iv) अववाश प्रवान करने में सक्षम प्राधिवारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आकस्मिक छुट्टी पर विताई गई अविधि;
 - (v) अध्यक्ष द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के अधीन किसी प्राधिकरण अथवा संगठन के अधीन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बिताई गई अविध;
 - (vi) अध्यक्ष द्वारा "ड्यूटी" के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत की गई कोई भी अन्य अवधि;
- (ज) "परिवार" से अभिप्रेत है कर्मचारी की पत्नी/पति और साधारणतः कर्मचारी के साथ रहने वाले तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित बचे,
- (झ) "बाह्य सेवा" से अभिप्रेत हैं वह सेवा जिसमें कर्मचारी अपना वेतन एवं भत्ते निगम की मंजूरी से, निगम से भिन्न अन्य किसी स्रोत से प्राप्त करता है,

- (ङा) "महा प्रबन्धक" से अभिप्रेत है निगम के "महा-प्रबन्धक" के पद पर तत्समय नियुक्त अधिकारी तथा उसके द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में, उप महा प्रबन्धक, सहायक महा-प्रबन्धक तथा मुख्य लेखापाल भी सम्मिलित हैं।
- (ट) "पुनर्ग्रहणाधिकार" से कर्मचारी के उस स्थायी पद को मूल रूप से, जिस पर उसे मूल रूप से अर्थात् स्थायी रिक्ति में नियुक्त किया गया है, ग्रहण करने का अधिकार अभिप्रेत हैं जिसे वह तत्काल या अनुपस्थिति की अविध/अविधियों की समाप्ति के पश्चात् मूल रूप से ग्रहण करने का हकदार है।
- (ठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में "प्रबन्धक" से अभि-प्रेत हैं:—
 - (i) प्रधान कार्यालय के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/प्रभागों के प्रभारी अधिकारी तथा तत्समय उक्त अधिकारियों की ड्यूटी का निष्पादन करने वाले अधिकारी।
 - (ii) किसी अन्य कार्यालय अथवा शाखा के के सम्बन्ध में, उस कार्यालय अथवा शाखा का प्रभारी अधिकारी।
- (इ) "मास" से अभिप्रेत है अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार गिना जाने वाला मास और इसका गणन कैलेन्डर मास की एक विशेष तारीख से आगामी कैलेन्डर मास की उसी तारीख से पहली तारीख तक उसके सहित किया जायेगा अथवा यवि इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होगी तो इसका गणन आगामी कैलेन्डर मास के अन्तिम विन तक और उसके सहित किया जायेगा,
- (ढ) "स्थानापन्न" से अभिप्रेत है ऐसे पद पर कार्य करना जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का "पुन-ग्रेंहणाधिकार" है अथवा ऐसे अस्थायी पद पर कार्य करना जिस पर स्थायी कर्मचारी नियुक्त है।

परन्तु, नियुक्ति 'प्राधिकारी, यदि उचित समझे तो, किसी कर्मचारी को ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है जिस पर किसी अन्य अधिकारी का पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है।

- (ण) "वेतन" से अभिप्रेत हैं, कर्मचारी को प्राप्त होने वाली मासिक राशि, जैसे---
 - (i) किसी पद पर स्थानापन्न या मूल रूप से कार्य करने के लिए संस्वीकृत या वह वेतन जिसका वह किसी संवर्ग में भ्रपनी स्थिति के कारण अधिकारी है;

- (ii) विशेष वेतन तथा वैयक्तिक वेतन, और
- (iii) कोई अन्य परिलब्धियां, जिन्हें बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए;
- (त) "परिवीक्षाधीन कर्मचारी" से अभिप्रेत है वह कर्म-चारी जो परिवीक्षा पर नियुक्त है अथवा ऐसा कर्मचारी जो निगम में मूल रिक्ति पर नियुक्त है,
- (थ) ''वैयक्तिक वेतन'' से कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला निम्नलिखित अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है—
 - (i) वेतन में संशोधन या अनुशासनिक कार्य-वाही से भिन्न किसी भी कारण से मूल वेतन में किसी प्रकार की कटौती के कारण किसी स्थायी पद्य के सम्बन्ध में मूल वेतन में होने वाली हानि से बचाने के लिए हां, अथवा
 - (ii) अन्य वैयक्तिक कारण से विशेष परिस्थि-तियों में,
- (थ) ''जन-सेवक'' से अभिप्रेत है और इसमें, समय-समय पर यथा संशोधित दण्ड संहिता की धारा 21 में यथा उल्लिखित व्यक्ति शामिल है।
- (द) "सेवा" में वह अविध सम्मिलित है जिसमें कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तथा विधिवत प्राधिकृत छुट्टी पर हो, परन्तु इसमें ऐसी कोई
 भी अविध सम्मिलित नहीं है जिसमें कोई कर्मचारी बिना अनुमित के कार्य में अनुपस्थित रहता
 है अथवा अपनी छुट्टी से अधिक समय तक
 छुट्टी पर रहता है, जब तक कि छुट्टी प्रदान
 करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुपस्थिति
 की विशेष रूप से अनुमित प्रदान न कर दी गई
 हो.
- (ध) "विशेष वेतन" से अभिप्रेत है निम्नलिखित परि-स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पद या कर्मचारी की उपलब्धियों में वृद्धि—
 - (i) विशोष रूप से श्रम साध्य प्रकृति के कार्य, अथवा
 - (ii) कार्य अथवा चायित्व में विशेष वृद्धि।
 - (iii) "मूल वेतन" से अभिप्रेत है वह वेतन जिसके लिये कर्मचारी, जिस पद पर वह मूल रूप से नियुक्त है उसके अथवा संवर्ग में उसकी मूल स्थिति के कारण उसका हकदार है।
- (त) "अस्थायी पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसके लिए सीमित अवधि के लिए एक निश्चित वेतन दर मंजूर की गई है, ऐसे पद पर कार्यरत व्यक्ति को अस्थायी कर्मचारी कहा जायेगा।

4. विनियमों में परिवर्तन

बोर्ड भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व अनुमित से, औद्योगिक विक्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43(1) में निहित विधि से समय-समय पर इन विनियमों में संशोधन कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी नवीन विनियम अथवा वर्तमान विनियमों में किया जाने वाला परिवर्तन किसी कर्मचारी के उस वेतनमान को घटा नहीं सकेगा जिस पर वह नवीन विनियम अथवा परिवर्तन के लागू होने के दिन से मूल हैसियत में वेतन लेने का हकदार है।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

इन विनियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए औद्योगिक बित्त निगम अधिनियम, 1948, की धारा 40 (क) के अन्तर्गत, बोर्ड सामान्य अथवा विगेष आदेश द्वारा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबधक अथवा सहायक महा-प्रबन्धक अथवा मुख्य लेखापाल अथवा निगम के किसी अन्य अधिकारी/अधिकारियों को आदेश में यथा विनिर्दिष्ट मतौं तथा सीमाओं के अधीन ऐसे अधिकार सौंप सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

6. विनियमों के निर्वचन तथा कार्यान्वित करने की शक्ति

विनियमों के निर्वचन का अधिकार अध्यक्ष को होगा,
जिसे एतद्द्वारा इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने
तथा उनके उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु अथवा कर्मचारियों
पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए समय-समय पर यथावश्यक
प्रशासकीय अनुदेश जारी करने का भी अधिकार दिया जाता
है।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के अन्तर्गत किया गया कोई निर्वचन अथवा जारी किया गया कोई अनुदेश विनियम 4 के अर्थ में इन विनियमों का परिवर्तन नहीं समझा जायेगा।

अध्याय 11

नियुक्तियां, परिवोक्षा, पुनर्ग्रहणाधिकार श्रीर सेवा-समाप्ति खण्ड-I—नियुक्तियां

7. कर्मचारियों का वर्गीकरण

(1) निगम के जिन कर्मचारियों पर ये विनियम लागू होंगे उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा:---

 श्रेणी I
 विर्ध्ठ अधिकारी

 श्रेनी II
 किनिष्ठ अधिकारी

 श्रेनी III
 लिपिकीय कर्मचारी वग

 श्रेणी IV
 अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग

(2) संचालक बोर्ड प्रत्येक पद अथवा पदों के वर्ग के लिए समय-समय पर, वेतन निर्धारित करेगा तथा अध्यक्ष प्रत्येक समूह के पदों की संख्या निर्धारित करेगा।

- (3) इस विनियम की किसी भी बात वा यह अर्थ महीं माना जायेगा कि अध्यक्ष की बोर्ड की पूर्व अनुमित के बिना ऐसा पद निर्मित करने के लिए प्राधिकृत किया नया है जिसका प्रारम्भिक वेतन 1,000 रुपये मासिक से अधिक है।
- 8. नियुक्तियां करन के लिए शक्ति प्राप्त प्राधिकारीं निगम की सेवा में निम्नलिखित रूप से नियुक्तियां की जा सकती हैं:—
 - (क) श्रेणी I के पदों की नियुक्तियां श्रध्यक्ष द्वारा की जा सकती हैं परन्तु, वरिष्ठ श्रधिकारें संवर्ग के पदों की सभी नियुक्तियों के लिए बोर्ड की कार्यो- सार मंजूरी श्रावश्यक होगी।
 - (ख) समय-समय पर बोर्ड एवं/अथवा अध्यक्ष द्वारा जारी सामान्य प्रथवा विशेष निदेशों के श्रधीन श्रेणी II के पदों की नियुक्तियां महाप्रबन्धक द्वारा,
 - (ग) समय-समय पर भ्रध्यक्ष भ्रथवा महाप्रबन्धक द्वारा जारी सामान्य भ्रथवा विशेष निदेशों के भ्रधीन, प्रधान कार्यालय के श्रेणी III एवं IV के पदों की नियुक्तियां, प्रधान कार्यालय में प्रशासन विभाग के प्रधान द्वारा तथा साखा कार्यालय के कर्मचारियों तथा उनके क्षेत्राधिकार के भ्रधीन उप कार्यालयों की श्रेणी III के कर्मचारियों की नियुक्तियां, शाखा कार्यालय के प्रभारी श्रधिकारी द्वारा तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां उप-कार्यालय के प्रभारी श्रधिकारी द्वारा।

संशोधन पश्चात विनियम

- 9. **श्रस्था**यी या श्रंश-कालिक श्राधार पर श्रेणी-¹¹¹ ग्रीर IV पदों पर परिवीक्षा पर नियुक्तियां
 - (1) स्थायी प्रकृति की रिक्तियों श्रौर पदों के मामले में श्रेणी-III ग्रौर IV पदों पर निगम की सेवा में नियुक्तियां परिकीक्षा पर की जाएंगी।
 - (2) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी और उप-विनियम (1) तथा इस सम्बन्ध में दिए गए सामान्य श्रथवा विशेष निदेशों के श्रधीन, श्रध्यक्ष द्वारा विहित शर्तों के श्राधार पर श्रेणी- 111 और 1V में श्रस्थायी रिक्तियों पर श्रस्थायी ग्रंश-कालिक श्राधार पर नियुक्तियां कर सकता है। परन्तु किसी भी दशा में ये शर्तें, समान हैसियत श्रथवा दायित्व वाली स्थायी नियुक्ति के लिए इन विनियमों में निर्धारित शर्तों से श्रधिक श्रनुकूल नहीं होंगी।

10. नियुक्तियां

निगम में विभिन्न पदों-ग्रिधकारी तथा भ्रन्य—की सीधी भर्ती बोर्ड द्वारा बनाए गए निश्चित नियमों/प्रिकिया के भ्रनुसार की जायेगी।

11. स्वास्थ्य प्रमाण-पत्न

कोई भी व्यक्ति निगम की सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निगम को स्वीकार्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा शारीरिक गठन से स्वस्थ एवं चिकित्सीय दिष्ट से योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता। निगम द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों के श्रनुसार स्वा-स्थ्य परीक्षा हेतु देय शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

12. चिरत एवं पूर्वयृत का सत्यापन

- (1) सभी ग्रधिकारी पदों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में, कोई भी व्यक्ति निगम की सेवा में तब तक प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि निगम सत्यापन द्वारा उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त को संतोषजनक न पाये।
- (2) निगम की सेवा में श्रन्य प्रत्यक्ष नियुक्तियों के सम्बन्ध में, इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक ब्यक्ति को अपनी नियुक्ति के समय, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से श्रच्छे नैतिक चरिन्न का प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करना होगा जो सब-डिवजनल मिजिस्ट्रेट श्रथवा उससे उच्च श्रधिकारी श्रथवा किसी राजपन्नित श्रधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो:

बशर्ते कि:---

- (क) जहां कोई व्यक्ति प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने में ग्रममर्थ हो, श्रथवा
- (ख) जहां किसी भ्रन्य कारण, जैसे सुरक्षा पहलू, की दृष्टि से चरित्र एवं पूर्ववृत्त का निरीक्षण श्राब-श्यक समझा जाए, तो विस्तृत सत्यापन किया जा सकता है।

13. आयु

निगम की सेवा में सर्वप्रथम प्रवेश के समय श्रेणी I और 1I के पदों की नियुक्तियों के लिए व्यक्ति की श्रायु 2 वर्ष से कम तथा श्रन्य नियुक्तियों के लिए 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

14. ग्रेड के न्यूनतम वेतन पर नियुक्तियां की जाएं

सभी पहली नियुक्तियां, नियुक्ति के ग्रेड के न्यूनतम वेतन पर की जायगी।

परन्तु, ग्रध्यक्ष, नियुक्ति के ग्रेड के लिए निर्धारित वेतनमान में अधिक से श्रधिक चार प्रारम्भिक वेतनवृद्धियां प्राधिकृत कर सकता है। यदि प्रत्याशी——

- (क) भ्रच्छी ग्रैक्षाणिक भ्रथवा तकनीकी भ्रथवा व्याव-सायिक योग्यताएं रखता हो, भ्रथवा
- (ख) उस नियुक्ति से पूर्व निगम की श्रस्थायी सेवा में रहा हो, श्रथवा
- (ग) ितगम के लिए महत्वपूर्ण विशेष श्रनुभव रखता हो।

परन्तु यह भ्रौर कि विशेष मामलों में, श्रध्यक्ष के श्रनु-मोदन पर, बोर्ड चार से श्रधिक, वेतनवृद्धियां प्रदान कर सकता है।

15. निगम को सेवा में पुनरियुक्ति

- (1) कोई भी ऐता व्यक्ति जिसे स्वास्थ्य-प्राधार प्रथवा छंटनी के प्रतिरिक्त िगम की सेवा में बरखास्त किया गया हो प्रथवा जो निगम की सेवा में न रहा हो, श्रेणी 1 के पदों पर नियुक्ति के लिए बोर्ड ग्रीर श्रन्य मामलों में प्रध्यक्ष द्वारा विहित गर्ती के ग्रधीन उनकी विशिष्ट मंजूरी के बिना, पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- (2) जब तक कि बोर्ड भ्रथवा भ्रध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, उप विकियम (2) के श्रन्तर्गत व्यवस्था न की गई हो ये विकियम निगम की सेवा में पुनित्युक्त किए जाने वाले व्यक्ति पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह श्रपनी पुनित्युक्ति की तारीख को पहली बार सेवा में श्राया हो।

16. सेवा प्रारम्भ

जब तक कि इन विनियमों द्वारा या इन विनियमों के प्रधीन प्रन्यथा व्यवस्था न की गई हो, किसी कर्मचारी की "सेवा" उस कार्य-दिवस से प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जब वह इन विनियमों के प्रधीन नियुक्ति पर कार्य के लिए निगम द्वारा उसे सूचित किए गए स्थान पर रिपोर्ट करेगा, परन्तु यदि वह ध्रपराह्म में कार्य पर ग्राने की सूचना देता है तो उसकी सेवा श्रागामी कार्य-दिवस से प्रारम्भ मानी जायेगी।

17. मूल नियुक्तियों का प्रावधान

- (1) जब तक कि इन विनियमों में ग्रन्थथा व्यवस्था न की गई हो एक ही समय में, एक स्थायी पद पर दो ग्रथवा ग्रधिक कर्मचारी स्थाधी रूप से नियुक्त नहीं किए जा सकते।
- (2) ग्रस्थायी ध्यवस्था के ग्रतिरिक्त एक ही समय में किसी एक कर्मचारी को दो ग्रथवा ग्रधिक स्थायी पदों पर मूल रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- (3) किसी कर्मचारी को किसी ऐसे पद पर मूल रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी ग्रन्थ कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार हो।

खण्ड-I ---परिवीक्षा

18. श्रेणी I श्रीर JI के कर्मचारी

निगम की सेवा में सीधे भर्ती होने वाले श्रेणी I एवं II के कर्मचारी को, उसकी नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई श्रवधि के लिए परिवीक्षा-धीन रहना होगा। यह परिवीक्षा अवधि कम से कम एक वर्ष तथा श्रिकिक से श्रिकिक दो वर्ष होगी :—

(i) परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी स्वेष्ठा में विशेष मामलों में, निगम की सेवा में सीधे भर्ती किये गए किसी भी कर्मचारी की परिवीक्षा ग्रविध समाप्त कर सकता है।

(ii) परन्तु जब कोई कर्मचारी श्रेणी I एवं II के पद पर पदोन ति श्रथवा स्थायी रिक्ति में प्रवरण द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उस पद पर वह तब तक स्थानापन्न हैसियत से माना जायेगा जब तक कि उस पद पर उसकी पुष्टि नहीं का दी जाती तथा जब तक कि श्रन्यथा विशेष रूप से विहित नहीं किया जाता, वह स्थायी नहीं होगा, और परिवीक्षाधीन माना जायेगा।

19. ग्रन्य कर्मचारी

स्थायी रिक्तियों पर सीधे भर्ती किए गए श्रेणी-I तथा II कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को एक वर्ष प्रथवा निगम के स्व-विवेक से यथानिर्धारित प्रविध तक परिबीक्षा-धीन रहना होगा।

20 परिवीक्षा की श्रवधि बढाने की शक्ति

बिनियम 18 श्रौर 19 में किसी बात के होते हुए भी सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी स्व-विवेक से किसी कर्मचारी की परिवीक्षा श्रवधि बढ़ा सकता है, परन्तु किसी भी दशा में, यह श्रवधि तीन वर्ष से श्रधिक नहीं होगी।

21 परिवीक्षा के बदले में श्रस्थायी सेवा

यदि किसी कर्मचारी ने, निगम की सेवा में श्रपनी पुष्टि होने से पूर्व, निरन्तर अस्थायी सेवा की हो तो नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेक से परिवीक्षा पर व्यतीत श्रविध से सम्बन्धित प्रावधान ऐसी श्रस्थायी सेवा की श्रविध की सीमा तक समाप्त कर सकता है।

खण्ड-III पुनर्ग्रहणाधिकार

22. पुनर्ग्रहणाधिकार

जब तक कि किसी मामले में श्रन्यथा विहित न किया गया हो, किसी स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त कर्म-चारी उस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार ग्रहण करता है तथा किसी श्रन्य पद पर धर्जित उसका पूर्व पुनर्ग्रहणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

23 पुनर्ग्रहणाधिकार कब रखा जाता है

जब तक कि विनियम 24 के श्रन्तगंत किसी कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार निलम्बित नहीं कर दिया जाता, तब तक मूल रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारी का उस पद पर निम्नलिखित स्थितियों में पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता है:—

- (क) उस पद के कार्यों का निष्पादन करते समय,
- (ख) बाह्य सेवा में अथवा श्रस्थायी पद श्रथवा किसी श्रन्य पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति के समय
- (ग) किसी भ्रन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्य-ग्रहण भ्रवधि के समय, परन्तु, यदि बह मुख

रूप से किसी निम्न पद श्रथवा निम्न वेतन श्रथवा ग्रेड पर स्थानान्तरित किया जाता है तो नये पद पर उसका पुनग्रंहणाधिकार उससे श्रगले दिन से स्थानान्तिरित कर दिया जायेगा जिस दिन वह स्थानान्तरित किए गए पद के कर्लंक्यों से कार्य मुक्त कर दिया जाता है।

- (घ) छट्टी के समय श्रौर
- (ङ) विनियम 64 के श्रन्तर्गत निलम्बन की भविध के समय।

24. पुनर्ग्रहणाधिकार का निलम्बन

- (1) मूल रूप से किसी स्थायी पद पर किसी कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में निलम्बित किया जायेगा:---
 - (क) यदि उसे मूल रूप से किसी श्रन्य स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है,
 - (ख) यदि उसे किसी ऐसे पद पर श्रस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है, जिस पर किसी श्रन्य कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार हो एवं उसका वह पुनर्ग्रहणाधिकार इस विनियम के श्रन्तर्गत निलम्बित न किया गया हो,
 - (ग) यदि उसे मूल प्रथवा स्थानापन्न हैसियत से किसी भ्रन्य पद पर बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त भ्रथवा स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा जब यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो कि जिस पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है वह उससे न्यूनतम तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए भ्रमुपस्थित रहेगा।
 - (घ) यदि इस बात के मानने के पर्याप्त कारण है कि कर्मचारी बीमारी श्रथवा भ्रन्य किसी विशेष परिस्थितियों के कारण भ्रपने उस पद से भ्रनु-पस्थित रहेगा जिस पर कि उसका तीन वर्ष से कम की भ्रवधि का पुनर्ग्रहणाधिकार है।
- (2) इस विनियम के श्रन्तर्गत किसी कर्मचारी का निर्लाम्बत किया गया पुनर्ग्रहणाधिकार, बहाल कर दिया जायेगा यदि किसी स्थायी पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है श्रथवा यदि जिन परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत उसका पुनर्ग्रहणाधिकार निलम्बित किया गया था वे सभाप्त हो जाती हैं।
- (3) यदि इस विनियम के ग्रन्तगंत, किसी पद के लिए किसी कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार निलम्बित कर दिया गया है, तो वह पद मूल रूप से भरा जा सकता है तथा उस पद पर मूल रूप से नियुक्त कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार हो जायेगा परन्तु निलम्बित पुनर्ग्रहणाधिकार के बहात होते ही ग्रव्यवस्था प्रतिवर्तित हो जायेगी।

25. लम्बे समय तक कार्य से श्रनुपस्थित रहने तथा सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान पुनर्ग्रहणाधिकार रह करना।

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी कर्मचारी का पुनर्प्रणाधिकार उसे 14 दिन का नोटिस देने के बाद रह कर दिया जायेगा, यदि वह इन विनियमों के भ्रधीन उसे देय सारी छुट्टी समाप्त हो जाने के बाद डयूटी से अनुपस्थित रहे तथा सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान, ऐसी छुट्टी पर जाने के तत्काल पूर्व या उससे पहले किसी भी समय उसके द्वारा धारित किसी पद पर उसका कोई पुनर्प्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

खण्ड-IV सेवा समाप्ति

26· परिवीक्षा के दौरान सेवा-मुक्ति

परिवीक्षा अविधि के दौरान किसी भी कर्मचारी की एक महीने के नोटिस प्रथवा उसके बदले में एक महीने का मूल वेतन देकर सेवा-मुक्त किया जा सकता है। कर्मचारी भी इसी प्रकार का नोटिस देकर प्रथवा उसके बदले में एक मास का मूल वेतन देकर, जैसी भी स्थिति हो, निगम की सेवा से त्यागपन्न दे सकता है।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों के मामलों में इस विनियम में से कुछ भी लागू नहीं होगा जो मूल पद धारण करते समय परिवीक्षा पर उस पद पर नियुक्त किए जाते हैं प्रथवा उच्च ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य करते हैं, जिसे इस प्रकार की नियुक्ति के दौरान सन्तोषजनक प्रगति करने में ग्रसमर्थ पाए जाने पर ने टिस श्रथवा उसके बदले में मूल वेतन के बिना ही उसके मूल ग्रेड पर पदावनत कर दिया जायेगा।

27. नोटिस द्वारा सेवा-समाप्ति ,

- (1) कोई भी कर्मचारी, सर्वप्रथम सक्षम प्राधिक.... सेवा छोड़ने प्रथवा समाप्त करने से सम्बन्धित अपनी इच्छा का लिखित नोटिस विए बिना, निगम में अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा प्रथवा समाप्त करेगा । श्रेणी I तथा II के कर्मचारियों के लिए नोटिस की अवधि तीन मास तथा ध्रन्य सामलों में एक मास होगी बिद कोई कर्मचारी इस उप-विनियम के प्रावधानों को भंग करता है तो वह अपेक्षित नोटिस की अवधि के लिए मूल वेतन की राशि, मुम्रावजे के रूप में निगम को देने के लिए उत्तरवायी होगा। सक्षम प्राधिकारी को, उस मामले में जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो या चल रही ही, ग्रथवा, बकाया हो, त्यागपत्र स्वीकार करने से इन्कार करने का अधिकार होगा, जिसके कारण कर्मचारी को लिखित में बंचित किए जाने होंगे।
- (2) उप-विनियमं (1) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा दिया गया नोटिस---
 - (क) तभी मान्य होगा ग्रथवा उचित समझा जायेगा यदि नोटिस की अविधि में कर्मचारी निगम की

सेवा में कार्यरत रहे श्रथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रधिकृत छुट्टी पर हो,

(ख) एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र वापिस नहीं लिया जा सकता

परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से उप-विनियम (1) तथा (2) में पीछे दिये गए सभी प्रथवा किसी भी प्रावधान में पूर्णंतः प्रथवा ग्रांशिक रूप में ढील दी जा सकती हैं ग्रथधा उसे समाप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी: 1. किसी पद विशेष पर नियुक्तियां करने में सक्षम प्राधिकारी ही, किसी कर्मचारी का उस पद से त्यागपत्र स्वीकार करने में सक्षम प्राधिकारी है।

टिप्पणी : 2. त्यागपन्न तभी प्रभावी हो सकता है जबिक वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वी-कार किया जाए तथा कर्मचारी को उसके कर्त्तव्य से भारमुक्त कर दिया जाए। त्यागपन्न स्वीकार करने समय, सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करेगा कि त्यागपन्न को तत्काल प्रथवा किसी ग्रागामी तारीख से प्रभावी बनाया जाए। यदि त्यागपन्न को ग्रागामी तारीख से प्रभावी बनाया जाए तो उसके लागू होने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 3. त्यागपत्न के प्रभावी हो जाने पर निगम में कर्म चारी की सेवा समाप्त हो जायेगी। । उस स्थिति में, यदि त्यागपत्न वापस लेने से सम्बन्धित कोई भी निवेदन स्वीकृत हो जाता है तो सेवा भंग की श्रवधि को क्षमा करने के उपरान्ते, उसे सेवा में पुनर्नियुक्ति माना जायेगा। चूंकि, इसमें श्राधिक वचनबद्धता है श्रतः पहले ही प्रभावी हो चुके त्यागपत्न को वापस लेने सम्बधी निवेदन की स्वीकार करने से पूर्व श्रेणी I के कर्मचारियों के मामले में बोर्ड तथा श्रन्य मामलों में श्रध्यक्ष की कार्योत्तर मंजूरी लेनी श्रावश्यक होगी।

- (3) निगम की सेवा में कर्मचारी की पुष्टि के पश्चात निगम, श्रेणी I तथा II के कर्मचारियों को तीन मास का नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन तथा अन्य मामलों में एक मास का नोटिस अथवा एक मास का वेतन देकर कर्मचारी की मेवा समाप्त कर सकता है।
- (4) उप-विनियम (3) के ग्रन्तर्गत किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के ग्रिधिकार का प्रयोग, श्रेणी I के कर्मचारियों के मामलों में बोर्ड की पूर्वानुमित से ग्रध्यक्ष द्वारा तथा ग्रन्थ कर्मचारियों के मामलों में ग्रध्यक्ष द्वारा किया श्रामेगा ।

- 27(5) उप-विनियम (3) में निहित कोई भी बात नियुक्ति प्राधिकारी के निम्नलिखित श्रधिकार को प्रभावित नहीं करेगी—
 - (क) किसी कर्मचारी को विनियम 33 तथा 61 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक महीने का नोटिस भ्रथवा उसके बदले में एक महीने का वेतन देकर सेवा-निवृत्ति भ्रथवा बरखास्त करना।
 - (ख) निगम द्वारा श्रनुमोदित योग्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर्मचारी को निगम की श्रागामी निरन्तर सेवा करने में स्थायी रूप मे श्रसमर्थ प्रमाणित करने पर एक महीने का नोटिस देकर श्रथवा उसके बदले में एक महीने का वेतन देकर कर्मचारी की मेवा समाप्त करना।

स्पष्टीकरण 1-विनियम 26 के प्रावधानों के भ्रनसार, परि-विका अवधि के समाप्त होने पर श्रथवा परिवीक्षा श्रवधि में सेवा में पुष्ट न किये गये कर्मचारी की सेवा-मुक्ति, इस विनियम के अर्थ में नेवा-समाप्ति नहीं माना जायेगा।

ग्रध्याय--- 3

सेवा अभिलेख तथा सेवा की सामान्य अर्ते

78. सेवा अभिलेख

तिगम द्वारा श्रेणी I तथा II कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय में तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी के कार्यरत कार्यालय श्रथवा शाखा में सेवा अभिलेख रखा जायेगा। यह श्रभिलेख यथानिर्धारित प्रारूप में होगा श्रोर उनमें यथानिर्धारित सूचना निहित होगी।

29. पुष्टीकरण

- (1) नीचे दिए गए उप-विनियम (2) के उपबन्धों के अधीन, परिवीक्षा श्रवधि (बढ़ाई गई श्रवधि सहित, यदि कोई हो) के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर, परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की उस पद या संवर्ग में, जिससें उसकी नियुक्ति हुई है, ग्रपनी परिवीक्षा श्रवधि के समाप्त हो जाने की तारीख से सेवा में पुष्टि की जा सकती है।
- (2) यदि संवर्ग में कोई कर्मचारी पदोन्तत (पूर्णतः अस्थाई आधार से भिन्ते) होने पर स्थानापन्तं रूप से, उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित परिवीक्षाधीः कर्मचारी की उसी संवर्ग में उसी पद पर नियुक्ति की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से कार्य कर रहा हो तो निगम की सेवा में पुष्टि किए जाने के लिए परिवीक्षाधीन कर्मचारी की अपेक्षा स्थानपन्तं कर्मचारी के दावे को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (3) अस्थायी पद पर ियुक्त कर्मचारी की, स्थायी पद के उपलब्ध होने पर अन्य पहलुक्रों अर्थात्, चरित्न, श्राचरण और कार्य के पहलुक्रों की उपयुक्तता को देखकर पुष्टि कर दी जायेगी।

(4) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारिवृन्द की पुष्टि हेतु, कोई सामान्य भ्रथवा विगेष गत निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार संचालक बोर्ड के पास सुरक्षित है।

30. वरिष्ठता

किसी ग्रेड विशेष में कर्मचारी की वरिष्ठता, इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा श्रनुमोदित नियमों के श्रनुरूप निर्धारित की जायेगी।

36. पदोन्नति

सभी पदोन्तितयां बोर्ड द्वारा इस हेतु विनिर्मित नियमों के ग्राधार पर, निगम स्वविवेक से करेगा तथा किसी कर्मचारी का किसी भी पद या ग्रेड में पदोन्तित का श्रिधिकार नहीं होगा।

37. पदायनित

- (1) एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति पर श्रन्तरित होने पर, कर्मचारी इस प्रकार के श्रंतरण के एक वर्ष में बिना किसी नोटिस के श्रपने पूर्व पद पर पदावनत श्रथवा पुनः अन्तरित किया जा सकता है।
- (2) उस कर्मचारी की, जो उच्च ग्रेड ग्रथवा नियुक्ति पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त है ग्रथवा उच्च ग्रेड या नियुक्ति पर जिसकी पुष्टि निश्चित श्रविध तक परिवीक्षा पर रहने के श्राचीन है, इस प्रकार के स्थानापन्न ग्रथवा परिवीक्षा के ग्रन्तर्गत किसी भी समय बिना किसी नोटिस के पदावनत किया जा सकता है।
- (3) जब कोई कर्मचारी निगम के कर्मचारिवृन्द में से चयन द्वारा श्रेणी I के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा नियुक्ति प्राधिकारी के मत से वह मन्तोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है प्रथवा श्रयोग्य पाया गया हो तो उसे ऐसे पद की परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना नोटिस के, श्रपने पूर्व मूल ग्रेड पर पदावनत किया जा सकता है।
- (4) इस विनियम में से कुछ भी, विनियम 61 के उप-बन्धों को प्रभावित नहीं करेगा।

33. निवर्तन तथा सेवा-निवृत्ति

(1) श्रेणी IV के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन सेवा-िवृत्त होगा जिसमें वह 58 वर्ष की आयु पूरी करेगा, जबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन सेवा-िवृत्त होगा जिससें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा। फिर भी, िगम की सेवा में 30 वर्ष पूरे होने पर अथवा 50 वर्ष की आयु होने पर, जो भी पहले हो, अथवा उसके बाद कभी भी, यदि निगम ऐसा करता निगम के हित में आवश्यक समझे तो कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर निगम को किसी भी कर्मचारी को निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त करने का पूरा अधिकार है। 30 वर्ष की सेवा पूरी

करने पर ग्रयवा 55 वर्ष की भ्रायु प्राप्त करने पर किसी श्रेणी का कोई भी कर्मवारी सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के लिखित नोटिस द्वारा सेवानिवृत्त होने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

उसके बाद कभी भी, यवि निगम ऐना करना निगम के हित में आवश्यक समझे तो कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर निगम को किमी भी कर्मवारी को निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त करने का पूरा अधिकार है । 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अथवा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किसी श्रेणी का कोई भी कर्मवारी सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के लिखित नोटिम द्वारा सेवानिवृत्त होने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

(2) किसी कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रथवा 50 वर्ष की श्रायु प्राप्त करने पर ग्रथवा उसके बाद किसी भी समय, उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त सेवा- निवृत्त करने के श्रधिकार का प्रयोग ग्रध्यक्ष द्वारा किया जायेगा— श्रेणी I के श्रधिकारियों के मामले में बोर्ड की पूर्व श्रनुमित लेनी ग्रनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण I: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 21 वर्ष की श्रायु प्राप्त करने से पूर्व कर्मचारी द्वारा की गई कोई भी सेवा श्रवधि मेवा में सम्मिलित नहीं होगी।

संशोधित विनियम

विियम 33 का स्पष्टीकरण II

इस विनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कर्मवारी ने साधारण अवकाश अर्जित किया हो लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख तक लिया नहो, उसको अपने विकल्प पर:

(क) इन विनियमों के ग्रन्तर्गत ग्रांजित ग्रवकाश के सम्बन्ध में ग्रिधिकतम 6 माह का ग्रवकाश लेने की ग्रनुमित दी जा सकती है ग्रीर उस मामले में श्रवकाश की समाध्ति पर कर्मवारी को सेवानिवृत्त समझा जायेगा।

या

(ख) एक मुक्त राशि, जो कि न लिए गए प्रधिकतम 6 माह के प्रजित प्रयकाण के लिए उसकी सेवानियृत्ति की तारीख के प्रनुसार वेतन, जैसा कि इन विनियमों के विनियम 3(ण) में परिभाषित है, महंगाई भत्ते सहित वेतन के समकक्ष होगी, की भ्रदायगी की जाएगी।

स्पष्टीकरण III: उपर्युक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित ग्रनुसार किसी कर्मचारी को मेवा-निवृत्त करने के ग्रिधकार को कार्यान्वित करने हेतु निगम ऐसे कर्मचारियों के मामलों का, उनके 50 वर्ष एवं 55 वर्ष की ग्रायु प्राप्त करने श्रथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के 6 मास पूर्व पुनरीक्षण करेगा,

तथा इस मामले में सिफारिशें देने के लिए ग्रध्यक्ष द्वारा एक विशेष पुतरीक्षण समिति का गठन किया जायेगा।

- (3) यदि किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के समय निगम की सेवा में पुनित्युक्त किया जाता है अथवा निगम से बाहर नियुक्त के लिए अनुमति दी जाती है तो इस प्रकार की सेवा की समाप्ति के तुरन्त बाद उसे छुट्टी अथवा छुट्टी का कुछ भाग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है या अनुमति प्रदास की जा सकती है परन्तु उसकी ऐसी नियुक्ति की अवधि—-
 - (i) यदि वह निगम की सेवा में पुनित्युक्त किया गया है तो, पुनित्युक्ति की सतीं के प्रधीत की गई व्यवस्था की सीमा को छोड़कर, निगम में उसकी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन हेतु सेवा प्रथवा इयुटी नहीं मानी जायेगी।
 - (ii) यदि वह निगम के बाहर नियुक्त किया गया है तो, विनियम 130 तथा इन विनियमों के अध्याय IV के प्रयोजनों को छोड़कर, निगम में किसी भी प्रयोजन हेतु सेवा अथवा ड्यृटी नहीं मानी जायेगी।

विभियम 33 के भ्रन्तर्गत स्पष्टीकरण IV (भ्रावर्धन):

"सेवानिवृत्ति की तारीख" का श्राशय उस तारीख से हैं जिसको कि वह इस विनियम के उपबन्धों के श्रनुसार निवर्तन श्रायु पूरी कर लेता है या उस तारीख सें हैं जिसको कि कर्म-चारी विनियम के उप-विनियम (1) के श्रधीन नियम द्वारा सेवा-निवृत्त कर दिया जाता है या उस तारीख से हैं जिसको कि वह उक्त उप-विनियम (1) की शर्तों के श्रनुसार स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो जाता है, जैसा भी मामला हो।

ग्रध्याय-17

आचरण, अनुशासन ग्रीर अपीलें

खण्ड- 1---श्राचरण श्रीर श्र<u>न</u>ुशासन

34. कर्मचारी की सेवाका विस्तार

- (1) जब तक भ्रन्यथा स्पष्ट रूप मे उल्लेख न किया जाए, कर्मचारी का सारा समय निगस की सेवा में रहेगा भ्रौर वह समय-समय पर निगम द्वारा निदेशित हैसियत मे, निदिष्ट समय भ्रौर स्थान पर निगम के कारोबार में श्रपनी सेवा श्रिपत करेगा।
- (2) उप-विश्यम (1) पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना, निगम—
 - (क) श्रपने कर्मचारियों के लिए सामान्यतः श्रथवा विभिन्न कर्मचारियों के लिए विभिन्न रूप से या विभिन्न कार्यालयों, शाखाग्रों श्रयवा विभागों के लिए कार्य-समय िश्चित करेगा,
 - (ख) क्रमेचारियों से पारियों में सिकय रूप से उपस्थित होने की ग्रिपेक्षा कर शकता है।

- (3) विनियम 140 से किसी बात के होते हुए भी, निगम द्वारा निर्धारित गर्नों के श्रधीन, निगम इसके स्टाफ के सदस्यों, अधिकारियों तथा श्रन्य कर्मचारियों को भारत में कहीं भी, इसकी विसपोपित संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य स्तर के विसीय संस्थानों श्रादि, में जहां कार्य की श्रनिवार्यता में इस प्रकार की नियुक्ति निगम द्वारा निश्चित श्रवधि के लिए श्रावण्यक हो, नियुक्त कर सकता है।
- 35. विनियमों, भ्रादेशों तथा भ्रनुदेशों का पालन करने का दायित्व
- (1) िनगम का प्रत्येक कर्मचारी इन विनियमों का पालन करेगा श्रीर उनसे बाध्य होगा तथा निगम उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए गए श्रादेशों तथा श्रनुदेशों का पालन करेगा जिनके क्षेत्राधिकार, श्रधीक्षण श्रथवा नियंत्रण में कार्य कर रहा है। यह सबैव कर्नव्य की निष्ठा एवं सत्यनिष्ठा को पूर्णतया बनाए रखेगा श्रीर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो निगम के कर्मचारी के लिए श्रशांभनीय है।
- (2) प्रत्येक कर्मचारी, तत्समय ग्रपने नियंत्रण तथा प्राधिकार में कार्य कर रहे निगम के सभी कर्मचारियों की कर्तांक्य के प्रतिनिष्ठा तथा मत्य निष्ठा को बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा।
- (3) कोई भी कर्मवारी, अपने शासकीय कर्संक्यों के निष्पादन में या उसे प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोग में, केवल उस स्थिति को छोड़कर जिसमें वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के तिदेशों के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वोत्तम विवेक से अन्यथा कार्य नहीं करेगा तथा यदि वह ऐसे किसी निदेश के अधीन कार्य कर रहा हो जो जहां कहीं व्यवहार्य हो, लिखित निदेश प्राप्त करेगा और यदि लिखित निदेश प्राप्त करेगा क्या वहार्य नहीं तो वह उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो, निदेश की लिखित पृष्टि प्राप्त करेगा।

परन्तु उप-विनियम (3) में निहित किसी बात का यह स्रर्थ नहीं होगा कि कोई भी कर्मचारी, ग्रपने उच्च श्रधिकारी स्रथवा प्राधिकारी से ग्रनुदेश ग्रथवा भ्रनुमोदन प्राप्त करके श्रपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा, जबकि शक्तियों तथा दायित्वों के वितरण के श्रधीन ऐसे श्रनुदेश प्राप्त करना भावश्यक नहीं है।

36. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक कर्मचारी निगम तथा उसके घटकों के कार्यों के बारे में पूर्णतया गोपनीयना बनाए रखेगा और जब तक न्यायिक या दूसरे प्राधिकारी द्वारा किसी कानून के अनुपालन में विवश न किया जाए या अपने कार्यपाल के संदर्भ मंबरिष्ठ प्रधिकारी द्वारा निर्देशित न हो, तब तक ज न्याधारण को या निगम के कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में गोपनीय प्रकृति की कोई सूच ग नहीं देगा।

37. कमीचारी निगम के हित को बढ़ायेंगे

प्रत्येक कर्मचारी ईमानवारी निष्ठा से निगम की सेवा करेगा तथा निगम के हितों की बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा तथा किसी भी सरकार के अधिकारियों या प्रतिनिधियों ग्रौर निगम के घटकों या निगम के सेाथ सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति ग्रौर निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ सभी लेनदेनों तथा व्यवहार में शिष्टता ग्रौर सावधानी बरतेगा।

38. राजनीति तथा चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध

- (1) कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं बनेगा अथवा किसी भी रूप में उससे संबद्ध नहीं होगा और नहीं किसी राजनैतिक आदोलन अथवा गतिविधियों में भाग लेगा, और न उसकी सहायता में चन्दा देगा या अन्य किसी प्रकार से सहायता करेगा।
- (2) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ग्रपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी ऐसे ग्रान्दोलन ग्रथवा गतिविधि में भाग लेने, उसे चन्दा देने ग्रथवा ग्रन्य किसी प्रकार से-सहायता देने से रोकने का प्रयास करे, जो निगम या विधि द्वारा सरकार के लिए प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसक हो, ग्रौर यदि कर्मचारी ग्रपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे ग्रान्दोलन ग्रथवा गतिविधि में भाग लेने, चंदा देने ग्रथवा ग्रन्य किसी प्रकार से सहायता करने से रोकने में ग्रसमर्थ हो तो वह निगम को उसकी रिपोर्ट देगा।
- (3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई राज-नैतिक दल है, अथवा क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आन्दोलन अथवा गतिविधि इस विनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तो इस सम्बन्ध से अध्यक्ष का निर्णय अस्तिम होगा।
- (4) कोई कर्मचारी किसी विधाः मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के किसी चुनाव के लिए प्रचार या ग्रन्थया हस्तक्षेप ग्रथवा उसके सम्बन्ध में ग्रपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा ग्रथवा भाग नहीं लेगा, परन्तु,
 - (i) इस प्रकार के चुनाव में मत देने के लिए योग्य कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। ऐता करते समय वह इस बात का कोई संकेत नहीं देगा कि उसका किय प्रकार मत देने का विचार है अथवा मत दिया है,
 - (ii) किसी कर्मचारी द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के उचित िष्पादा में या तत्समय लागू किसी कानूनी के अन्तर्गत किसी चुाव के कार्य-संचाल में सहायता करने माल से इस विधियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण : कर्मचारी द्वारा उसके शरीर, वाहन अथवा निवास पर किसी चुनाव चिह्न का प्रदर्शन, इस उप-विनियम के अर्थ के अन्तर्गत चुनव के सम्बन्ध में उसके प्रभाव का उपयोग िहित होगा।

39. कर्मचारियों द्वारा संघों का सदस्य बनना

कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा उसका सदस्य नहीं बनगरहेगा जिसके उद्देश्य अथवा गतिविधियां, भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता के हितों, सार्वजिनक व्यवस्था, अथवा नैतिकता के विरुद्ध हों।

40. प्रदर्शन तथा हड़तालें

- (i) कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता ग्रौर ग्रखण्डता, राज्य की सुरक्षा, िगम के हितों, विदेशी राज्यों के साथ मैदीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजिनक व्यवस्था, शिष्टाचार ग्रथवा नैतिकता के विरुद्ध हो ग्रथवा जिससे न्यायालय की ग्रवहेलना, पद की मानहानि या तौहीन होती हो।
- (ii) कोई भी कर्मचारी, जो श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 के श्रर्थ के अन्तर्गत "कर्मकार" नहीं है, अपनी या निगम के किसी कर्मचारी ग्रथवा कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित किसी भी, विषय के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की हड़ताल की प्रश्रय ग्रथवा उसका साथ नहीं देगा।

स्पष्टीकरण I: उपर्युक्त विनियम में "प्रदर्शन" शब्द में विरोध अथवा क्षोभ प्रकट करने वाले लिखित बैज पहनना, नारे लगाते हुए जुलूसों का संगठन करना, जनता के लिए प्रवेश योग्य बैठकें आयोजित करना, आपत्तिजनक इश्तिहार लगाना, आम जनता को सम्बोधित बुलेटिन निकालना तथा बहुसंख्यक कर्मचारी वर्ग का नारे लगाता हुआ प्रतिनिधि-मंडल सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण II: उपर्युक्त विनियम में "हड़ताल" शब्द का अर्थ है संयुक्त रूप से कर्मचारियों के वर्ग द्वारा काम करने से मना करना, काम बन्द करना या धीमी गित से काम करना तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

- (i) अनुमित के बिना, कार्य से सामूहिक अनुपस्थिति (जिसे गलत प्रकार से "सामूहिक आकस्मिक छुट्टी" कहा जाता है)
- (ii) समयोपरि कार्य करने से मना करना जबिक ऐसा समयोपरि कार्य निगम के हित में हो,
- (iii) ऐसे व्यवहार अथवा आचरण को प्रश्रय देना, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय के कार्य में इकावट आये अथवा उसमें अत्यिधिक विलम्ब हो। इस प्रकार के व्यवहारों में 'धीमी गित से काम करना", "काम न करना", "खाली बैठना", "कलम बन्द करना", "धरना देना", "सांकेतिक", "सहानुभूति में" अथवा इस प्रकार की अन्य हड़तालें, बन्ध अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य आन्दोलन में भाग लेने हेतु कार्य से अनुपस्थिति भी इसमें सम्मिलित है।

41. प्रेस तथा रेडियो से सम्बन्ध

(1) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना कोई भी कर्मचारी सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी समाचार-पत्न अथवा अन्य आविधिक प्रकाशन के सम्यादन अथवा प्रबन्ध का स्वामी नहीं होगा अथवा उसके सम्पादन या प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा अथवा अपने पद की हैसियत से उसके अधिकार में आए हुए किसी दस्तावेज, कागजपत्र या सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट अथवा प्रकाशित नहीं करेगा।

- (2) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के विना अथवा अपने कर्त्तच्य के वास्तविक निष्पादन के अतिरिक्त, कोई भी कर्मचारी स्वयं अपने, अज्ञात अथवा छद्म या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से—
 - (क) स्वयं अथवा किसी प्रकाशन के माध्यम से अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करवायेगा अथवा किसी पुस्तक या लेख संकलन में अपना लेख नहीं देगा, अथवा
 - (ख) रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्न अथवा पत्निका में अपना लेख नहीं देगायापत्न नहीं लिखेगा।

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी---

- (i) यदि ग्रेसा प्रकाणन किसी प्रकाणक के माध्यम से हो तथा पूर्णतः साहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का हो, अथवा
- (ii) यवि ऐसा योगवान, प्रसारण, अथवा लेख कभी-कभी दिया जाता हो तथा वह पूर्णतः साहिस्यिक, कला-स्मक, अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का हो।
- (3) उपर्युक्त खण्ड (2) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को संक्षम प्राधिकारी को वार्ता का सम्पूर्ण पाठ प्रस्तुत करना होगा यदि—
 - (i) विषय उसके शासकीय कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है,
 - (ii) पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में दिये गए यदि कुछ कथनों के भ्रामक निबंचन की संभावना है,

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, अधिकारियों के मामले में सक्षम प्रधिकारी का अर्थ है 'अध्यक्ष' तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में 'महाप्रबन्धक' होगा।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार है कि उसके द्वारा वियागया प्रसारण या लेखन उपर्युक्त खण्ड (2) के परन्तुक के अम्तर्गत आता है।

42. निगम तथा सरकार की आलोचना

(1) निम्नलिखित उप-विनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी कर्मचारी अपने या अज्ञात, छद्म अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम से किए गए किसी रेडियो प्रसारण या प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा किसी प्रेस सूचना अथवा किसी सामान्य अभिव्यक्ति में निम्नलिखित किसी तथ्य अथवा मत का कोई कथन नहीं देगा---

- (i) जिससे निगम, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की चालू अथवा हाल की ही नीति अथवा कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; अथवा
- (ii) जिससे निगम अथवा उसके प्रवन्धक वर्ग की अव-मानना अथवा बदनामी हो;
- (iii) जिससे निगम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकीर अथवा निगम और भारत में या उसके बाहर किसी भी वित्तीय संस्थान या संस्थाओं या निगम और उसकी किन्हीं वित्तपोषित संस्थाओं के बीच सम्बन्ध उलझनकारी हो सकते हों;
- (iv) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी सरकार के मध्य सम्बन्ध बिगड़ने की संभावना हो।

परन्तु किसी कर्मचारी द्वारा अपने पद की हैसियत में अथवा उसे सौंपे गये कार्य के उचित निष्पादन में दिए गए किसी अन्य कथन अथवा प्रकट किए किसी विचार के सम्बन्ध में खण्ड (1) में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

- (2) फर्मचारियों की सेवा की शतों की सुरक्षा के लिए अथवा उनमें सुधार के प्रयोजन हेतु, किसी कर्मचारी द्वारा "आई० एफ० सी० इम्पलाइज एसोसिशन" या कर्मचारियों के किसी अन्य मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ के पदाधिकारिये के रूप में व्यक्त किए विचारों की "वास्तविक" अभिव्यंविक पर उपर्युक्त उप-विनियम (1) (i) में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- (3) विदेशों का भ्रमण करने वाले निगम के कर्मचारियों को भ्रमण किए गए देश में स्थित भारतीय मिशन के प्रमुख की विशेष पूर्व अनुमति के बिना भारतीय अथवा विदेशी मामलों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने तथा विशेष रूप से, लिखित अथवा मौखिक कथन देने से बचना चाहिए।
- 43. किसी समिति अथवा अन्य प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य देना ।
- (1) उप-विनियम (3) में यथा उपविन्धित के सिवाय, कोई भी कर्मचारी, महाप्रबन्धक की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति, सिमिति अथवा प्राधिकरण द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा।
- (2) यदि उप-विनियम (1) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो तो इस प्रकार की साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी, निगम या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या अन्य किसी भी वित्तीय संस्थान की नीति अथवा किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।
- (3) इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी।
 - (क) सरकार, संसद या राज्य विधान सभा अथवा निगम द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य;

- (ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्यः
- (ग) सरकार अथवा निगम के अधीनस्य प्राधिकरणों द्वारा आदेशित विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

44. गैर शासकीय और अन्य प्रभाव डलवाना

कोई भी कर्मचारी, निगम में अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए निगम के किसी भी प्राधिकारी पर किसी भी प्रकार का राज-नैतिक अथवा अन्य बाह्य दबाव नहीं डालेगा अथवा डालने का प्रयास करेगा।

- 45. निगम से सम्बन्धित फर्मों में निकट सम्बन्धियों का नियोजन
- (1) कोई भी कर्मचारी, निगम से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी अथवा फर्म में अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नियोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हैं सियत अथवा प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा।
- (2) प्रथम श्रेणी का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधि-कारी की पूर्व अनुमित के बिना अपने पुन्न, पुन्नी अथवा किसी अन्य आश्रित व्यक्ति को निगम से शासकीय व्यवहार रखने वाली किसी फर्म अथवा कम्पनी में नियोजन स्वीकार करने की अनुमित नहीं देगा।

परन्तु यदि नियोजन की स्वीकृति के लिए निगम की पूर्व अनुमित की प्रतीक्षा करना सम्भव न हो अथवा उसे अत्यन्त आवश्यक समझा जाए तो, निगम को उसकी सूचना दी जायेगी तथा निगम की अनुमित की शर्त के अधीन नियोजन अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जाए।

- (3) जैसे ही किसी कर्मचारी को अपने परिवार के किसी मबस्य द्वारा किसी कम्पनी अथवा फर्म में नियोजन स्वीकार करने की जानकारी प्राप्त हो, वह इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा और वह यह भी सूचित करेगा कि क्या उसके उस कम्पनी अथवा फर्म के साथ कोई शासकीय सम्बन्ध हैं अथवा थे।
- (4) कोई भी कर्मचारी, अपने शासकीय कर्त्तंच्यों का पालन करने में किसी कम्पनी, फर्म अथवा किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी विषय पर कार्यवाही नहीं करेगा अथवा उसे संविदा देगा या मंजूर करेगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस कम्पनी अथवा फर्म में, या उस व्यक्ति के अन्तर्गत कार्यरत हो अथवा यदि या उसके परिवार का कोई सदस्य ऐसे मामले या संविदा में किसी अन्य प्रकार से विलचस्पी रखता हो, तो कर्मचारी ऐसा प्रत्येक मामला या संविदा अपने घरिष्ठ प्राधिकारी को भेजेगा तथा उसके पण्चात् मामले या संविदा का निपटान, उस अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जिसके पास मामला भेजा गया था।

स्पष्टीकरणः:—इस विनियम में कर्मधारी के सम्बन्ध में ''परिवार के सदस्य'' के अर्थ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, चाहे वह उसके साथ रह रहा/रही हो अथवा नहीं, परन्तु किसी सक्षम अदालत की डिक्री या आदेश द्वारा कर्मचारी से श्रलग रहने वाली पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, इसमें शामिल नहीं होते:

- (ii) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित पुत्न या पुत्नी अथवा सौतेला पुत्न अथवा सौतेली पुत्नी, परन्तु इसमें ऐसी सन्तान या सौतेली सन्तान सम्मिलित नहीं होती जो किसी भी प्रकार कर्मचारी पर आश्रित नहीं है अथवा विधि द्वारा या उसके अधीन जिसकी अभि-रक्षा से, कर्मचारी को वंचित कर विधा गया हो; तथा
- (iii) कर्मचारी अथवा उसकी पत्नी या उसके पति से रक्त अथवा विवाह द्वारा सम्बन्धित कोई अम्य व्यक्ति, जो पूर्णतः उस^कपर आश्रित हो।

46. उपहार स्वीकार करना

- (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना निगम से शासकीय रूप से सम्बन्धित किसी व्यक्ति अथवा अधीनस्थ कर्मचारी से अल्प मूल्य से अधिक मूल्य के उपहार की मांग अथवा उसे स्वीकार नहीं करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे उपहार की मांग करने अथवा स्वीकार करने की अनुमित नहीं देगा
- (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई उपहार ग्रल्प मूल्य का है श्रथवा नहीं या यदि कर्मचारी का संदेह हो कि उसे प्रदान किया गया उपहार श्रल्प मूल्य का है श्रथवा नहीं तो ऐसा मामला सक्षम प्रिष्ठकारी के पास भेज दिया जायेगा तथा उस पर उसके द्वारा दिया गया निर्णय श्रन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण:— ''उपहार'' शब्द में, निगम ग्रंथवा कर्मश्रारी से शासकीय सम्बन्ध न रखने वाले किसी निकट सम्बन्धी ग्रंथवा वैयक्तिक मिन्न के श्रितिरिक्त किसी ग्रन्थ यक्ति द्वारा प्रदान किये गये निःशुल्क परिवहन, भोजन व्यवस्था, ग्रावास ग्रंथवा ग्रन्य सेवाएं या ग्रन्य कोई भी ग्रंधिक लाभ सम्मिलित है।

टिप्प्णी I := यदा कदा भीजन, लिफ्ट, ग्रथवा श्रन्य सामाजिक श्रादर सत्कार "उपहार" नहीं समझे जाएंगे ।

टिप्पणी II : कर्मचारी ऐसे व्यक्ति, श्रौद्योगिक श्रथवा व्यावसायिक फर्मी या संगठनों श्रादि से, जिनसे उसका शासकीय सम्बन्ध है, श्रिक्षक खर्चीले सत्कार अथवा बारम्बार सरकार की स्थिति से बचेगा।

(3) विवाह, वर्षगाठों, अन्त्येष्टि श्रथवा धार्मिक उत्सवों पर कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों से उपहार स्वीकार नहीं करेगा जिनसे उसका शासकीय सम्बन्ध है। 46 क. दहेज लेना अथवा देना

कोई भी कर्मचारी

- (i) न तो दहेज देगा ग्रंथवा लेगा या दहेज के लेन देन को प्रोत्साहित करेगा, श्रथवा
- (ii) न ही दुल्हन दूल्हे के माता पिता प्रथवा संरक्षकों से प्रत्यक्ष या, प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा। स्पप्टीकरण:——उस विनियम के प्रयोजनों हेतु "दहेज" का वही प्रथं है जो दहेज प्रतिषेध ग्रिधिनियम 1961 (1961 का 28) में हैं।

47. ग्रभिदान

किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निगम की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्मचारी, किसी निधि को एकस्न करने या नकद या वस्तु रूप में श्रन्य संग्रह करने के लिये ग्रंशदान की मांग ग्रथवा स्वीकृति ग्रथवा उसके साथ श्रपने को ग्रन्यथा सम्बन्ध नहीं करेगा।

48. निवेश, उधार देना तथा उधार लेना

(1) कोई भी कर्मचारी किसी स्टाक, शेयर या प्रन्य निवेश या किसी प्रकार की ग्रन्य वस्तुओं का सट्टा नहीं करेगा

परन्तु इस उप विनियम में निहित किसी भी बात का तात्पर्य किसी कर्मचारी को उसकी इंग्छानसार उसकी बचत का हितकारी निवेश करने से रोकना नहीं होगा।

- स्पष्टीकरण:--इस उप विनियम के श्रथ में, स्टाकों, शेयरों, प्रतिभूतियों श्रथवा श्रन्य निवेशों का श्रादतन कय श्रथवा विकय श्रथवा क्रय विकय दोनों सट्टा माने जाक्षेगे;
- (2) कोई भी कर्मचारी न तो स्वयं ऐसा निवेश करेगा श्रीर न ही ग्रपने परिवार के किसी सदस्य को श्रथवा उसकी श्रोर से किसी व्यक्ति को ऐसा निवेश करने की श्रनुमित देगा जिससे उसे शासकीय कत्तव्यों का पालन करने में बाधा पड़ने श्रथवा उसके प्रभावित होने की संभावना हो।

स्पष्टीकरण:-इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिये "परिवार के सदस्य" ग्राभिक्यक्ति से वही ग्रार्थ ग्राभिप्रेत है जो विनियम 45 के स्पष्टीकरण से दिया गया है।

- (3) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) की प्रकृति का है, तो इस सम्बन्ध में श्रध्यक्ष का निर्णय श्रन्तिम होगा ।
- (4) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना कोई भी कर्म चारी, स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा अपनी और से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस स्थान की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जहां वह तत्समय ख्यूटी पर हो, प्रत्यक्ष या एजेन्ट के रूप में ब्याज पर, अथवा धन या वस्तु के रूप में उगाही अथवा अदायगी पर किसी व्यक्ति को धन उधार नहीं देगा :—

परन्तु कर्मचारी, ऐसी मंजूरी के बिना निजी सेवक को ग्रत्प राशि ग्रिप्रिम श्रथवा ग्रदायगी ग्रथंवा उधार या श्रपने निजी मित्र श्रथवा सम्बन्धी को क्याज रहित श्रल्प राशि पूणतः श्रस्थायी ऋण के रूप में दे सकता है।

स्पष्टीकरण:—इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु डाक घर तथा वाणिज्य श्रौर महकारी बैंकों में जमा धन उधार में सम्मिलित नहीं होगा ।

(5) कोई भी कर्मचारी, बैंकिंग व्यापार के लिये विधिवत् प्राधिकृतत किसी प्रतिष्ठित बैंक या फर्म के साथ व्यापार के ग्राम लेन बैंक के अलावा स्वयं प्रथवा प्रपन परिवार के किसी सदस्य प्रथवा ग्रपनी श्रीर से किसी व्यक्ति के माध्यम से उस स्थान की स्थानीय सीमाग्रों के भीतर, जहां वह तत्समय ड्यूटी पर हो श्रथवा जिसके साथ उसके शासकीय सम्बन्ध होने की संभावना हो, धन उधार नहीं लेगा या धन सम्बन्ध होने की संभावना हो, धन उधार नहीं लेगा या धन सम्बन्ध ग्राभार नहीं लेगा, श्रीर न ही, सक्षम प्राधिकारो की पूर्व अनुमति के बिना, श्रपने परिवार के किसी सदस्य की इस प्रकार के लेन देन में सम्मिलित होने की श्रनुमित देगा;

परन्तु, कोई भी कमघारी श्रपने मित्र श्रथवा सम्बन्धी से श्रल्प रामि का ब्याज रहित, पूर्णत अस्थाई ऋण ने सकता है या किसी प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ श्रपना उधार खाता रख सकता है।

परन्तु यह श्रोर कि सक्षम प्राधिकारो की पूर्व मंजूरी से कर्मचारी द्वारा कोई लेन-देन किये जाने के सम्बन्ध में इस उप विनियम की कोई भी बात लागू नहीं होगी।

(6) यदि किसी कर्मचारी को किमी ऐसे पत्न प्रथवा स्थान पर नियुक्त श्रथवा स्थानान्तरित किया जाये जहां उसके द्वारा, उप विनियम (2), उप विनियम (4) श्रथवा उप विनियम (5) के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो तो वह तत्काल उस परिस्थितियों की सूचना, सक्षम प्राधिकारी को देगा श्रीर तत्पश्चात् उस प्राधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों अथवा श्रनुदेशों के श्रनुसार कार्य करेगा।

49. निजी व्यवसाय तथा नियोजन

(1) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रनुमित के बिना प्रत्यक्ष प्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवसाय या व्यापार या कोई श्रन्थ नियोजन नहीं करेगा;

परन्तु कोई भी कर्मचारी, अनुमति के बिना धार्मिक, सामाजिक धर्मार्थ प्रकृति का कार्य अवैतिनिक रूप से कर सकता है। कभी-कभी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का कार्य कर सकता है, बजते कि उससे उसके शासकीय कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा काम करने को मना करे तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा अथवा करना बन्द कर देगा।

स्पष्टीकरण:——िकसी कर्म चारी द्वारा उसकी पत्निया उसके परि-वार के किसी श्रन्य सदस्य द्वारा संचालित, उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा निर्यावित बीमा ऐजेन्सी श्रादि के कार्य के समर्थन में प्रचार किया जाना इस उप-विनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।

- (2) यदि किसी कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी व्यवसाय या व्यापार में लगा हो, प्रथवा किसी बीमा ऐजेन्सी यो कमीशन ऐजेन्सी का स्वाभी या प्रबंधक हो तो, वह इसकी मुचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।
- (3) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना और श्रथने कासकीय कर्तव्यों के निष्पादन के अलावा तत्समय लागू किसी कानून के अन्तगत पंजीकृत किए जाने वाले किसी बैंक या कम्पनी अथवा वाणिष्यिक प्रयोजनों के लिए सहकारी समिति के पंजीकरण या प्रवन्ध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु किसी कम्पनी, सहकारी समिति या किसी राज्य वित्तीय निगम श्रथवा किसी श्रन्य संस्था के बोर्ड या उसके प्रबन्ध कार्य सौंपे गए श्रन्य निकाय में निगम द्वारा इसके नामित ब्यक्ति के रूप में नामांकित किए गए किसी कर्मचारी के सबंध में इस उप-नियम में सं क्रुष्ठ भी लागू नहीं होगा।

परन्तु यह श्रौर कि इस उप-विनियम में से कुछ भी किसी कर्म-चारी को सहकप्री सिमितियों के संबंध में तत्समय लागू किसी कानून के ध्रधीन पंजीकृत निगम के कमचारियों द्वारा मूलत : कर्म-चारियों के हित के लिए गठित किसी सहकारी सिमिति श्रथवा तत्समय लागू किसी कानून के श्रधीन पंजीकृत, कला, विज्ञान, धर्म या धर्मार्थ के संबद्धन के लिए किसी सिमिति या कम्पनी के पंजीक्ररण, प्रवर्त्तन या प्रबन्ध में भाग लेने से नहीं रोकेगा।

- (4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, कोई भी कर्म-चारी किसी सार्व बनिक निकाय श्रयवा किसी व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार न करे।
- 50, दिबालियापन तथा आदतन ऋणग्रस्तता
- (1) कर्मचारी अपने निजी कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार करेगा जिससे आदतन ऋण्यस्तता अथवा दिवालियेपन ते दूर रह सके। जिस कर्मचारी को दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णित करने के लिए उसमें देय राशि की वसूली हेतु उसके विरुद्ध कानूनी कार्य-वाही की जाती है वह तत्काल कानूनी कायवाही के सम्पूण तथ्यों की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।
- टिप्पणी: यह सिद्ध करना कर्मचारी का कर्त्तव्य होगा कि दिवालिया-पन या ऋणग्रस्तता उन परिस्थियों का परिणाम था, भिमका वह साधारण सचेतना से पूर्वानुमान नहीं लगा सका, भ्रथवा िन पर उसका नियंत्रण नहीं था भौर फिजूलखर्ची या दुर्व्यसनों की भादतों के कारण ऐसा नहीं हुआ है ।
- 51. चल तथा ग्रचल सम्पत्ति का ग्रजन ग्रौर निपटान
- (1) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना कोई भी कर्मचारी अपने नाम प्रथवा प्रयने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, ऋष-विक्रय, उपहार द्वारा या प्रन्य किसी प्रकार से किसी श्रचल सम्पत्ति का ग्रर्जन या निपटान नहीं करेगा:

परन्तु कर्मचारी, निधीरित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी यदि ऐसा लेन-देन—

(i) कर्मचारी के साथ शासकीय सम्बन्ध रखने वाले अयक्ति के साथ किया जाएगा, प्रथा

- (ii) नियमित प्रथवा प्रतिष्ठित च्यापारी से भिन्न ग्रन्य किसी माध्यम से किया जाए।
- (2) श्रेणी-I तथा II के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामाले में 1000/- रुपए से अधिक मूल्य अथवा श्रेणी-III श्रौर IV के कर्मचारियों के मामाले में 500/- रुपए से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, प्रत्येक कर्मचारी उसके श्रथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से किए गए प्रत्येक लेन-देन की सुचना निर्धारित प्राधिकारी को देगा ।

परन्तु, कर्मचारी, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेगा यदि ऐसा लेन-देन—

- (i) कमच्चारी के साथ शासकीय सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के साथ, ग्रथवा
- (ii) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी भिन्न अन्य किसी माध्यम से किया जाए।

स्पष्टीकरण:—इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु चल सम्कत्ति' के अर्थ में भ्रन्य जातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्पत्ति भी सम्मिलित है, भ्रर्थात्—

- (क) जवाहरात, 1000 रुपए या कर्मचारी की क़ुल वाधिक परिलब्धियों के छठे भाग, जो भी कम हो, श्रधिक वाधिक प्रीमियमों की बीमा पालिसियां, शेयर, प्रति भूतियां श्रौर डिबेंचर;
- (ख) कर्मचारी द्वारा दिए गए रक्षित ग्रथवा ग्रारक्षित 🗽 ऋण;
- (ग) मोटर कारें, मोटर-साइकिल, घोड़े अथवा अन्य किसी प्रकार के वाहन; श्रीर
- (घ) रोफि बरेटर्स, रेडियो तथा रेडियोग्राम ।
- (3) प्रत्येक कर्मचारी निगम में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके पण्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में, अध्यक्ष द्वारा इस हेतु तथा-निर्धारित प्रपत्न में उसकी परिसम्पित्यों तथा देयताश्रों का विवरण प्रस्तुत करेगा निसमें निम्निलिखित का पूर्ण ज्यौरा दिया जायेगा।
 - (क) कर्मचारी द्वारा उसके अथवा उसके परिवार के किस. सदस्य या किस. अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे, यां बन्धक पर प्राप्त की गई, प्राप्ति की गई अथवा उसराधिकार में प्राप्त सम्पूर्ण ग्रवल सम्पत्ति;
 - (ख) उसे उत्तराधिकार ग्रथवा उसी प्रकार से ग्रजित ग्रथवा धारित शेयर, डिबेंचर तथा नकदराशि बैक में जमा राशि भी शामिल है;
 - (ग) उसे उत्तराधिकार श्रथवा उसी प्रकार से प्राप्त, ऑजित या धारित अन्य चल सम्पत्ति; और
 - (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से . देय हुए ऋण और अन्य देयतायें।

टिप्पणी: सभी विवरणों में 1,000 रुपये से कम मूल्य की अपल सम्पत्ति की वस्तुएं भी सम्मिलित की जाएं और उसे एक मुक्त राणि के रूप में दिखाया जाए। इस प्रकार के विवरण में दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे, वस्र, बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पुस्तकों, आदि मूल्य सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

- (4) इस विनियम के .उप-विनियम (1) और (3) के उपबन्ध सामान्यतः श्रेणी 1 के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, चाहे वह अस्थायी परिवीक्षाधीन, स्थानापन्न या मूल हैं, सियत में नियुक्त हो अथवा प्रतिनिय्क्ति पर या बाह सेवा पर नियुक्त हों परन्तु अध्यक्ष की स्वेच्छा से इसके लिए सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा इन्हें अन्य श्रेणी के कर्म-चारियों पर भी लागू किया जा सकता है।
- (5) अध्यक्ष, समान्य अथवा विशेष, जैसा भी उसमें उल्लिखित हो, द्वारा, किसी भी समय किसी भी कर्मचारी से, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित या अजित, चल या अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण और पूरा विवरण, आवेश में निर्दिष्ट अवधि तक प्रस्तुत करनें का आदेश दे सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षत हो तो इस प्रकार के विवरण में जिस प्रकार अथवा जिन साधनों से यह सम्पत्ति आजित की गई है, वे भी सम्मिलित किए जायेंगे।

52. कुछ प्रयोजनों के लिए निगम के कर्मेचारियों का 'लोक सेवक'' के रूप में माना जाना

दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1958 द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के खण्ड 12 के अधीन निगम के कर्मचारी "लोक सेवक" समक्षे जायेंगे और लोक सेवकों से सम्बन्धित उक्त दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के उपबंध उन पर लागू होंगे।

53. कर्मचारियों के कार्यों और चरित्र का दोष निवारण

श्रेणी I अथवा श्रेणी II के पद पर कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना, ऐसे किसी शासकीय कार्य के दोष निवारण के लिए न्यायालय अथवा प्रैस का आश्रय नहीं लेगा, जिसका विषय प्रतिकूल आलोचना अथवा मानहानिकारक प्रकृति का हो।

स्पष्टीकरण—इस विनियम में से कुछ भी, किसी कर्म-चारी को उसके निजी चरित्र अथवा निजी हैसियत से किए गए किसी कार्य के दोष निवारण से नहीं रोकेंगा, और यदि वह उसके निजी चरित्र चेथवा निजी हैसियत से किए गए किसी कार्य के दोष निवारण के लिए कार्यवाही करता है तो वह उस कार्य की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

54. द्विविवाह

(1) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना, तत्ममय उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमत्य होने पर भी, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह नहीं करेगा।

- (2) कोई भी महिला कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विना, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पत्नी जीवित हो।
- 55. नशीले पेयों तथा औषधियों का सेवन प्रत्येक कर्मचारी ---
 - (क) जिस क्षेत्र में वह रहता हो वहां नशीले पेयों औषधियों से सम्बन्धित कानून का कड़ाई से पालन करेगा –
 - (ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी नशीले पेय या औषधि के नशे में नहीं रहेगा और इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तथ्यों के निष्पादन पर ऐसे या पेय औषधि का प्रभाव न पड़े;
 - (ग) किसी मार्वजनिक स्थान पर नणीले पेयों या औषधियों का मेवन नहीं करेगा;
 - (घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में नहीं जाएगा; और
 - (ड) किसी नशीले पेय या औषधि का अत्यधिक मान्ना में सेवन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः—इस विनियम के प्रयोजन के लिए सार्व-जिनक स्थान से तात्पर्य है ''ऐसा कोई स्थान या परिसर (इसमें ऐसे क्लब जो केवल सदस्यों के लिए हैं परन्तु जहां सदस्य गैर-सदस्य व्यक्तियों को अतिथियों के रूप में आमिन्वत कर सकते हैं, णराब-घर और जलपान-गृह, वाहन शामिल हैं)। जहां, भुगतान करके या अन्यथा जन-साधारण की पहुंच हो अथवा पहुंचने की अनुमति हो।''

56 किसी कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

सक्षम प्राधिकारी की सामान्य अथवा विशेष मंजूरी के बिना, श्रेणी I तथा II के पद पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी मानपक्ष, विदाई मानपत्न या कोई ऐसा पत्न स्वीकार नहीं करेगा या स्वयं उसके अथवा किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में आयोजित बैठक अथवा आतिथ्य-मत्कार में भाग नहीं लेगा:

परन्तु इस विनियम में से क्रष्ठ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :--

- (I) किसं, कर्मचारी के सम्मान में अथवा किसी अन्य कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति या स्थानान्नरण के अवसर पर या होल ही में निगम की सेवा छोड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए आयोजित किया गया पूर्णत: निजी तथा अनौपचारिक विदाई अभिनन्दन समारोह; अथवा
- (II) सार्वजनिक निकायों अथवा संस्थानों द्वारा आयोजित साधारण तथा अत्यन्त अल्प-व्ययो अभिनन्दन समारोहों की स्वीकृति।

टिप्पणी:—किसी भी विदाई समारोह के लिए, चाहे वह पूर्णतः निजी या अनौपचारिक ही हो, अभिदान कःने के लिए किसी कर्मचारी को प्रेरित करने के उद्देण्य से उस पर किसी प्रकार क्वा दबाव या प्रभाव डालना, तथा निगम के किसी ऐसे कर्मचारी के सत्कार के लिए जो श्रेणी II तथा II का कर्मचारी न हो, किसी भी परिस्थित में श्रेणी II या IV के कर्मचारियों से अभिदान एकत्र करना निषद्ध है।

57. ड्यूटी से अनुपस्थिति

(1) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और नहीं बीमारी अथवा दुर्घटना होने पर उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण-पन्न प्रस्तुत किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से अल्पकालिक बीमारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पन्न देने की शर्त को सुभाष्त कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जो छुट्टी के बिना ड्यूटी से या अपनी छुट्टी से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों, जिनके लिए उसे संतोषजनक स्पम्टीकरण देना होगा, को छोड़ कर, वह, ऐसी अनुपस्थिति या छुट्टी से अधिक समय की अनुपस्थित के दौरान किसी प्रकार का बेतन या भत्ता, लेने का हकदार नहीं होगा, और वह उसके विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी अनुपस्थित अथवा छुट्टी से अधिक ठहरने की अबधि के बाद विनियम 27 के अन्तर्गत सेवा समाप्ति या विनियम 61 के अन्तर्गत बरखास्त्रगी नहीं की जाती तो ऐसी अबधि, सामनाय, बीमारी, विशेष अभवा अमाधारण अवकाश पर ध्यतीत की गई अवधि के रूप में — जैसा भी सक्षम प्राधि- जारी सुनिश्चित करे, मानी जा सकती हैं।

58. नियुक्ति स्थान से अनुपस्थिति

श्रेणी I तथा II के कर्मचारी निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी लिए बिना रातभर उनके नियुक्ति स्थान से अनुपहिथत नहीं होंगे;

- (क) यदि कर्मचारी स्वयं महाप्रबन्धक है तो अध्यक्ष ;
- (ख) श्रेणी I के कर्मचारियों के मामले में महाप्रवन्धक : और -
- (ग) अन्य मामलों में विभागाध्यक्ष ।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, तो उन मामलों में उपयुक्त अपेक्षाओं को समाप्त भी कर सकता है जिनमें ऐमा करना ठीक हो अथवा इस बात की संतुष्टि हो जाए कि प्रत्येक मामले में पिरिस्थितियां ऐसी थीं कि रातभर के लिए नियुक्ति स्थान छोड़ने से पूर्व अनुमित प्राप्त करना कर्मचारी के लिए संभव नहीं था।

- 59 कर्मचारियों द्वारा कार्य-घंटों का अनुपालन किया जाना तथा देर स न आना
 - (2. जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो अथवा अनुमित प्रदान न की जाए प्रत्येक कर्मचारी निश्चित कार्य समय का पालन करेगा और देर से नहीं अपेगा।
- (2) जिस कर्मचारी को देर से आने की आदत हो, उसके मामले में मक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए उचित दण्ड के अतिरिक्त, एक मास में प्रत्येक तीन दिन देर से आने पर एक दिन की आकस्मिक छुट्टी जब्त पर ली जामेगी। यदि किसी कर्मचारी के पास आकस्मिक छुट्टी बकाया न हो तो इस प्रकार जब्त की जाने वार्लः छुट्टी की अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित साधारण अथवा असाधारण छुट्टी के रूप में मानी जायेगी।
- 60. ऋण प्रस्तता या दण्डनीय अपराध के लिए कर्मचारियों को नजरबंदी या गिरफ्तार कना।
- (1) जो कर्मचारी ऋणग्रस्तता या दण्डनीय अपराध के लिए गिरफ्तार या किसी भी कानूनी प्रक्रिया में नजरबन्द किया जाता है, वह अपनी जानकारी के अनुसार, ऐसी गिरफ्तारी या नजरबन्दी जैसी भी स्थिति हो, के तथ्यों और उनके कारणों के तथ्य एवं सूचना की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को तत्काल करेगा अथवा करवाएगा।
- (2) यदि कर्मचारी को ऋणग्रस्तता के लिए जेल हुई हो या सक्षम प्राधिकारी के मतानुसार ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया हो जिसमें वह घोर नैतिक पतन का बोषी हो या जिससे कर्मचारी द्वारा निगम में ड्यूटी किए जाने पर निगम का कारोबार प्रभावित होता हो, तो उसे बरखास्त किया जा सकता है या विनियम 561 में उल्लिखित कोई भी घंड विया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का मत निर्णायक होगा एवं कर्मचारी पर बाध्य कर होगा। उसके जेल जाने या दोषी ठहराये जाने की तारीख से कर्मचारी को बरखास्त या उस पर कोई अन्य दंड लगाया जा सकता है और विनियम 61 में निहित कोई भी बात इस प्रकार के दंड पर लागू नहीं होगी।
- (3) यदि किसी कर्मचारी को उप-विनियम (2) के अनुसरण में बरखास्त कर दिया गया हो और उच्चतर न्यायालय ने उसके जेल जाने या दोषी ठहराये जाने को रह कर दिया हो और इसके अतिरिक्त दोषी ठहराये जाने के मामले में कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उसे पुन: सेवा में ले लिया जायेगा।
- (4) यदि किसी कर्मचारी को उप-विनियम (3) के अन्तर्गत पुनः सेवा में लें लिया जाता है, तो जितनी अविध के लिए वह उप-विनियम (2) के अन्तर्गत बरख़ास्त किये जाने के कारण इयूटी से अनुपस्थित रहा हो, उस अविध को इयूटी पर बिताई गई अविध के रूप में माना जायेगा और कर्मचारी उस वेतन और भत्तों पर हकबार होगा जो उसे बरखास्त न किए जाने पर प्राप्त होते:

परन्तु ऐसे वेतन और भत्ते, तिर्वाह भक्ते अथवा सम्बन्धित अवधि में निगम द्वारा उसे प्रदक्त किसी अग्य राणि के समायोजन के अधीन देय होंगे।

स्पष्टीकरण: — इस विनियम में जेल भेजने या दोषी ठहराने से यह तास्पर्य लिया जायेगा कि न्यूनतम न्यायालय या किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा या वोषी ठहराया गया है।

60. क दुराचार

"दुराचार" शब्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन विनियमों के विनियम 44 से 60 के अन्तर्गत उस्लिखित बातों के अतिरिक्त निक्नलिखित कताकृत "दुराचार" के रूप में माने जायेंगे:---

- (1) निगम के कारोबार या सम्पत्ति अथवा निगम के परिसरों में किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोरी, क्षोबाइड़ी या बेईमानी करना।
 - (2) रिश्वत या कोई अवैध भेंट लेना या देना।
- (3) किसी कर्मचारी या उसकी ओर किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा कर्मचारी की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में धन-सम्बन्धी संसाधन या सम्पत्ति का अधिग्रहण, जिसका कि वह कर्मचारी संतोषजनक रूप से हिसाब न दे सके।
- (4) नियोजन के समय या नियोजन के दौरान अपने नाम, आयु, पिता का नाम, अर्हता, योग्यता या पिछली सेवा अथवा नियोजन से सम्बन्धित किसी अन्य मामले के बारे में गलत जानकारी देना।
 - (5) निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के ढंग से कार्य करना।
- (6) अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर या अन्यथा अपने उच्च अधिकारियों के किसी विधि सम्मत और यथोचित आदेश की जानबृक्षकर अवज्ञा या आज्ञा का उल्लंबन करना।
- (7) पर्याप्त आधार अथवा उपयुक्त या सन्तोषजनक स्पष्टीकरण के बिना लगासार 4 से अधिक विनों तक छुट्टी के बिना अथवा मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक अबुषस्थित रहता।
 - (8) आधतन देर से आना और अनियमित उपस्थिति।
- (9) काम की उपेक्षा करना अथवा कार्य निष्पादन के प्रति लापरवाही बरहना जिसमें बीमारी का बहाना या धीरे काम करना भी शामिल है।
 - (10) निगम की किसी सम्पत्ति को क्षतित्रस्त करना।
- (11) निगम के परिसरों में या उसके आस पास लगे किसी सुरक्षा साधन को छेड़ना या उसमें कोई अनिधकृत विश्वर्तन करना।
- (12) निवम के परिसरों में अथवा ऐसे परिसरों के बाहर, जहां ऐसा व्यवहार नियोजन से सम्बन्धित हो, मदोन्मत्त वा उपद्रवी अथवा अव्यवस्थित या अशोभनीव व्यवहार करना। 4—239 QI/87

- (13) प्रतिष्ठान के परिसरों में जुआ खेलना।
- (14) प्रतिष्ठान के ऐसे परिसरों में, जहां ध्रुमपान निषेध हो, ध्रुम्प्रपान करना।
- (15) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना और तत्समय लागू किसी कानून या निगम के नियमों द्वारा मंजूर न होने पर निगम के परिसरों में धन एकब करना।
 - (16) डयूटी के समय सोना।
- (17) कोई ऐसा कार्य करना जो नैतिक अधमता से ग्रस्त दण्डनीय अपराध हो।
- (18) अनुमति या पर्याप्त कारण के बिना कर्मचारी का उसके नियुक्ति स्थान से अनुपस्थित होना ।
- (19) सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्पष्ट अनुमित के बिना निगम से सम्पत्ति, मशीनरी, माल, आदि खरीदना अधवा निगम को कोई सम्प्रत्ति, मशीनरी, माल आदि बेचना ।
- (20) अनुशासन या सदव्यवहार को भंग करने वासा कार्य।
- (21) किसी ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहित करने का प्रयास करना जो दुराचार के समान हो।

टिप्पणी—''दुराचार'' के उपर्युक्त दुष्टांत केवल उदाहरण स्वरूप है, विस्तृत नहीं।

61. दण्ड

किसी कर्मचारी द्वारा किये गये दुराचार अथवा किसी अन्य उचित और उपर्युक्त कारणों के सम्बन्ध में कर्मचारी पर निम्नालिखित दण्ड, इसमें इसके बाद की गई ब्यवस्था के अनुसार दिये जा सकते हैं:--

लघुदण्ड

- (क) भर्सना,
- (ख) वेतन वृद्धियों को संवयी प्रभाव सहिस या उसके बिना रोकना,
- (ग) पदोन्नति रोकना,
- (घ) लापरवाही या आदेशों के उल्लंबन से निगम को हुई धन सम्बन्धी किसी हानि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में, कर्मचारी के वेतन या उसे देय किसी राशि से कसूल करना।

भारी वण्ड

- (ड) निम्न ग्रेड या पद में पदादनत किया जाता,
- (च) समय मान में निम्न स्तर पर अवनत किया जाना,
- (छ) सेवा से हटाया जाना जिस्से भविष्य में नियोजन के लिये अयोग्यता नहीं माना जायेगा, और
- (ज) बरखास्तगी

स्पष्टीकरण—इस विनियम के अन्तगत निम्नलिखित को दण्ड के रूप में नहीं माना जायेगाः—

- (i) किसी कर्मचारी का कार्य सन्तोषजनक न पायें जाने या अपेक्षित स्तर का न होने पर, अथवा निर्धारित परीक्षा में उसीर्ण न होने के कारण उसकी वेतनवृद्धि रोकना
- (ii) दक्षतारोध पार करने में कर्मचारी के अनुपयुक्ता के कारण, समय मान में दक्षतारोध के समय उसकी वेतन वृद्धि रोकना;
- (iii) किसी कर्मचारी का उच्चतर पद पर, जिसके लिये, वह विचारार्थ पात्र हो लेकिन मामले पर विचार करने के बाद अनुपयुक्त पाया गया हो, स्थानापन्न हैसियत से अथवा अन्यथा, पदोन्नति न होना;
- (vi) उच्च ग्रेड या पद में स्थानापभ्र रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी की इस आधार पर ऐसे उच्च ग्रेड या पद के लिये, परीक्षण के बाद, अनुपयुक्त समझा गया हो अथवा ऐसे प्रशासनिक कारणों के आधार पर जो उसके दुराचार से सम्बन्धित न हों, निम्न ग्रेड या पद में पदावनति।
- (v) किसी अन्य ग्रेड या पद में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की, परिवीक्षा की अवधि के दौरन या उसके समाप्त होने पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर पदावनित ।
 - (vi) निम्नलिखित प्रकार से सेवा समाप्ति---
 - (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की, परि वीक्षा की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार;
 - (ख) संविदा या करार से भिन्न अन्यथा अस्थाई हैसियत में नियुक्त किसी कर्मचारी की, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उस अवधि के समाप्त होने पर, जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया था या उससे पहले;
 - (ग) संविदा या करार के अधीन नियुक्त कर्मचारी की, ऐसी संविदा या करार की गातों के अनुसार;
 - (घ) प्रतिष्ठान में कटौती के कारण;
 - (इ) किसी कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगना अथवा उसे उसके कार्य में सुधार लाने के लिये कहना; और
 - (च) अध्याय 11 के अधीन सेवा समाप्ति या सेवा निवृत्ति।
 - (vii) विनियम 64 के अधीन निलम्बन!
 - (viii) विनियम 33 के शधीन निगम द्वारा कर्मेचारी को सेवा निवृत्त किया जाना।
 - 62. दण्ड देने की प्रक्रिया
 - (क) भारी दण्ड
 - (1) विनियम 61 के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज) में विनिविष्ट भारी दण्ड लगाने का आदेश तब तक

- नहीं दिया जायेगा जब तक कि इस विनियम के अनुसार जांच नकी गई हो।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में किसी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचार या दुव्यंतहार के किसी आरोप की सत्यता की जांच का आधार है तो वह स्वयं उसकी जांच कर सकता है अथवा उसकी सत्यता की जांच करने के लिये निगम के किसी अधिकारी को (जिसे इसमें इसके बाद जांच प्राधिकारी कहा गया है) नियुक्त कर सकता है।
- (3) यदि किसी मामले में आंच करने का प्रस्ताय हो तो सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध गारोपों के आधार पर एक निश्चित आरोप पत्न तैयार करेगा । आरोप पत्न, उन आरोपों के विवरण सहित जिन पर वह आधारित है, दस्तावेजों और ऐसे साक्ष्यों की सूची जिनके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किये जाने का प्रस्ताव हो, कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा, जिस सक्षम प्राधिकारी, द्वारा यथानिर्धारित समय (15 दिन में अधिक नहीं) एक लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा कि वह आरोप पत्न की किसी अथवा सभी मदों को स्वीकार या अस्वीकार करता है।

स्पप्टीकरण—इस स्तर पर कर्मचारी गो आरोप-पन्न के साथ सूचीबद्ध दस्तावेज अथवा कोई अन्य दस्तावेज दिखाना आवश्यक नहीं है।

(4) कर्मचारी का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अथवा यदि निर्विष्ट समय में ऐसा कोई कथन प्राप्त न हो तो, सक्षम प्राधिकारी स्वयं अथवा उपर्युक्त उप-खण्ड (2) के ग्राधीन नियुक्त जांच प्राधिकारी इसकी जांच कर सकता है:

बशर्ते कि, कर्मचारी द्वारा उसके लिखित कथन में स्वीकार किए गए आरोपों के सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक न हो । किर भी, सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

- (5) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं जांच करता है या जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करता है तो, वह आदेश द्वारा निगम के किसी कर्मचारी की प्रस्तुती-करण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो उसकी ओर से आरोप-पन्न की मदों के समर्थन में मामले पेश करेगा।
- 62(क)(6) कर्मचारी निगम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है, परन्तु वह इस प्रयोजन के लिए किसी विधि-च्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता। परन्तु कर्मचारी ऐसे अन्य किसी कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा जिसके पास बचाव सहायक के रूप में पहले से ही दो मामले हाथ में हों।
- (7) जांच प्राधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख को कर्मचारी, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, स्थान और तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा। जांच प्राधिकारी कर्मचारी से पूछेगा कि क्या वह दोष स्वीकार करता है या कोई प्रतिवाद करना चाहता है और यदि वह किसी

आरोप के सम्बन्ध में दोष स्वीकार करता है तो, नियुक्ति प्राधिकारी उसके अभिकथन को रिकार्ड करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर सम्बन्धित कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाएगा। जांच प्राधिकारी उन दोषों के सम्बन्ध में निष्कर्ष का विवरण देगा, जिन्हें संबन्धित कर्मचारी स्वीकार कर लेता है।

- (8) यदि सम्बन्धित कर्मचारी दोष स्वीकार नहीं करता तो जांच प्राधिकारी मामले को, इस आणय का एक आदेश रिकार्ड करने के बाद कि संबन्धित कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता है, 30 (तीस) दिन से अधिक दिनों के लिए किसी अगली तारीख तक स्थिगत कर देगा—
 - (i) आरोप-पत्न के साथ सूचीबद्ध दस्तावेजों का निरीक्षण,
 - (ii) उन अतिरिक्त दस्तावेजों, जिनका वह निरीक्षण और जिन साक्ष्यों की पूछताछ करना चाहता है, उनकी सूची, और
 - (iii) आरोप-पत्न में सूचीबद्ध साक्ष्यों, यदि कोई हों, के अभिकथनों की प्रतियां उसे दी जाएं।
- टिप्पणी—सम्बन्धित कर्मचारी को उपर्युक्त उप-खण्ड 8 (11)
 में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेजों और साक्ष्यों
 की सम्बद्धता देनी होगी और यदि जांच प्राधिकारी जांच किए जा रहे आरोपों से उनकी
 सम्बद्धता के बारे में संतुष्ट होगा तो उन दस्तावेजों को मंगवाया एवं साक्षियों को बुलाया
 जायेगा।
- (9) जांच प्राधिकारी उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे जाते हैं, यथा विनिर्दिष्ट तारीख को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।
- (10) जिस प्राधिकारी की अभिरक्षा या कब्जे में अधिगृहीत बस्तावेज हों, वह उन्हें, मांग नोटिस में विनि-दिष्ट तारीख, स्थान और समय पर जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा बंशर्ते कि जिस प्राधिकारी की अभिरक्षा या कब्जे में अधिगृहीत बस्तावेज हों वह इस विशेषाधिकार का दावा कर सकता है कि क्या ऐसे बस्तावेजों को पेश करना सार्वजनिक हित अथवा निगम के हित के विषद्ध तो नहीं होगा। उस स्थित में वह जांच प्राधिकारी को तबनुसार सूचित करेगा।
- (11) जांच के लिए नियत की गई तारीख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जायेंगे जिनके द्वारा आरोपों की प्रामाणिकता सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से साक्ष्यों की जांच की जायेगी तथा कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसकी प्रति जांच की जा सकती है। प्रस्तुतीकरण अधिकारी को, जांच प्राधिकारी की अनुमित के बिना साक्षियों की, किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर उनको प्रति-जांच की जा चुकी है

- लें किन किसी नये विषय पर नहीं, पुनः जांच करने का हक होगा । जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है जैसे वह उचित समझे ।
- (12) जांच प्राधिकारी, अभियोजन का मामला बन्द करने से पहले अपनी स्वैच्छा से, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को आरोप-पन्न में सम्मिलित न किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है अथवा वह स्वयं किसी नए साक्ष्य की मांग कर सकता है अथवा किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है या उनकी पुनः जांच कर सकता है। ऐसे मामले में, कर्मचारी को, दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड में लिए जाने से पूर्व उसका निरीक्षण करने का; अथवा इस प्रकार बुलाए गए साक्षी की प्रति जांच करने का अवसर दिया जायेगा।
- (13) जब सक्षम प्राधिकारी के लिए मामला बन्द कर दिया जाता है तो कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक या लिखित रूप में, जिसे वह वरीयता दे, बयान देने के लिए कहा जा सकता है। यदि बयान मौखिक रूप से दिया जाता हैं तो इसे रिकार्ड किया जायेगा तथा कर्मचारी को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। दूसरी स्थिति में प्रतिरक्षा के बयान की एक प्रति प्रस्तुतीकरण-अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जायेगी।
- (14) तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। कर्मचारी यदि चाहे तो स्वयं अपनी ओर से जांच कर सकता है। तब कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों की जांच की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में साक्षियों पर लागू उपबन्धों के अनुसार जांच प्राधिकारी द्वारा उनकी प्रति जांच, पुन! जांच और जांच भी की जा सकेगी।
- (15) कर्मचारी द्वारा उसका मामला बन्द किए जाने के पश्चात्, यदि कर्मचारी ने स्वयं जांच न की हो तो जांच प्राधिकारी उसे आम-तौर पर उन परिस्थितियों के बारे में पूछ सकता हैं जो उसके विरुद्ध प्रमाण के रूप में हैं ताकि कर्मचारी उसके विरुद्ध होने वाली किसी परिस्थिति के प्रमाण को स्पष्ट कर सके।
- (16) साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण पूरा होने के बाद, कर्मचारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी, साक्ष्य का प्रस्तुती-करण पूरा होने के 15 दिन के भीतर अपने-अपने मामलों का लिखित संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (17) यदि कर्मचारी खण्ड (3) में उल्लिखित प्रति-रक्षा का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजन के लिए विनि-दिष्ट तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत नहीं करता अथवा स्वयं या अपने सहायक अधिकारी के माध्यम से उपस्थित नहीं होता या इन विनियमों के किसी उपवन्ध का अन्यथा पालन नहीं करता या करने से इनकार कर देता है तो, जांच प्राधिकारी एकपकीय जांच कर सकता है।
- (18) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी, किसी जांच के मामले में पूर्ण या श्रांशिक साक्ष्च की सुनवाई करने श्रीर

उसे रिकार्ड करने के बाद उसमें श्रधिकारिता का प्रयोग नहीं कर पाता और उसके स्थान पर कोई श्रन्य आंच श्राधि-कारी श्राता है जिसे ऐसी श्रधिकारिता प्राप्त है और जो उसका प्रयोग करता है, तो इस प्रकार बाद में श्राने वाला जांच प्राधि-कारी श्रपने पूर्वाधिकारी द्वारा इस प्रकार रिकार्ड किए गए श्रथका श्रांशिक रूप से श्रपने पूर्वाधिकारी द्वारा श्रौर श्रांशिक रूप से स्वयं रिकार्ड किए गए साक्ष्य के श्राधार पर कार्य-वाही कर सकता है।

बंशतें कि यदि बाद में झाने वाले जांच प्राधिकारी का मत हो कि न्यायहिस में किसी ऐसे साक्षी की और जांच करना श्रावण्यक है जिसका साक्ष्य पहले ही रिकार्ड कर लिया गया है, तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है, प्रति जांच कर सकता है तथा पुनः जांच कर सकता है। जैसी की इसमें पहले व्यवस्था की गई है।

- (19) (i) जांच कार्य समाप्त होने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:--
 - (क) ध्रारोप की मदों का सारांग और दुराचार या दुर्व्यवहार के श्रभ्यारोपण का विवरण;
 - (ख) ध्रारोप की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में कर्मचारी की प्रतिरक्षा का विवरण;
 - (ग) ग्रारीप की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में साक्ष्य का एक मूल्यांकन; और
 - (ध) श्रारोप की प्रत्येक मद का निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण—यदि जांच प्राधिकारी के मत में जांच की कार्यवाही से, ब्रारीप की मूल मदों से भिन्न ब्रारीप की कोई मद सिद्ध होती है तो, वह ब्रारीप की ऐसी मद पर श्रपने निष्कर्ष रिकार्ड कर सकता है।

समार्ते कि आरोप की ऐसी मद के सम्बन्ध में निष्कर्ष तक्ष तक रिकार्ड नहीं किये जायेंगे जब तक या तो कर्मधारी उन तथ्यों को स्वीकार न कर ले जिन पर आरोप की ऐसी मद आधारित हो प्रथवा आरोप की ऐसी मद के विरुद्ध उसे स्वयं अपनी प्रतिरक्षा का समुचित श्रदसर न दिया गया हो।

- (ii) जिस मामले में जांच प्राधिकारी स्वयं सक्षम प्राधिकारी न हो उसमें वह सक्षम प्राधिकारी को जांच का रिकार्ड प्रेषित करेगा जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:—
 - (क) उपर्युक्त खण्ड (i) के श्रन्तर्गत उसके द्वारा तैयार की गई जांच की रिपोर्ट;
 - (ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई खण्ड (13) में उल्लिखित, यदि कोई हो, का लिखित क्यौरा;
 - (ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;
 - (ध) खण्ड (16) में वर्णित लिखित सारांश, यदि कोई हो; और

(ङ) जांच के बारे में सक्षम प्रौधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा दिए गए क्यादेश, यदि कोई हों।

(ख) जांच रिपोर्ट पर कार्रक्षाई:

- (1) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी न हो तो, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, दोबारा या ध्रागे जांच के लिए और रिपोर्ट के लिए मामले को जांच प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा जांच प्राधिकारी उसके बाद, जहां तक हो सके, उप-विनियम (क) के उपबन्धों के ध्रमुसार ध्रागे जांच के लिए कार्यवाही करेगा।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी, आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के सम्बन्ध में अपने कारण रिकार्ड करेगा और उस ग्रारोप पर ग्रंपने स्वयं के निष्कर्ष देगा, यदि उस प्रयोजन के लिए उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त हों।
- (3) यदि धारोप की सभी ध्रथवा किसी मद्य के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी का मत है कि कर्म-चारी पर विनियम 61 में विनिर्दिष्ट कोई ध्रथंदण्ड लगाया जाना चाहिए तो, वह उप-विनियम (ग) में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा दण्ड लगाने का धादेश करेगा।
- (4) यदि प्रारोप की सभी प्रथवा किसी मद के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी का मत है कि कोई वण्ड प्रावश्यक नहीं है तो वह सम्बन्धित कर्मचारी को दण्ड से मुक्त करने का प्रादेश पारित कर सकता है।

(ग) लघुदण्ड

- (1) यदि विनियम 1 के खण्ड (क) से (छ) में विनिदिव्द कोई लघु दण्ड लागू करने का प्रस्ताव हो तो, सम्बन्धित कर्मचारी को उसके विरुद्ध दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोप की लिखित सूचना दी जायेगी और 15 दिन से अनिधक विनिदिव्द अविध में उसकी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी, आदेश पारित करने से पूर्व कर्मचारी द्वारा उसकी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किये गये लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।
- (2) कार्य विवरण के रिकार्ड में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल किये जायेंगे:--
 - (i) कर्मचारी को प्रेषित, दुराचार, दुर्घ्यवहार के आरोपों के विवरण की एक प्रति;
 - (ii) उसका अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किया गया कथन यदि कोई हो; और
 - (iii) कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी का आदेस ।

(ध) आदेशों की सूचना देना

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-विनियम (क) और (ग) के अन्तर्गत विये गये आदेशों की सूचना सम्बन्धित कर्मचारी

को दी आयेगी और उसे जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की एक प्रति भी दी जायेगी।

(ड) कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया

उप विनियम (क), (ख) या (ग) में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी निम्निलिखित किसी भी परि-स्थिति में विनियम 61 में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड दे सकता है——

- () जब कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप अथवा न्यायिक जांच द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों या निष्कर्षों के आधार पर दोर्षः ठहराया गया हो; या
- (ii) जब सक्षम प्राधिकारी आश्वस्त हो कि इस विनियम में दिये गये छंग से जांच करना यथोचित रूप से व्यवहार्य नहीं है, जिसके सम्बन्ध में कारणों को वह लिखित रूप में रिकार्ड करेगा; अथवा
- (iii) जब कोई आश्वस्त हो कि निगम की सुरक्षा के हित में, इस विनियम में निर्धारित ढंग से जांच करना समीचीन नहीं है।
- (च) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदि से प्रति-नियुक्ति पर आये कर्मचारी
 - (1) यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार, अथवा किसी अग्य सरकारी उपक्रम, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण से निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये किसी कर्मचारी को निलम्बन के आदेश दिये गये हों अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसकी सेवायें प्रदान करने वाले प्राधिकरण (यहां इसके बाद "प्रदाता प्राधिकरण" कहा गया है) को, यथास्थिति उसके निलम्बन आदेश अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से संबन्धित परिस्थितियों से तत्काल अवगत करवाया जायेगा।
 - (2) कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्य-वाही के निष्कर्षों के अनुसार--
 - (क) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि उस पर कोई लघु दण्ड लगाया जाना चाहिये तो वह प्रदाता प्राधिकरण मे परामर्श के बाद, यथावश्यक समझे गये आदेश पारित कर सकता है। परन्तु, सक्षम प्राधिकारी तथा प्रदाता प्राधिकरण के बीच मतभेद की स्थिति में कर्मचारी की सेवायें प्रदाता प्राधिकरण को सेवायें प्रदाता प्राधिकरण को सौंप दी जायेगी।
 - (ख) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि उस पर कोई भारी दण्ड लगाया जाना चाहिये तो उसकी सेवायें पुनः प्रदाता प्राधिकरण को सौंप

- दे तथा उसके (प्रदाता प्राधिकरण) द्वारा यथावश्यक समझी गई कार्रवाई के लिये उसे जांच की कार्यवाही हस्तान्तरित कर दे।
- (3) यदि कर्मचारी खण्ड 2(क) के अन्तर्गत उस पर लघु दण्ड लगाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है, इसका निपटान प्रदाता प्राधिकरण से परामर्श के बाद किया जायेगा। परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकारी और प्रदाता प्राधिकरण के बीच मतभेद हो तो कर्मचारी की सेवायें प्रदाता प्राधिकरण को सौंप दी जायेगी और उसके (प्रदाता प्राधिकरण) द्वारा यथावश्यक समझी गई कार्रवाई के लिये उसे मामले की कार्यवाही हस्तान्तरित कर वी जायेगी।

63. सामूहिक जांच

जब दो या दो से अधिक कर्मचारी एक ही मामले से सम्बन्धित हों तो ऐसे सभी कर्मचारियों पर भारी दण्ड लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी आदेश पारित कर सकता है जिसमें निदेश दिया जायेगा कि उन सबसे विरुद्ध सामूहिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

टिप्पणी—यदि ऐसे कर्मचारियों पर भारी दण्ड लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी अलग अलग हैं तो उनमें से सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा, सामूहिक कार्यवाही में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये आदेश दिया जा सकता है।

- 64. निलम्बन और निलम्बन के दौरान पारिश्रमिक
 - (क) निलम्बन
- (1) सक्षम प्राधिकारी या उस प्रयोजन के लिये बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त कोई अन्य प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है।
 - (क) यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो या विचाराधीन हो; अधवा
 - (ख) यदि किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी मामले की जांच की जा रही हो।
- (2) जिस कर्मचारी को आपराधिक आरोप के आधार पर या अन्यथा 48 घण्टे से अनिधिक अविधि के लिये हिरासत में ले लिया जाता है, उसे, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से, हिरासत में लिये जाने की तारीख से निलम्बत किया गया माना जायेगा और अगला आदेश होने तक वह निलम्बित रहेगा।
- (3) यदि किसी निलम्बित कर्मचारी पर लागू, सैवा से बरखास्त किये जाने या हटाये जाने का दण्ड, इन विनियमों के अधीन अपील पर अथवा पुन रीक्षण के आधार पर रह् कर दिया जाता है और मामले में आगे जांच या कार्रवाई के लिये अथवा किसी अन्य निवेश के साथ स्थिगत कर दिया जाता है तो, उसके निलम्बन के आदेश की, बरखास्तगी या

हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख को और उस तारीख से लागू माना जायेगा और अगला आदेश होने तक लागू रहेगा।

- (4) जिस मामले में कर्मचारी पर बरखास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने का दण्ड, विधि न्यायालय के निर्णय प्रथवा इसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप रद्द अथवा अवैध घोषित कर दिया जाये और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर सक्षम प्राधिकारी उसके विकत्न उन दोषारोपणों पर ग्रागे जांच करने का निर्णय लेता है जिनसे मूलतः बरखास्तगी अथवा सेवा से हटाने का दण्ड लगाया गया था तो कर्मचारी को बरखास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया हुआ माना जायेगा और वह आगाभी आदेशों तक निलम्बित रहेगा।
- (5) इस विनियम के स्रधीन दिया गया स्रथदा दिया माना गया निलम्बन का स्रादेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा रह किया जा सकता है जिसने वह स्रादेश दिया हो स्रथदा जिसके द्वारा वह स्रादेश दिया माना गया हो।

ं परन्तु, फिर भी श्रेणी I और II के कर्मचारी के मामले में इस प्रकार परिकलित निर्वाह भर्ते और श्रन्य भर्तों का जोड़ उसके मूल वेतन से कम नहीं होगा परन्तु श्रेणी III ग्रीर IV के कर्मचारियों के मामले में निर्वाह भर्ता, पहले छ: महीने के लिये मूल वेतन और उसके 25% तथा श्रगले छ: महीने के लिये मूल वेतन और उसके 50% के बराबर होगा। यदि जांच कार्यवाही, कर्मचारी को निलम्बित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती तो एक वर्ष के बाद की श्रविध के लिये निर्वाह भर्ते की दर, मूल वेतन और उसका 75% होगी।

- (2) यदि श्रेणी I और 11 के कर्मचारी के मामले में निलम्बन की अविध छ: महीने से श्रिधिक हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी पहले छ: महीने की श्रविध के बाद की किसी भी अविध के सम्बन्ध में निर्वाह भत्ते में निम्नानुसार परिवर्तन कर सकता है:—
 - (i) यदि सक्षम प्राधिकारी के मत में निलम्बन की प्रविध उन कारणों से (लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने वाले) चढ़ गई हो, जिनके लिये निलम्बित कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार न हो तो निर्वाह भत्ते की राशि को मूल वेतन और भत्तों की 75 प्रतिशत माझा तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) निलम्बन के दौरान पारिश्रमिक

(i) निलम्बित कर्मचारी श्रयने मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर निर्वाह भत्ता लेने का हकवार होगा बगर्ते कि सक्षम प्राधिकारी श्राश्वस्त हो कि कर्मचारी किसी श्रन्य रोजगार या कारोबार या व्यवसाय या धन्धे में नहीं लगा हुआ। इसके भतिरिक्त, वह ऐसे निर्वाह भक्ते पर स्वीकार्य महंगाई भता श्रीर कोई श्रन्य प्रतिपूरक भक्षा लेने का भी हकदार होगा जो उसे निलम्बन की तारीख को प्राप्त होता था, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी श्राश्वस्त हो कि कमचारी उसी उद्देश्य के लिये खर्च करता है जिसके लिये उसे भक्षा प्रदान किया गया था।

- (ii) यदि सक्षम प्राधिकारी के मत में निलम्बन की भ्रविध उन कारणों से (लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने वाले) बढ़ गई जिनके लिये निलम्बित कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो, तो निर्वाह भत्ते की राशि को मूल बेतन भ्रीर भत्तों की 25 प्रतिशत मान्ना तक का किया जा सकता है।
- (3) यदि किसी कर्मचारी को दण्डनीय ध्रारोप के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है ध्रीर जमानत नहीं दी जाती तो उसे कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी निलम्बन की स्थिति को जारी रखने का निर्णय करता है तो जमानत दिये जाने पर कर्मचारी उस तारीख से निर्वाह भत्ते का हकदार होगा जिस तारीख से उसकी जमानत दी गई हो।

(ग) निलम्बन की भ्रवधि का नियमन

- (1) निलम्बित कर्मचारी को पुनः नियुक्त किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी, उसे निलम्बन की भ्रवधि में निम्नलिखित वेतन भौर भत्ते प्रदान कर सकता है—
 - (1) यदि कर्मचारी को दोष मुक्त कर दिया जाता है ग्रीर विनियम 61 में उल्लिखित कोई दण्ड नहीं लगाया जाता तो उसे पूरा वेतन भौर भत्ते जिनका वह तब तक हकदार होगा यदि उसे निलम्बित न किया गया होता, में से निर्वाह भत्ता घटाकर भुगतान किया जायेगा।
 - (2) यदि भ्रन्यथा स्थित हो तो बेतन और भत्तों का उतना भनुपात दिया जायेगा जो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे।
- (2) उप-खण्ड (i) के अन्तगत श्राने वाले किसी मामले में ड्यूटी से श्रनुपस्थिति की श्रविध को डयूटी पर बिताई गई श्रविध के रूप में माना जायेगा। उप-खण्ड (ii) के श्रन्तगत श्राने वाले किसी मामले में इसे तब तक डयूटी पर बिताई गई श्रविध के रूप में नहीं माना जायेगा जब तक कि सक्षम श्राधिकारी ऐसा निदेश न दे।

खण्ड II ध्रपील

65. भ्रपील का भ्रधिकार

विनियम 61 में निर्विष्ट दण्डों में से किसी भी वण्ड के ग्रिधिरोपण के विरूद, कोई भी कर्मचारी, इसमें धागे उल्लिखित धनुसार, विनियम 66 से 72 तक के प्रावधानो के श्रधीन, ग्रपीलीय प्राधिकारी को भ्रपील करने का हकवार होगा। 66. श्रपीलीय प्राधिकारी श्रपील की जा सकेगी---

- (क) श्रेणी 1 के पदों के मामले में बोर्ड की,
- (ख) श्रन्य कर्मैचारियों के मामले में श्रध्यक्ष की।

परन्तु कोई भी भ्रपील निगम के बोर्ड के संचालकों को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित नहीं होगी तथा ऐसी कोई भी कार्यवाही श्रनुशासन का उल्लंबन समझी जायेगी।

67. भ्रपील करने के लिये सीमा भ्रवधि

किसी भी ऐसी भ्रपील पर तब तक विचार नहीं किया आयेगा, जो कि उस भ्रादेश की तारीख से 6 मास की भ्रविध के भीतर न की गई ही जिसके विश्व अपील की गई हैं।

परन्तु, यदि ग्रपीलीय प्राधिकारी ग्राध्वस्त हो जाता है कि सम्बन्धित कर्मचारी के पास उस ग्रवधि के भीतर ग्रपील न करने का तर्कसंगत अथवा प्रयाप्त कारण था तो वह उक्त ग्रवधि के समाप्त होने पर भी ग्रपील पर विचार कर सकता है।

68 अपील के लिये अपेक्षित शर्ते

(1) भ्रपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक कर्मचारी पृथक ग्रीर भ्रपने नाम से अपील करेगा।

परन्तु, विनियम 62 के अन्तर्गत दो अथवा अधिक कर्मेचारियों के विरुद्ध संयुक्त जांच के अनुसरण में पारित किये गये समेकित आदेश के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी की स्वविवेक से सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम से संयुक्त अपील की अनुमति दे सकता है।

- (2) प्रत्येक श्रपील, उस प्राधिकारी को सम्बोधित की जायेगी जिसे श्रपील की जानी है और उसमें निम्नलिखित श्रपेक्षाश्रों का पालन होगा—
 - (क) वह निगम की राजभाषा में लिखी हुई होगी प्रथवा यदि वह उस भाषा में नहीं लिखी गई है तो उसके साथ, निगम की राजभाषा में उसकी ग्रनूदित प्रति संलग्न होगी तथा सम्बन्धित कर्मचारी/ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी,
 - (ख) वह संक्षिप्त होगी, उसमें किसी प्रकार की श्रनादरणीय श्रथवा श्रनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा, तथा श्रनावश्यक बातों श्रथवा श्रत्यधिक शब्दाउम्बर से मुक्त होगी,
 - (ग) यह सुपाठ्य और सुबोध होगी चाहिये,
 - (घ) उसमें सभी तथ्यात्मक विवरण धौर विश्वसनीय तर्क होंगे तथा वह श्रपने श्राप में पूर्ण होगी,
 - (क) उनमें भ्रपेक्षित राहत का स्पष्ट उल्लेख होगा,
 - (भ) वह उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी,

69 श्रपीलें कब रोकी जा सकती हैं

- (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखिन स्थितियों में प्रपील रोकी जा सकती है यदि—
 - (क) उसमें विनियम 67 स्रौर 68 की स्रपेक्षास्रों का अनुपालन न किया गया हो या वह उनके अनुरूप न हो,
 - (ख) उसका विषय व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से सम्बन्धित न हो,
 - (ग) उसमें वही अपील दोहराई गई हो जिसका पहले ही विधिवत् निर्णय कर लिया गया है ग्रीर सक्षम प्राधिकारी के विचार से उसमें कोई ऐसे नये तथ्य या परिस्थितियां या मूहे न हों जिनके ग्राधार पर मामले परपुन: विचार किया जा सके,
 - (घ) वह ऐसे मामले में लिये हो, जिसके लिये इन विनियमों के ग्रधीन ग्रपील का ग्रधि-कार नहीं है।
- (2) इस विनियम के प्रधीन रोकी गई श्रपील के प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी या कर्मचारियों को श्रपील रोकने के तथ्य तथा कारणों की सूचना देगा—

परन्तु यदि भ्रपील केवल इसलिये रोकी गई है कि, उसमें विनियम 68 के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया हो तो सम्बन्धित कर्मचारी को भ्रपील रोकने की सूचना देने के एक मास के भीतर भ्रपील पुनः की जा सकती है श्रीर जब वह उक्त उपबन्धों के श्रनुरूप पुनः प्रस्तुत की जाय तो, उसे रोका नहीं जायेगा।

70 प्रपीलीय प्राधिकारी को श्रपील यथाशीझ भेजी जाये

सक्षम प्राधिकारी, विनियम 69 के अन्तर्गत न रोकी गई प्रत्येक अपील, परिहार्य विलम्ब के बिना, अपील प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। इस प्रकार प्रेषित प्रत्येक अपील के साथ, आरोपित तथ्यों तथा अपील के पक्ष में दिये गये आधारों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणियां अथवा अभिमत संलग्न होंगे।

71. अपीलों पर विचार

- (1) विनियम 61 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) से (छ) में उल्लिखित कोई भी दण्ड लागू करने वाले किसी भी आदेश के विरुद्ध की गई अपील की मामले में अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा:--
 - (क) क्या इन विनियमों में विहित प्रिक्रिया का पालन किया गया है और यदि नहीं तो इस प्रकार अनुपालन न किये जाने के परिणामस्थरूप अन्याय तो नहीं हुआ है।
 - (ख) क्या सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष न्यायोचित है।

- (ग) क्या अधिरोपित दण्ड अधिक, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है, और
 - (i) दण्ड को रद करने, कम करने, उसकी
 पुष्टि करने अथवा उसमें वृद्धि करने के
 आदेश पारित करेगा. अथवा
 - (ii) मामले में नये सिरे से अथवा आगे जांच के लिये सक्षम प्राधिकारी के पास वापस भेजेगा और उसे ऐसे निदेश देगा जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

परन्तु बढ़ाये गये दण्ड का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित कर्मचारी को इस प्रकार बढ़ाये गये दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया हो।

- (2) किसी भी अन्य आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि वह न्यायोचित तथा सम्यक् समझे।
- (3) इस विनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों को सक्षम प्राधिकारी लागू करेगा।
- 72. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश अथवा अपील रोकने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

किसी भी कर्मचारी को विनियम 71 के अन्तर्गत पारित किसी आदेश अथवा विनियम 69 के अन्तर्गत अपील को रोकने के आदेश के विरूद्ध, अपील करने का अधिकार नहीं होगा।

73. संयुक्त याचिकार्ये

विनियम 66 से 71 के उपबन्ध उस सीमा तक उन याचिकाओं पर भी लागू होंगे, जो एक से अधिक कर्मचारियों से सम्बन्धित हों तथा एक श्रेणी के कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के समूह अथवा निगम द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई हों संयुक्त याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा, यवि—

- (क) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिस पर अध्यक्ष अथवा महाप्रवन्धक आदेश पारित करने में सक्षम हो और निवारण हेतु उसे कोई आवेदन न किया गया हो;
- (ख) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसके निवारण के लिये निगम द्वारा जारी किए किसी विनियम/आदेश के अन्तर्गत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई हो;

अथवा

(ग) वह किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है जो याचिका में सम्मिलित नहीं है। 74. सक्षम प्राधिकारी के बाद में अपीलीय प्राधिकारी बन जाने पर प्रावधान

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी जब कोई व्यक्ति, जिसके आदेश के विकद्ध अपील की गई है, उसकी अनुवर्ती नियुक्ति के कारण अथवा अन्यथा ऐसे आदेश के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी बनता है तो वह व्यक्ति उस अपील को उस प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जिसका वह आसम्न अधीनस्थ है और इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उस अपील के सम्बन्ध में उक्त प्राधिकारी ही अपीलीय प्राधिकारी माना जायेगा।

75. अस्थाई कर्मचारियों, प्रतिनियुक्ति पर कर्म<mark>चारियों, आदि</mark> पर इस अधयाय का लागू होना

इन विनियमों के अन्य उपबन्धों अथवा उनकी नियुक्ति की शतों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना इस अध्याझ के उप-बन्ध अस्थाई कर्मचारियों, अंश-कालिक कर्मचारियों सथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों, स्थानीम प्राधिकरणों आदि से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों पर लागू होंगे।

अध्याय V

वेतन एवं भक्ते, वेतनवृद्धियां, रियायतें, गुल्क तथा देय राशियां आदि

खण्ड I--सामान्य शते

76 अन्य अध्यायों का अध्यारोही प्रभाव

इस अध्याय के उपबन्ध इन विनियमों के अन्य उपबन्धों की शर्तों के अधीन प्रभावी होंगे।

- 77. मूल नियुक्तियां और पद घारण करना
- (1) किसी पद पर उसकी मूल नियुक्ति के कारण अथवा किसी संवर्ग में उसकी मूल स्थिति के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी, जबकि वह उस पद पर कार्यरत हो अथवा किसी अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण अविधि में हो और जब वह निम्नलिखित स्थितियों में न हो तो परावर्तन के पद पर, निर्दिष्ट पदों में से एक पद धारण करेगा:—
 - (क) निलम्बन के अधीन, अथवा
 - (ख) आकस्मिक अवकाण के अतिरिक्त किसी अन्य अवकाण पर, या बाह्य सेवा में प्रतिनिधुक्ति पर, अथवा
 - (ग) अस्थाई पद धारण करने अथवा ग्रन्य पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति पर ।

परन्तु यदि ऐसा कर्मचारी मूल रूप से निम्न पद या निम्न वेतन वाले पद अथवा ग्रेड में स्थानान्तरित कर दिया गया हो तो वह स्थानान्तरित पद के अपने कर्त्तव्य से कार्य-मुक्त होने की तारीख से अगले दिन से उक्त पद क्रोधारण करेगा।

- (2) उप विनियम (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार पद धारण करने पर कर्मभारी उसके द्वारा इससे पूर्व इसी प्रकार धारित अन्य किसी पद पर नहीं रहेगा।
- (3) किसी कर्मचारी द्वारा इस विनियम में यथा उपबन्धित, धारित पद का ग्रेड ही तत्समय उसका मूल ग्रेड माना जायेगा।
- 78. दो व्यक्ति एक ही पद का वेतम तथा भत्ते नहीं लेंगे

जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, एक ही समय में किसी पद विशेष के लिये दो व्यक्ति बेतन सथा भक्ती नहीं लेंगे।

79. वेत'न एवं भत्ते किस स्थिति में महीने के किसी भाग के लिए संदेय नहीं होंगे

कोई भी कर्मचारी को विनियम 27 द्वारा यथा अपेक्षित नोटिस विसे बिना किसी कैलैण्डर मास में अपनी सेवायें छोड़ अथवा समाप्त कर वेता है, उसे कैलैंण्डर मास के भाग के लिसे कोई वेतन तथा भत्ते तब तक अदा नहीं किसे जायेंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस से छूट नहीं दे दी जाती।

खण्ड II--वेतन और भत्ते

80. वेतम और मत्ते

जब तक कि इन विनियमों में अत्यथा व्यवस्था न की गई हो, कर्मधारी का वेतन और भक्ते, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित होंगे तथा वे केबल उन कर्मचारियों को संदेम होंगे जो सम्बद्ध समय में वे शर्ते पूरी करते हैं जिनके अधीन वेतन और भक्ते तत्समय अनुमत्य हों।

81. वेतन और भक्ते कब प्रोद्भूत और संदेय होंगे

- (1) उप-विनियम (2) तथा विनियम 82 के अधीन, कर्में चारी का वेतन और भरों उसकी सेवारम्भ होने से प्रोद्भूत होंगे, वेतन और भत्ते आम तौर पर प्रयेक कैलैण्डर मास में उस महीने के अन्तिम कार्य दिवस को अपराह्म में संदेय हैं।
- (2) जब तक कि अन्यथा विशिष्ट रूप से उल्लिखित न हो, जब कोई कर्मचारी किसी अन्य पद पर नियुक्त हो जाता है अथवा एक पद से दूसरे पद परस्थानान्तरित होता है या उक्त ग्रेड था नियुक्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है अथवा अन्य नियोक्ता के अन्तर्गत सेवा हेतु प्रतिनियुक्त होता है तो जिस पद पर वह नियुक्त/स्थानान्तरित अथवा प्रतिनियुक्त हुआ है उसके लिये, उसके वेतन तथा भत्ते उस तारीख से प्रोद्भूत होने प्रारम्भ होंगे जिस तारीख से वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, यदि वह उस तारीख को पूर्वाह्म में कार्यभार ग्रहण करता है तो उस दिन से उसका वेतन तथा भत्ते प्रोद्भूत होने प्रारम्भ होंगे, और यदि उस दिन अपराह्म में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसका वेतन तथा भत्ते प्रोद्भूत होने प्रारम्भ होंगे।

82. वेतन कवेरभत्तों के गणन की विधि

वेतन और भत्तों का गणन उस अवधि के लिये जिसके लिये वे सन्देय है, कर्मचारी द्वारा धारण किये गये पद में की गई सेवा तथा उस सेवा के दौरान लागू ग्रेड में संदर्भ में किया जायेगा।

83. स्थानान्तरण, आदि होने पर कर्मचारियों के वेतन और भक्ते

जब कोई कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित होता है तो पुराने पद का कार्यभार देने सथा नये पद का कार्यभार लेने की तारीख के मध्य इ्यूटी पर न होने की अवधि में वह पुराने अथवा नये पद में से जिसके भी वेतन और भत्ते कम होंगे, लेगा ।

- 84. परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर वेतन का पुनर्निर्धारण
 - (i) एक ग्रेंड से दूसरे ग्रेंड में परिषीक्षा पर नियुक्त कर्में थारी का वेतम आरम्भ में, उच्चतर ग्रेंड के वेतममान में न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा तथा इस प्रकार निर्धारित वेतन और पुराने वेतनमान में कर्मचारी के मूल वेतन, यदि वह अधिक हो, के बीच अन्तर को वैयक्तिक वेतम के रूप में माना जायेगा।

पुष्टीकरण होने पर

(ii) उच्चतर ग्रेड में पुष्टीकरण होने पर किर्मचारी का वेतन, उच्चतर ग्रेड में उस अवस्था से अगली अवस्था पर निर्धारित किया जायेगा जिस पर पुष्टीकरण की तारीख को पुराने वेतनमान में कर्मचारी वेतन प्राप्त कर रहा है, यदि कर्मचारी द्वारा पुष्टीकरण के समय प्राप्त वेतन से उक्त वेतन उच्चतर है।

84क. स्थानापन्न वेतन

- (1) निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विशेष या सामान्य श्रनुदेशों के श्रधीन कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, उप-विनियम (2) श्रीर (3) में उल्लिखित ढंग से निर्धारित शिया जाएगा।
- (2) उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर्मचारी, इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर पुराने वेतनमान
 में उसके मूल वेतन और जिस पद पर वह नियुक्त
 किया गया है उसके वेतनमान के उस स्तर पर जो पुराने वेतनमान में उसके मूल वेतन से ग्रगला हो, के बीच ग्रन्तर के
 बराबर स्थानापन्न वेतन प्राप्त करेगा ग्रथवा यदि वह पहले
 ही मध्यवर्ती ग्रेड में स्थानापन्न हैं, तो वह मध्यवर्ती ग्रेड में
 उसे प्राप्त वेतन ग्रीर जिसे पद पर वह ग्रथ नियुक्त है उसके
 वेतनमान के उस स्तर पर जो मध्यवर्ती ग्रेड में वेतन से ग्रगला
 हो, के बीच ग्रन्तर के बराबर स्थानापन्न वेतन प्राप्त करेगा;
 परन्तु यह कि यदि पदोन्नित ग्रस्थायी प्रकृति की हो और

पदोन्नित की परिस्थितियां उसका श्रौचित्य सिद्ध करती हो तो अध्यक्ष कर्मचारी का वेतन, इस विनियम के अन्तर्गत अनुमत्य राशि से कम राशि पर निर्धारित कर सकता है।

- (3) यदि उसे प्रत्यावर्तित किया जाता है भौर उस उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्त रूप से पुनित्युक्त किया जाता है तो उसका स्थानापन्त वेतन निर्धारित करने के लिए भौर विनियम 88 की व्यवस्थाओं के अनुसार स्थानापन्त ग्रेड में वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के लिए उसे धनुमति देने के लिए उच्चतर ग्रेड में उनकी पूर्ववर्ती स्थानापन्त सेवा को हिसाय में लिया जाएगा।
- (4) इस विनियम के उप-खण्ड (1) से (3) के प्राव-धानों में किसी बात के होते हुए भी निगम वेतन निर्धारण के लिए भिन्न प्रक्रिया ग्रपना सकता है जैसा कि निगम ग्रौर कर्मचारी एसोसिएसन ग्रादि के बीच पारस्परिक रूप से सहमति क्यक्त की गई है।

85. ठीक नीचे का नियम

जब कोई कर्मचारी उसकी ब्रकुशलता ब्रथवा ब्रनुप-युक्तता या उसके छुट्टी पर होने प्रथवा उसकी स्वेच्छा से स्थानापन्तः पदोन्नति के लिए मना करने से भिन्न अन्य किसी कारण से उच्च ग्रेड के पद पर स्थानापन्न रूप से नियक्त किए जाने से रोक दिया गया हो, तो उसे प्रत्येक प्रवसर के लिए ऐसे उच्च ग्रेड में लागू वेतन तथा भन्ते लेने के लिए भनुमति दी जा सकती है, जिसमें सेवा की ग्रनिवार्यता के कारण उसके संवर्गे ग्रौर समृह का उससे तुरन्त कनिष्ठ ग्रयवा यदि वह कर्मचारी उसकी अकुणलता प्रथवा अनुपयुक्ता या **उ**सके छुट्टी पर होने या उसकी स्वेच्छा से स्थानापन्त पदो-न्नति को मना करने के कारण उससे ग्रागे बढ़ गया हो, . तो उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी जो इस प्रकार धारे नहीं बढ़ा, छह मास से अनाधिक अवधि की रिक्ति में ऐसे उच्च ग्रेड में स्थानापन्त रूप से नियुक्त किया जाता है, भीर उसके वेतन तथा भर्ते प्राप्त करता है; बशर्ते कि इसे विनियम के मूल भाग के अन्तर्गत लाभ के लिए अनुमत्य कर्मचारी से बरिष्ठ सभी कर्मचारी भी उक्त उच्च ग्रेड के वेतन तथा भत्ते ले रहे हों, जब तक कि उपर्युक्त कारगों से कोई मन्य कर्म-भारी उनसे भागेन बढ़ गया हो।

परन्तु यह श्रौर कि इस विनियम के श्रन्तर्गत किसी एक स्थानापन्न रिक्ति के सम्बन्ध में एक से ग्रधिक कर्मचारी को ऐसे उच्च ग्रेड के वेतन ग्रौर भन्ने प्राप्त करने की ग्रनुमित न दी जाए।

86. एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में धन्तरण होने पर वेतन का पुत्रनिर्धारण

(1) जब कोई कर्मचारी एक वर्ग झथवा ग्रेड से झन्य वर्ग झथवा ग्रेड में झन्तरित झथवा नियुक्त होता है झौर इसके पुराने तथा नए पद के ग्रेड भिन्न हैं, तो नये पद में इसका मूल वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी निदेश दे। (2) जब कोई कर्मवारी एक ग्रेड से दूनरे ग्रेड में अन्तरित होता है श्रीर ऐसे अन्तरण में अधिक महत्व के कार्य या दायित्व निहित न हों तो, नये वेत नमान सें उसका प्रारम्भिक वेतन, पुराने वेत नमान में उसके मूल वेतन के समकक्ष स्तर पर होगा अथवा यदि नये वेतनमान में ऐसा कोई स्तर न हो तो उस वेतन से ठीक निम्न स्तर पर रहेगा, ग्रीर वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन के बराबर ऐसा वयक्तिक वेतन तब तक उसे मिलता रहेगा जब तक कि वह नए वैतनमान की अनुवर्ती वेतनवृद्धियों में न मिल जाए।

87. वेतन भौर भरी कब प्रोदभूत होने बन्द होंगे

ंकर्मचारी के वेतन ग्रौर भर्त उसके सेवा में न रहने की तारीख से प्रोद्भूत होने बन्द हो जायेगे ग्रौर संदेय नहीं होंगे:—

परन्तु यदि सेवा समाप्ति :---

- (क) कर्मचारी के निगम में उसकी सेवा छोड़ने ग्रथवा समाप्त करने के कारण हो ग्रौर इस प्रकार की समाप्ति किसी छुट्टी के दिन ग्रथवा उस दिन की समाप्ति पर हो, तो उसका वेतन ग्रौर भत्ते, पिछले कार्य-दिवस के कार्य-समापन के समय समाप्त हो जायेंगे।
- (ख) कर्मचारी की बरखास्तगी के कारण हो तो उसका वेतन ग्रीर भसे उसकी बरखास्तगी की तारीख से समाप्त हो जायेंगे।
- (ग) कर्मचारी की मृत्यु के कारण हो तो उसका वेतन छौर भत्ते उसकी मृत्यु होने के दिन से भ्रागामी दिन से समाप्त हो जायेंगे।

खण्ड III—वेत ₁'वृद्धियां

88. वेतनवृद्धियां कब प्रोव्भूत होंगी

(1) उप-विनियम (4) तथा विनियम 57 के धाधीन, वेतनवृद्धि वृद्धिशील वेतनमान सें, उस वेतनमान के प्रत्येक स्तर पर साधारणतया सेवा की प्रत्येक विभिष्ट प्रविध की समाप्ति पर प्रोद्भूत होंगी, चाहे ऐसी सेवा स्थायी, परिवीक्षाधीन अथवा स्थानापन हो।

परन्तु, कर्मचारी वेतनवृद्धि, प्रोवभूत होने की वास्तविक तारीख पर ध्यान दिए बिना उस मास की पहली तारीख को प्राप्त करेगा।

परन्तु फिर भी⊸–

- (i) ग्राकस्मिक ग्रवकाश को छोड़कर वितियम 103 में उल्लिखित ग्रन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के दौरान प्रोद्भूत होने वाली वेतनवृद्धि, उस ग्रवकाश से लौटने पर पुनः कार्य ग्रहण करने की तारीख से ही प्रवान की जायेगी;
- (ii) वण्ड के रूप में रोकी गई वेतन-वृद्धि केवल वण्ड समाप्त होने की तारीख से ही प्रवान की जायेगी; ग्रौर

- (1) कुछ निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रदान की गई प्राग्निम बढ़ाई हुई वेत त्वृद्धि की तारीख केवल सम्बद्ध नियमों तथा विनियमों द्वारा ही व्यवस्थित की जायेगी।
- (2) जब वेतन तथा भत्तों के बिना भ्रीर वेतनवृद्धि के लिए न गिने जाने वाले असाधारण भ्रवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप सामान्य वेतनवृद्धि भ्रास्थगित कर दी जाये, तो ऐसी भ्रास्थगित वृद्धि उसके वास्तव में देय होने की तारीख पर विचार किए बिना सम्बन्धित मास के प्रथम दिन से प्रदान की जायेगी भीर प्रारम्भिक नियुक्ति तथा/भ्रथवा उच्च पद पर पदोननति के मामले में मूल तथा/भ्रथवा स्थानापन्न पद में कोई भी वेतनवृद्धि, जिस मास में देय होगी उसके प्रथम दिन से प्रदान की जायेगी, वाहे 12 मास की सामान्य बेतनगृद्धि की भ्रवधि पूरी न हुई हो।
- (8) जब कर्मचारी उच्च ग्रेड में स्थानापन्त रूप से नियुक्त किया गया हो, तो उच्च ग्रेड में उसके द्वारा की गई सेवा, कर्मचारी के मूल ग्रेड के साथ ही उच्च ग्रेड में भी उप-वितियम (6) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में नहीं ली जायेगी, श्रौर यदि दोनों के बीच कोई ऐसा मध्यवर्ती ग्रेड हो, जिसमें वह स्थानापन्त रूप से नियुक्त था श्रयंवा भव स्थानापना रूप से नियुक्त या श्रयंवा भव स्थानापना रूप से नियुक्त हुआ होता यदि वह उच्चतर ग्रेड में स्थानापन रूप से नियुक्त न हुआ होता तो उस मध्यवर्ती ग्रेड में भी ऐसी स्थानापन्न सेवा को वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में लिया जायेगा।
- (4) जिस श्रवधि के धौरान कर्मचारी विना वेतन छुट्टी पर रहा हो, तो उस श्रवधि को वेतनवृद्धि के लिए तब तक हिसाब में नहीं लिया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधि-कारी द्वारा उसे वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में लेने का प्राधि-कार न दिया जाए श्रौर उसके कारण लिखित रूप में न विए गये हों।
- 89. किसी कर्मचारी के निम्न पद, भादि पर पदावनत् किए जाने से वेतन का समायोजन
- (1) अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में कर्मचारी को निम्न पद अथवा ग्रेड में अथवा उसके वृद्धिशील वेतनमान में निम्न स्तर पर पदावनत् करने के लिए इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में पदावनित के प्रभावी रहने की अवधि, निम्न स्तर या ग्रेड में प्रारम्भ में निर्धारित किए जाने वाला वेतन, निम्न पद, ग्रेड या स्तर में वेतनवृद्धि प्रोवभूत होने का समय और बहाल होने पर क्या आगामी वेतनवृद्धियां आस्थ- कित की जायेंगी, इन सब का उल्लेख होगा।
- (2) जब कर्मचारी की वेतनवृद्धि में विलम्ब करने ग्रथवा रोकने ग्रथवा निम्न पद ग्रथवा ग्रेड या उसके वृद्धि-शील वेतनमान में निम्न स्तर पर पदायनत् करने का दण्ड का ग्रादेश इन विनियमों के ग्राधार पर रद्द ग्रथवा संशोधित

- कर दिया जाता है तो कर्मचारी के वेतन श्रौर भत्ते निम्त-लिखित प्रकार से नियमित किए जायेंगे :---
 - (क) यदि उक्त ग्रावेण रह कर दिया जाता है तो, उस भवधि के लिए, जिस श्रविधि में वह ग्रावेश लागू था, उसे उस ग्रदेश के जारी न होने पर जिन वेतन भौर भत्तों का वह हकदार होता तथा जो वेतन ग्रीर भत्ते वह वास्तव में प्राप्त कर रहा है, इन दोनों का ग्रन्तर प्रवान किया जायेगा।
 - (ख) यदि उक्त ग्रादेश संशोधित किया जाता है, तो वेतन ग्रीर भत्ते इस प्रकार नियमित किए जायेंगे जैसा कि यदि इस प्रकार का संशोधित ग्रादेश पहले ही लागू कर दिए जाने पर होता।

90. स्थानापन्त ग्रेड में वेतनकृद्धियां

यदि उच्छतर ग्रेड में स्थानापन्न कर्मचारी, वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में न ली जाने वाली छुट्टी से भिन्न किसी भन्य छुट्टी पर जाता है, तो प्रत्येक भ्रवसर पर भ्रधिकतम 4 महीने की छुट्टी की ऐसी भ्रवधि को, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी भ्रवधि के रूप मे प्रमाणित किया जाए कि यदि उक्त कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाता तो उस भ्रवधि में स्थाना-पन्न रूप में कार्य करता, उच्चतर ग्रेड में भौर उसके मूल ग्रेड एवं उच्चतर ग्रेड, जिसमें वह स्थानापन्न था भ्रथवा स्थानापन्न होता, के बीच किसी मध्यवर्ती ग्रेड में वैतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार हिसाब सें लिया जायेगा जिस प्रकार उच्चतर ग्रेड में सिक्रय सेवा करने पर हिसाब में लिया जाता।

स्पष्टीकरण: — इस विनियम की सीमाश्रों और प्रपेक्षाश्रों के ग्रधीन, यदि इस विनियम के भ्रधीन वेतन-वृद्धियों के लिए गिनी जाने वाली छुट्टी के भ्रन्तिम विन के तुरन्त बाद कोई सार्वजनिक छुट्टी हो, तो ऐसी छुट्टी को इस गर्त पर वेतन-वृद्धि के लिए हिसाब में लिया जायेगा कि उस सार्वजनिक छुट्टी को कर्मचारी की छुट्टी की भ्रमचारी की छुट्टी की भ्रमचारी की छुट्टी की भ्रमचार कर्मचारी की छुट्टी के खाते से घटा दिया जाए।

91. वेतनवृद्धियों की मंजूरी

वेतनवृद्धियां लेने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथवा कोई द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी। यदि कर्मचारी निलम्बित है तो सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से इस प्रकार की मंजूरी में विलम्ब कर सकता है।

92. वेतनवृद्धियों, दक्षतारोध, भावि को रोकना

(1) इस विनियम के उप-विियम (2) से (4) तक तथा विनियम 89 के उपनंदों की गतों के प्रधीन, प्रनुपासितक कार्रनाई को छोड़कर अन्यथा किसी भी वेतनवृद्धि को रोका नहीं जाए। वेतनवृद्धि रोकने वाले प्रत्येक भादेश में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि कितनी श्रवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई है श्रीर क्या इस स्थगन से भावी वेतनवृद्धियों का स्थगन भी प्रभावित होगा।

- (2) यदि किसी वृद्धिशील वेतनमान में दक्षता-रोध हो तो कर्मचारी को उस दक्षता-रोध से आगे तब तक वेतन-वृद्धियां प्राप्त नहीं होंगी जब तक कि प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने के लिए योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जायेगा।
- (3) ऐसे प्रत्येक भवसर पर, जबिक कर्मचारी को दक्षता-रोध, जो पहले उस पर लागू था, पार करने की प्रनुमति दी जाती है, उसे वृद्धिणील वेतनमान में उसे स्तर पर रखा जायेगा, जो दक्षता-रोध हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धा-रित किया जाए, बणर्ते कि वह स्तर उस स्तर से उच्च नहीं होगा जिस पर दक्षता-रोध लागू न किये जाने पर उसे बेतन मिलता भौर साथ ही दक्षता-रोध हटाने पर प्रदान की गई वेतमवृद्धियां पूर्व प्रभावी नहीं होंगी।
- (4) उप-विनियम (2) और (3) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, कर्मचारी द्वारा किसी विभागीय या निगम द्वारा निर्धा-रित कोई भ्रन्य परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अपेक्षा के भ्रनुपालन में लगाई गई किसी भी प्रकार की पाबन्दी पर भी लागू होंगे।

93. समय पूर्व वेतनवृद्धियां

विशिष्ट मामलों में, ग्रध्यक्ष समयपूर्व वेतनवृद्धियां प्रदान कर सकता है, परन्तु श्रेणी 1 के ग्रधिकारियों के प्रत्येक मामले में बोर्ड की पूर्व श्रनुमति लेनी ग्रावश्यक होगी।

खण्ड-।∨--रियायतें

94. मानवेय, श्रावि प्रवान करना

- (1) संचालक बोर्ड ऐसी णर्ते निर्धारित कर सकता है जिनके श्रधीन निगम किसी कर्मचारी को इंस्टीट्यूट आंफ बैंकर्स की परीक्षाएं ग्रथवा ऐसी परीक्षाएं, जिनमें उत्तीर्ण होना निगम की सेवा के हित में ग्रावश्यक हो, उत्तीर्ण करने पर स्थास्थित मानदेय या विशेष वेतनवृद्धि प्रधान की जा सेकती है।
- (2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु ऐसी शर्ती, पावन्दियों या सीमाओं के प्रधीन जो मानदेय प्रवान करने के सम्बन्ध में लागू की गई हों, प्रध्यक्ष, किसी कर्मचारी को, किए गए यदा-कदा या विरामी प्रकृति के विशेष कार्य के लिए घौर या तो श्रमसाध्य प्रथवा ऐसे विशेष गुणवत्ता के कार्यों के लिए जिनके लिए विशेष पुरस्कार देने का ग्रौचित्य हो, पारिश्रमिक के रूप में मानदेय प्रदान कर सकता है जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: (1) यदि कार्य श्रध्यक्ष की पूर्वानुमित के विना किया गया हो भौर इसकी राशि

- पहले ही तय न करली गई हो तो मान देय प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
- (2) ग्रस्थायी रूप से काम में वृद्धि होने पर ग्रथवा यदि विशेष कार्य, चाहै वह यदाकदा या विरामी प्रकृति का हो, कर्मचारी द्वारा धारित पद से सम्बद्ध सामान्य कर्तव्यों के समुखित भाग के रूप में माना गया हो, कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।
- (3) उक्त उप-विनियम के प्रधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित स्टाफ कार ड्राइबर अथवा गेस्टेटनर प्रापरेटर की प्रनुपस्थिति में स्टाफ कार अथवा डुप्लीकेंटिंग मशीन चलाने के लिए मानदेय प्रदान किया जा सकता है, बंगर्ते कि कर्मचारी स्वयं इसी प्रकार के पथ पर कार्य न कर रहा हो और मल्पाविध के लिए कोई नियमित स्थानापनन व्यवस्था ग्रावश्यक ग्रथवा उच्चित न समझी गई हो।

95. ब्रवकाश किराया भौर सेवा-निवृत्ति किराया रियायतें

निगम के स्टाफ को, इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर श्रनुमोदित व्यवस्थाओं के श्रनुसार श्रवकाण धौर सेवा-निवृत्ति किराया रियायतें प्रदान की जा सकती हैं।

96. भ्रम्भिम

निगम के स्टाफ को बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित भारतों के अधीत क्याज पर अथवा अन्यथा अग्निम (मकान के निर्माण, वाहन खरावने के लिये, बाढ़ राहत, आदि के लिये अग्निम) प्राप्ता करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकनी है।

97. बोर्ड द्वारा विनियम 90 श्रीर 96 के श्रधीन लिए गए निर्णयों को, निगम द्वारा जारी किए जाने वाले प्रशासन परि-पत्नों के रूप में स्टाफ के सदस्यों में प्रसारित किया जायेगा श्रीर इस सम्बन्ध में नए अनुदेश जारी किए जाने तक वर्त-मान श्रादेश प्रभावी रहेंगे।

98. शासकीय स्थिति के दोष-निवारण के लिए विस्तीय सहायता बोर्ड ऐसी परिस्थितियों, शतों श्रीर सीमाश्रों का निर्धारण कर सकता है जिनके प्रधीन, यदि कर्मचारी को उसके शासकीय कायों या स्थिति के कारण होने वाले श्रथवा उससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कर्मचारी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई हो, कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रवान श्रथवा जैसा भी मामला हो, उसकी प्रतिरक्षा प्राधिकृत की जा सकती है।

परन्तु, इस विनियम में से, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही पर कुछ भी लागू नहीं होगा,जो कर्मचारी के शासकीय कार्यों या स्थिति से उद्भूत या उससे सम्बन्धित न हो। 99. विनियमों से संशोधन के बिना कोई रियायतें नहीं दी जायेंगी

बोर्ड की विशेष मंजूरी के बिना इन विनियमों के दायरे में न झाने वाली कोई भी रियायतें प्रदान न की जायें। परन्तु, फिर भी, प्रध्यक्ष ऐसी रियायतें सुख-सुविधायें प्रदान कर सकता है जो इन विनियमों के वायरे में न झाती हों, यदि उनके विचार में ऐसी रियायतें, सुख-सुविधायें प्रदान करना झावश्यक श्रथवा समायोजित हो, परन्तु उसके तत्काल बाद बोर्ड से कार्योत्तर धनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

- 100. रियायतों को सेवा की शतों के रूप में नहीं माना जायेगा और उनका पुरुषयोग अनुशासन का उलंघन माना जायेगा
- (1) इस खंड के घ्रधीन ध्रथवा समय-समय पर प्राधिकृत रियायतें किसी भी परिस्थिति में कर्मजारी की सेवा शतों का भाग न मानी जाएं श्रीर इन्हें घ्राधिक घ्रथवा पूर्ण रूप से वापिस लिया जा सकता है या निलम्बित किया जा सकता है, जैसा भी बोर्ड निर्धारित करे।
- (2) कर्मचारी द्वारा, इसमें प्राधिकृत ग्रथवा समय-समय पर प्राधिकृत की गई रियायतें देने के सम्बन्ध में किसी भी गर्त का उल्लंघन या निगम द्वारा दी गई ऐसी सुविधाओं या सुख-सुविधाओं के निष्पादन में किसी सुविधा का दुरुपयोग, इस विनियमों के ग्रथ के ब्रधीन मनुसासन का उल्लंबन माना जहमेगा।

खण्ड-V-देय राशियों, गुल्क अथवा अन्य आय की वसूली

101. देय राशियों की वसूली

जब तक निगम अन्यथा विशेष रूप से सहमत न हो, कर्मचारी, उसके द्वारा निगम को देय और संदेय किसी भी मुद्रा या मुद्राओं के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक से एकदम वसूली हेसु, और उसके वितन और भत्तों अथवा कर्मचारी को निगम द्वारा देय और संदेय किसी अन्य राशि से एकमुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित किस्तों में समाधोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

- 102. शासकीय हैंसियत में घन्य स्रोतों से अजित शुल्क तथा धन्य आय निगम को ग्रदा की जायेगी।
- (1) इन विकियमों के उपजन्धों के अधीन कर्मणारी द्वारा शासकीय हैसियत में निगम से भिन्न स्रोतों से अथवा निगम में उसकी सेवा के दौरान कर्मणारी द्वारा अजित ज्ञान से समर्थित प्रवासों से प्राप्त पूर्ण शुल्क या अजित ज्ञाय अथवा उसका भाग जैसी भी सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे, निगम को दिया जायेगा।

परन्तु, किसी पुस्तक अथवा अन्य कृति की विकी अथवा रायल्टी से प्राप्त किसी आय पर इस विनियम में से कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि वह—

(क) कर्मचारी द्वारा निगम में उसकी सेवा के दौरान ग्राजित ज्ञान से समर्थित नहीं है।

- (ख) कर्मचारी द्वारा निगम में उसकी सेवा के बौरान प्रजित ज्ञान से समिथित होने पर भी, विषय के निष्पादन में कर्मचारी के विद्वतापूर्ण प्रध्ययन या प्रनुसंधान का द्योतक हो घौर वह उसके द्वारा धारित पद से सम्बद्ध उसके सामान्य कर्त्तब्यों श्रीर दायित्वों के प्रनुसरण या उसका भाग न
- (2) म्रध्यक्ष द्वारा विशेष म्रादेश से मन्यथा निदेश न दिये जाने तक उप-विनियम (6) के म्रधीन कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी गुल्क का, 400/- के मार्थिक म्रथमा, यदि वह म्रावर्ती प्रकृति का है, 200/- के वार्षिक से एक-तिहाई भाग तक निगम को जमा करवाया जायेगा।

श्रष्टयाय--Vl

छुट्टी ध्रौर कार्य-भार ग्रहण अवधि खण्ड-1,—छुट्टी से सन्बन्धित सामान्य निदम

103 छुट्टी के प्रकार

इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी प्रदान की जासकती है।

- (क) साधारण छुट्टी
- (खा) आकस्मिक छुट्टी ।
- (ग) बीमारी की छुट्टी
- (घ) विशेष छुट्टी
- (ङ) त्रसाधारण छुट्टी
- (च) प्रसूति छुट्टी
- (छ) भ्रष्ययन छुट्टी
- (ज) खाते पर छुट्टी
- (**झ) विशेष ग्रगक्तता छुट्टी**

104. खुट्टी प्रदान करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी

इन विनियमों में प्रन्यथा विशेष रूप से उपबंधित को छोड़कर छुट्टी मंजूर करने की शक्ति ग्रध्यक्ष ग्रथवा निगम के ऐसे किसी भी श्रधिकारी में निहित होगी, जिसे श्रोद्यो-गिक वित्त निगम श्रधिनियम, 1948 की धारा 40 क की शर्तों के श्रधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो। छुट्टी के लिए सभी श्रावेदन-पत्न छुट्टी प्रदान करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी को सम्बोधित किये जायेंगे।

106. छुट्टी अस्वीकार अथवा रद्द करने की शक्ति

श्रधिकार के रूप में छुट्टी का दावा नहीं किया जा सकता। सेवा की ग्रपेक्षाग्रों के श्रनुसार, छुट्टी मंजूर करने की ग्राक्ति प्राप्त अधिकारी के पास, किसी भी प्रकार की छट्टी को ग्रस्वीकार ग्रथवा रद करने का श्रधिकार ग्रारक्षित है।

106. कर्मचारी को छुट्टी से वापस बलाने की सक्ति

(1) छुट्टी प्रदान करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी, पहले से ही छुट्टी पर गए किसी कर्मचारी को वापस भी बुला सकता है यदि निगम के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।

(2) कर्मचारी को छुट्टी की समाप्ति से पहले वापस बुलाने के सभी ध्रदेशों में उल्लेख किया जाये कि क्या यह वापसी स्वेच्छिक है ग्रथवा ग्रनिवार्य। यदि वापसी स्वेच्छिक है ग्रथवा ग्रनिवार्य। यदि वापसी स्वेच्छिक है तो कर्मचारी किसी रियायत का हकदार नहीं है, यदि यह ग्रनिवार्य है तो कर्मचारी उस तारीख से इ्यूटी पर माना जायेगा ॄिजस तारीख से बह ग्रादेश दिये गये स्थान के लिए रवाना होता है ग्रीर वह नियमों के ग्रनुसार याना भसा पाने का हकदार होगा।

107 छुट्टी अर्जन ग्रोर व्यपगत होना

केवल ड्यूटी पर ही छुट्टी अजर्ता होती है भौर कर्म-चारी के सेवा में न रहने की तारीख से छुट्टी व्यपगत जाती है।

लेकिन सेवा दौरान देहान्त हो जाने वाले कर्मचारी के मामले ने, उसके खाते में जमा साधारण छुट्टी के सम्बन्ध में स्वीकार्य छुट्टी वेतन उसके नामित (नामितों) उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को भ्रवा किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए छुट्टी के बेतन का गणन उसके ड्यूटी पर होने के समय प्राप्त किये गये भ्रन्तिम वेतन के भाधार पर किया जायेगा।

108 छुट्टी की अवधि की समाप्ति से पहले लौटना

छुट्टी पर रहने वाला कर्मचारी से प्रदान की गई छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) की धवधि समाप्त होने से पहले तब तक ड्यूटी पर नहीं सौट सकता जब तक छटी मजूर करणे वाले प्राधिकायी द्वारा उसे ऐसा करने की अनमित दी जाए।

109 छुट्टी का प्रारम्भ ग्रीर तमाप्त होना

- (1) कर्मचारी छुट्टी का पहला दिन, उसके कार्यभार सौंपने या ड्यूटी परहोने के भ्रन्तिम दिन से ग्रगला कार्य-दिवस है भ्रोर कर्मचारी की छुट्टी का श्रन्तिम दिन उपके ड्यूटी पर लौटने के दिन से पहला कार्य-दिवस है।
- (2) जब तक कर्मचारी के छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे प्रपराह्न में इ्यूटी पर वापस प्राने की प्रनुमित न दी गई हो, वह अपनी छुट्टी समाप्त होने पर छुट्टी समाप्ति के दिन से ग्रगले कार्य-दिवस को इ्यूटी पर वापस ग्राने की पूर्वाह्न में रिपोर्ट करेगा।
- (3) छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी, ऐसी परिस्थितियों ग्रौर गर्तों के श्रधीन जैसी वह उचित समझे; छुट्टी के पहले ग्रौर/ग्रथवा बाद में रिववार या ग्रन्य मान्यता-प्राप्त सार्वजनिक छुटियां जोड़ने की ग्रनुमित दे सकता है।
- 110. छुट्टी के दौरान, पता प्रस्तुत करने भौर कोई रोज-गार या निजी व्यवसाय न करने का दायित्व
- (1) प्रत्येक कर्मचारी, भ्राकस्मिक छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी पर जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी को ऐसी

- छुट्टी के दौरान भ्रपना पता देगा भीर पहले दिए गए पत्ते में किसी परिवर्तन से उक्त प्राधिकारी को सूचित करता रहेगा।
- (2) छुट्टी के दौरान कर्मचारी, उसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त प्रधिकारी की स्वीकृति के बिना, कोई सेवा नहीं करेगा श्रथवा कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेगा जिसमें लेखपाल, तकनीकी या भौद्योगिक परामर्शन्दाता, वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में प्रथवा विधिक व्यवसायी के रूप में निजी व्यवसाय भी शामिल है।
- 111. छुट्टी से लौटने पर कर्मचारी किस स्थान पर ड्यूटी के लिए पुनः उपस्थित हो

खुट्टी पर गया हुआ कर्मचारी जिस स्थान पर पहले रहा हो, उसी स्थान पर इ्यूटी के लिए लौटेगा बगर्ते कि उसको इसके विपरीत कोई भ्रन्यथा भादेश प्राप्त न हों।

परन्तु कि श्रेणी I और श्रेणी II के कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किए जाने पर जोर नहीं दिया जाएगा यदि मंजूर की जाने वाली छुट्टी चार दिन से ग्रधिक न हो ग्रौर सक्षम प्राधिकारी ऐसी छुट्टी के कारणों की वास्तविकता से सन्तुष्ट हो।

- 112 बीमारी भौरे भारोग्य प्रमाण-पत्न की भावश्यकता
- (1) सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे कर्मचारी से, जिसने स्वास्थ्य के कारणों से छुट्टी का श्रावेदन-पत्न दिया हो, उसके श्रावेदन-पत्न के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
- (2) सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे कर्मचारी से, जिसने स्वास्थ्य के कारणों से छुट्टी ली हो, ड्यूटी के लिए पुनः उपस्थित होने से पहले प्रशेग्य चिकित्सा प्रमाण-पन्न की मांग कर सकता है यद्यपि ऐसी छुट्टी उसे वास्तव में चिकित्सा प्रमाण-पन्न के स्नाधार पर मंजूर नहीं की गई थी।

113 कर्मचारी को निलम्बन के दौरान छुट्टी देय नहीं होगी

ऐसे किसी कर्मचारी को छुट्टी प्रवान नहीं की जायेगी जो निलम्बित हो या जिसके विरुद्ध इन विनियमों के मध्याय IV के मन्तर्गत कोई कारवाई ग्रनिणींत हो।

खण्ड-II---साधारण खुट्टी

114. ग्रावेदन-पन्न छुट्टी के लिए कब प्रस्तुत किया जाए

श्रेणी I के कर्मचारियों द्वारा साधारण छुट्टी के लिए धावेदन-पत्र उस तिमाही से पहली तिमाही के गुरू में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें वह छुट्टी पर जाना चाहिला है तथा ग्रन्थ कर्मचारियों द्वारा छुट्टी मांगे जाने की तारीख से एक मास पूर्व भावेदन-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण :—"तिमाही" का धर्म है प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर धौर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तीन महीने की ग्रवधि।

115. साधारण छुट्टी किस मान्ना में भ्रजित की जायेगी

- (1) ड्यूटी के ग्यारह दिन पर एक दिन की साधारण छट्टी अर्जित होगी।
- (2) कर्मधारी द्वारा भ्रजित की गई साधारण छुट्टी का हिसाब लगाते समय, निगम की सेवा में ग्राने के बाद से या इसके पहले उसके छुट्टी से लौटने की तारीख से उन ग्यारह महीनों की पूरी भवधियों को पहले हिसाब में लिया जायेगा जिनके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर रहा हो भीर कर्मचारी के छट्टी के खाते में ड्यूटी के ग्यारह महीने की ग्रविध के लिए एक महीने की छुट्टी जमा की जायेगी जो इस उप-विनियम (1) के ग्रन्सर्गत उपलब्ध है, यदि उसके बाद ड्यूटी की कोई भवधि शेष वन जाती है या ग्यारह महीने की कोई पूरी ध्रवधि न हो तो ऐसी बची हुई भवधि या ड्यूटी की वास्तविक भवधि को गिना जायेगा ग्रीर कर्मभारी द्वारा की गई इयूटी के हर ग्यारह दिन के लिए एक दिन की अर्जित छुट्टी जमा होगी। यदि अर्जित की गई छुट्टी के एक दिन का ग्रंश ग्राधा-दिन या उससे मधिक हो तो उसे पूरा दिन माना जायेगा ग्रौर यदि वह भाधे विन से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। श्रेणी III ग्रौर Iγ के परिवीक्षाधीन कर्मचारी के मामले में साधारण छट्टी का धर्जन सेवा के पहले वर्ष में इ्यूटी की भविध का 1/22वां भाग धौर उसके **बा**द भाग होगा।

116. देय साधारण छुट्टी

कर्मचारी को देय साधारण छुट्टी, उसके द्वारा श्रजित छुट्टी में से बास्तव में ली गई छुट्टी को घटाने के बाद शेष बची हुई धवधि है।

117. किन सीमाभ्रों तक साधारण छुट्टी मर्जित की. या ली जा सकती है

सभी कर्मजारियों के मामले में किसी एक बार ली जाने वाली साधारण छुट्टी की भविध 180 दिन है भौर किसी कर्मजारी की इतनी छुट्टी जमा हो जाने के बाद बहु भौर साधारण छुट्टी भीजत नहीं कर सकता।

परन्तु, जिस तारीख को कर्मचारी ग्रधिकतम छुट्टी ग्रांजित करेगा उस तारीख से कम से कम तीन महीने पहले जब उसने छुट्टी के लिए ग्रौपचारिक रूप से ग्रावेदन किया हो ग्रौर छुट्टी ग्रस्त्रीकार कर दी गई हो या उसने लिखित रूप से यह सुनिश्चित कर लिया हो कि यदि वह छुट्टी के लिए ग्रावेदन करे तो वह मंजूर नहीं की जा सकती तो ऐसे कर्मचारी को छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक उपर्युक्त ग्रधिकतम मबिंध से ग्रधिक छुट्टी ग्रांजित करने की ग्रामुमित दी जा सकती है।

118 भाकस्मिक छुट्टी

- (1) जनवरी ने प्रारम्भ श्रौर दिसम्बर में समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष में (इसमें इसके बाद इस विनियम में "कैलेंडर वर्ष" कहा जायेगा) कर्मचारी को श्रधिकतम पन्द्रह दिन की श्राकस्मिक छुट्टी, निम्नलिखित मर्तों पर मंजूर की जा सकती है कि—
 - (क) कार्य-अपेक्षाएं छुट्टी प्रवान करने की श्रनुमति देती हो भौर छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर किसी ध्रन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की ध्रावश्यकता न हो।
 - (ख) किसी एक समय में मांगी गई छुट्टी की अवधि सात विन से अधिक और सार्वजनिक छुट्टियां साथ मिलाने से दस दिन से अधिक न हो, लेकिन जब छुट्टी की अवधि ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक हो जाती है तो पहले अथवा बाद में जोड़ी गई सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर समग्र अवधि, साधारण छुट्टी या कर्मचारी को अनुमत्य ऐसी अन्य छुट्टी पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जा गी।

परन्तु, छह माह से कम सेवा अवधि वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रत्येक माह की सेवा के लिए एक आकस्मिक छुट्टी प्रवान की जाएगी।

- (2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, श्रेणी I के कर्मचारियों के मामले में श्रध्यक्ष ग्रौर ग्रन्थ मामलों में महाप्रबंधक, उक्त उप-विनियम में निर्धारित सभी या कुछ सीमाग्रों या शर्तों के बिना विशेष श्राकस्मिक छूट्टी प्रदान करने की श्रनुमित दे सकता है, यदि सिकय इयुटी से श्रनुपस्थित निम्नलिखित कारणों मे हो——
 - (क) किसी संक्रामक रोग ग्रर्थात्, हैजा, चेचक, डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफस ज्वर, श्रादि के कारण कार्यालय में उपस्थित न होने के ग्रादेश के कारण;
 - (ख) कर्मचारी द्वारा किसी एसोसिएशन या इस सम्बन्ध में निगम द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ध्रन्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए जाने के कारण;
 - (ग) कर्मचारी को प्रादेशिक सेवा, सहायक बल, इंडिया होम गार्डस् या किसी अन्य नागरिक रक्षा संगठन ग्रथवा इस संबंध में निगम बारा मान्यताप्राप्त इसी प्रकार के किसी अन्य सरकारी संगठन में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के कारण;
 - (घ) यदि कीड़ाओं का स्रायोजन स्रन्तर्राज्यीय, स्रन्तर क्षेत्रीय श्रथवा स्रन्तर मण्डलीय स्राधार पर किया जाए सीर इस उद्देश्य के लिए निगम द्वारा स्रन-मोवित राष्ट्रीय कीड़ा फेडरेशन, एसोसिएशन स्रचवा स्रन्य संगठन की स्रोर से स्रथवा राज्य, क्षेत्र

भयवा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में कर्मचारी का क्रीड़ा में भाग लेने के लिए चयन किया गया है भौर ये कीड़ाएं भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रथवा राष्ट्रीय महत्व की हों, उनमें भाग क्षेत्र के कारण;

- (ङ) ग्रन्थ विशेष या ग्रमाधारण परिस्थितियों के कारण ग्रथीत्,
 - (i) परिवार नियोजन योजना के श्रन्तर्गेत नस-बन्दी भ्रापरेशन करवाना;
 - (ii) किसी कार्य-दिवस के दौरान रक्त दान करना;
 - (iii) सिविल उपद्रव, कर्फ्यूया सामान्य हड़तालों के दौरान कार्यालय झाने में ग्रसमर्थ होना;
 - (iv) निगम द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षाओं में भाग लेना;
 - (v) ऐंसी कोई अन्य विशेष स्थिति जिसे भ्रष्यक्ष, सामान्य या विशेष भ्रादेश द्वारा विशेष या असाधारण घोषित करे;

परन्तु----

- (i) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत प्रवान की गई आकस्मिक छुट्टी सहित (क), और (ग) के अन्तर्गत प्रवान की गई विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि किसी भी स्थिति में किसी एक कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर तीस विन से अधिक नहीं होगी।
- (ii) खण्ड (ख) के ग्रन्तर्गत प्रवान की गई विशेष ग्राकिस्मिक छुट्टी की ग्रविध किसी भी स्थिति में किसी एक कैलेंडर वर्ष में 21 दिन से ग्रिधिक नहीं होगी।
- (iii) खण्ड (घ) के घंतर्गत प्रदान की गई विशेष आकस्मिक छुट्टी की प्रविध किसी भी स्थिति में किसी एक कैलेंडर वर्ष में 45 दिन से घधिक नहीं होगी;
- (iv) खण्ड (ङ), के प्रन्तर्गत प्रदान की गई विशेष धाकस्मिक छुट्टी की ध्रवधि किसी भी स्थिति में, प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के स्वरूप के ग्राधारपर सक्षम प्राधिकारी द्वाराप्राधिकृत किए गए दिनों से ग्रिधिक नहीं होगी।
- (3) जब कोई कर्मचारी उप-विनियम (2) के खण्ड (क) से (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में छुट्टी के लिए आवेदन करता है और उसके लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रवान करने से किसी एक कैलेंडर वर्ष में उसे प्रवान की गई आकस्मिक छुट्टी की कुल अविध, उक्त उप-विनियम के परन्तुक में निर्विष्ट सीमाओं से अधिक हो जाए, तो इस प्रकार अधिक अनुपस्थित की अविध सामान्य छुट्टी, बीमारी की छुट्टी या विशेष छुट्टी, गर्वि ऐसं। छुट्टी अन्यथा अनुमत्य हो, पर बिताई गई अविध और येष ऐसी कोई छुट्टी अनुमत्य न हो तो असाधारण छुट्टी पर बिताई गई अविध के रूप में मानी जायेगी। विनियम

120 में किसी बात के होते हुए भी इस उप-विनियम के अन्तर्गत दी जाने बाली कोई विशेष छुट्टी ली जा सकती है चाहे सामान्य छुट्टी अनुमत्य हो।

(4) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए प्राक्रिमक छुट्टी ग्रीर विशेष ग्राक्रस्मिक छुट्टी का हिसाब लगाते समय, बीच में ग्राने वाली सार्वजनिक छुट्टियों को ग्राक्षस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं माना जायेगा।

119 बीमारी की छुट्टी

- (1) कर्मचारी को उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 18 मास तक की अवधि के लिए बीमारी की छुट्टी दी जा सकती है और सामान्यतः एक बार में कर्म-चारी को अनुमत्य बीमारी की छुट्टी की अवधि, निगम में उसकी सेवा की अवधि के उसी अनुपात में होगी जो 30 वर्ष की सेवा के लिए 18 महीने की अवधि का है।
- (2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत अनुमत्य ऐसी छुट्टी की अधिकतम अविध के अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी, श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में बोर्ड और अन्य मानलों में अध्यक्ष की अनुमति से केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।

120. विशेष छुट्टी

किसी कर्मचारी को उसकी सेवा की पूरी धवधि के बौरान, जब उसे कोई साधारण छुट्टी देय न हो, निजी कार्यों के लिए ग्रिधकतम 12 मास की भवधि तक विशेष छुट्टी दी जा सकती है ग्रीर समान्यतः एक बार किसी कर्मचारी को धनुमत्य विशेष छुट्टी की भवधि, निगम में उनकी सेवा भवधि के उसी भनुपात में होगी जो तीस साल की सेवा में बारह महीने की भवधि का है।

परन्तु, कि यदि कोई साधारण और बोमारी की खुद्टी (खाते पर छुट्टी सहित) उपजब्ध न हो तो निम्नलिखित बीमारियों, जिनके लिये लम्बे उपचार की ग्रावश्यकता है, से पीड़ित श्रेणी IV कर्मचारी को श्राधे वेतन भीर घोषाई वेतन पर जिलेख छुट्टी प्रवान की जायेगी:

नीमारी का नाम

- ा. क्षय रोग
- ずせて
- 3. कुष्ठ रोग
- 4. पीलिया
- 5. पोलियो
- 6. मानसिक रोग
- 7. हृदय रोग

121. संगरोध के कारण ग्रनुपस्थिति

यदि कोई कर्मचारी संगरोध के कारण ख्यूटी से अनु-पस्थित हो तो निगम, कर्मचारी के अनुरोध पर अधिकतम तीन महीने तक की ऐसी अनुपस्थित को, साधारण खुट्टी, बीमारी भी खुट्टी या विशेष खुट्टी, यदि ऐसी खुट्टी अन्यथा अनुमत्य हो, पर बिताई गई अवधि के रूप में स्वीकार कर सकता है। विनियम 120 में किसी बात के होते हुए भी इस विनियम के अधीन प्रदान की जाने वाली किसी विशेष खुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है चाहे साधारण खुट्टी अनुमत्य हो।

122 प्रसाधारण छुट्टी

- (1) कर्मंचारी को श्रसाधारण छुट्टी तब मंजूर की जा सकती है जब उसे कोई साधारण छुट्टी देय न हो झौर जब उसकी सेवा की श्रवधि और अन्य सम्बद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी मंजूर करने के अभित प्राप्त प्राधिक कररी द्वारा बीमारी की छुट्टी या विशेष छुट्टी वेना उचित न समझा जाए!
- (2) भपबादारमक परिस्थितियों को छोड़कर झसाधारण छुट्टी की भवधि किसी एक बार में 3 महीने भौर कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान 12 महीने से अधिक नहीं होगी, 12 महीनों से अधिक की भसाधारण छुट्टी, श्रेणी 1 के कम- चारियों के मामले में बोर्ड भौर प्रत्य मामलों में अध्यक्ष की स्वीकृति से प्रवान की जा सकती है।

(छुट्टी के वौरान बेतन के लिए विनियम सं० 130 वेखें)

123. प्रसूति छुट्टी

- (1) प्रसूति छट्टी किसी विवाहित महिला कर्मणारी को किसी एक भवसर पर अधिक से भिधक चार महीने की भवधि तक और कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान अधिक से अधिक बाह्ह महीने के लिए प्रवान की जा सकती है।
- (2) गर्भपात और गर्भस्नाय के मामले में भी इस शर्त के भ्रधीन प्रसूति छुट्टी दी जा सकती है कि छुट्टी की भ्रविध 6 सप्ताह से भ्रधिक न हो और छुट्टी के भ्रावेदन के समर्थन में, निगम को स्वीकार्य चिकित्सा भ्रधिकारी का प्रमाण-नम्न सलग्न हो।
- (3) प्रसूति छुट्टी के साथ मिशाकर कोई अन्य प्रकार की छुट्टी ली जा सकती है, परन्तु प्रसूति छुट्टी के अनुक्रम में जी जाने वाली छुट्टी केवल तभी दी जा सकती है यदि आवेदन के समर्थन में चिकित्सा प्रसाल-पक्ष संनम्ब हो।

124. प्रथमन की छुट्टी

6-239GT/87

(1) किसी कर्मचारी को, एक बार में 12 महीने से अन-धिक और उसकी पूरी सेवा में 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती है जिससे वह अपने कर्सव्यों के क्षेत्र से सीधा सम्बन्ध रखने वाला कोई अनुमहेदिस अध्ययन, प्रशिक्षण या शिक्षण का पाठ्यक्रम भारत में, भारत से बाहर किसी देश में कर सकता है। अध्ययन के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रत्येक मामले में अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक होगी और वह उन शतों के अधीन होगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई हो और सामान्यतः उन कर्मचारियों को प्रवान नहीं की जायेगी जिन्होंने निगम में कम-से-कम 5 वर्ष की सेवान की हो याजो 3 वर्ष में सेवा-निवृत्त होने वाले हों।

(2) ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसे प्रध्ययान के लिए खुट्टी प्रवान की गई हो, इस सम्बन्ध में यथानिर्धारित फार्म में मिगम के उचित हित रक्षण के लिए एक बन्ध-पत्र भरेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्वीकार करेगा कि वह प्रध्ययन के लिए छुट्टी या उसकी बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर बार्षेंस आएगा और ड्यूटी पर बापस आने के बाद क्यूटी पर बार्षेंस आएगा और ड्यूटी पर बापस आने के बाद कम-से-कम 3 वर्ष के लिए निगम की सेवा करेगा।

125. खाते पर छुट्टी

खाते पर छुट्टी केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब अन्य प्रकार की छुट्टियां नियमों के अन्तर्गंत देय और अनुमत्य न हों। खाते पर छुट्टी के दौरान कर्मचारी उसी छुट्टी-बेतन का हकदार होगा जो अर्द्धवेतन छुट्टी के दौरान होगा, बस्सुत: इसका तात्पर्म है कि खाते पर छुट्टी अग्निम रूप से प्रकान की गई अर्द्धवेतन छुट्टी है।

"खाने पर छुट्टी" की मंजूरी के लिए आवश्यक शर्ते

- (i) यह नियम के स्थायी कर्म चारियों को अनुमृत्य होगी।
- (ii) यह केवल तभी भनुमत्य होगी जब किसी भन्य छुट्टी (भ्रसाधारण छुट्टी को छोष्ट्रकर) देय भीर भ्रनुमत्यनहो।
- (iii) यह केवल तभी प्रवान की जायेगी जब खुट्टी
 मंजूर करने का सक्ति प्राप्त श्रिधकारी ग्राम्बस्त
 हो कि छुट्टी समाप्त होने पर कर्मचारी की इयूटी
 पर वापस ग्राने की पर्याप्त सम्भावना है ग्रीर वह
 उसके नामे खाते डाली गई छुट्टियां समाप्त करने
 के लिए पर्याप्त समय तक सेवा में रहेगा। इसलिए
 खाते पर छुट्टी, सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में
 नहीं दी जा सकती ग्रीर उस ग्रद्ध-वेतन छुट्टी कर्थांत्
 विशेष छुट्टी या बीमारी की छुट्टी तक सीमित
 होती है जिसकी कर्मचारी द्वारा ग्रंथनी वापसी पर
 ग्रामित किए जाने की सम्भावना है।
- (iv) यदि ऐसा कोई कर्मचारी, जिसे "खाते पर छुट्टी" प्रदान की गई हो, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की अनुमति के लिए आवेदन करता है, और यदि उस अनुमति दे दी जाती है तो "खाते पर छुट्टी" रह कर दी जायेगी। "खाते पर छुट्टी" का लाभ उठाने वाले कर्मचारी से इस आशय का एक वचन-पत्न लिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का निर्धारण, कि क्या कर्मचारी से, पहले ही ली गई "खावे पर छुट्टी" की अवधि के दौरान लिये गये छुट्टी वेतन की राशि वापस करने की मांग की जानी चाहिए, प्रश्येक मामले के गुण-दौय के आधार पर किया जायेगा, अर्थात् यदि सेवा-निवृत्ति स्वैच्छिक है तो राशि वापस करने के लिए बाध्य किया जायेगा; यदि कर्मचारी को और सेवा करने

वाले भ्रस्थास्थ्य के कारण ऐसा करना भ्रपरिहार्य होतो राणि की वापसी के लिए भ्राग्रह नहीं किया जायेगा।

- (v) किसी कर्मचारी को दी जा सकने वाली "खाते पर छुट्टी" की कुल मान्ना, उसकी पूरी संवा के दौरान 360 दिन तक सीमित है, जिसमें से किसी एक समय में 90 दिन से प्रधिक नहीं दी जा सकती श्रोर चिकित्सा प्रमाण-पन्न से भिन्न स्थिति में कुल मिला-कर 180 दिन के लिए दी जा सकती है।
- (vi) क्षयरोग का इलाज करवाने वाले कर्मचारियों को खाते पर छुट्टी प्रदान करना।

क्रमरोग से पीड़ित स्थायी कर्मचारियों श्रौर ऐसे प्रस्थायी कमचारियों को भी, जिन्होंने 3 वर्ष से श्रधिक समय तक लगातार सेवा की हो, इस शर्त के श्रधीन "खाते पर छुट्टी" दी जा सकती है कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी श्राश्वस्त हो जाए कि कर्मचारी की (i) छुट्टी समाप्त होने पर ड्यूटी पर वापस श्राने की श्रौर (ii) उसके बाद, उसके द्वारा ली गई "खाते पर छुट्टी" की मान्ना के बराबर बीमारी की छुट्टी/ विशेष छुट्टी श्राजित करने की पर्याप्त सम्भावना है। छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस श्राने की संभावना का निर्धारण चिकत्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्न के श्राधार पर किया जाना चाहिए। "खाते पर छुट्टी" की मान्ना के बराबर कम-से-कम छुट्टी श्राजित करने की संभावना का निर्धारण इस तथ्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ड्यूटी पर वापस श्राने के बाद कर्मचारी की उतनी सेवा-श्रविध होगी जिसमें वह श्रपने नामे डाली गई छुट्टियां समाप्त कर सके।

निम्नलिखित व्यक्ति उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी होंगे :--

- (क) किसी मान्यताप्राप्त ग्रारोग्य निवास में इलाज करवा रहे कर्मचारी के मामले में मान्यता प्राप्त ग्रारोग्य निवास का प्रभारी चिकित्सा प्राधिकारी;
- (ख) म्रथने निवास स्थान पर इलाज करवा रहे कर्मचारी के मामले में सम्बन्धित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा भिधकारी द्वारा मान्यताप्राप्त क्षयरोग विशेषज्ञ; श्रीर
- (ग) फ़्रेफड़ों के क्षयरोग से भिन्न क्षयरोग से पीड़ित कर्मचारी के मामले में ग्रह्ता प्राप्त क्षयरोग विशेषज्ञ मथवा सिविल सर्जन।
- (vii) कुष्ठ रोग का इलाज करवा रहे कर्मचारियों को "खाते पर छुट्टी" प्रदान करना । कुष्ठ रोग से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में भी उपर्युक्त उप-पैरा (vi) में उल्लिखित रियायत, इसमें निर्धारित की गई शतीं के ही मधीन लागू होंगी । ऐसे मामलों में

निम्नलिखित व्यक्ति उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी होंगे :---

- (क) किसी मान्यताप्राप्त कुष्ठ रोग संस्थान जहां रोगी इलाज करवा रहा हो, प्रभारी चिकित्सा ग्रधिकारी; ग्रथवा
- (ख) सम्बन्धित राज्य प्रणासनिक चिकित्सा ग्रधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग विशेषज्ञ।

126. बिशेष बिकलांगता छुट्टी

श्रपने शासकीय कर्त्तंत्र्यों के उचित निष्पादन में या अपनी शासकीय स्थिति के कारण लगी चोट के द्वारा विकलांग हो गए किसी कर्मचारी को, चाहे वह स्थायी हों या अस्थायी, विशेष विकलांगता छुट्टी दी जा सकती है। श्राकस्मिक चोट लगने के ऐसे मामलों में भी निगम विशेष विकलांगता छुट्टी दे सकता है, जिनमें विकलांगता इतनी असाधारण हो कि ऐसी छुट्टी की मंजूरी का श्रोजित्य हो।

िन मतौँ के म्रधीन विशेष विकलांगता छुट्टी प्रवान की जायेगी, वे निम्नसिखित हैं:---

- (i) विशेष विकलांगता छुट्टी, सम्बन्धित कर्मचारी का इलाज करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण-पत्न के भ्राधार पर श्रौर उस सीमा तक दी जा सकती है जितनी वह श्रावग्यक प्रमाणित करे। उक्त प्राधिकारी के प्रमाण-पत्न के बिना इसे प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (ii) घटना घटित होने के 3 मास के भीतर विकलांगता प्रकट हो जानी चाहिए, लेकिन निगम, विकलांगता के कारण से श्राण्यस्त हो जाने पर उन मामलों में भी छुट्टी प्रदान कर सकता है जिनमें विकलांगता घटना के घटित होने के 3 मास से श्रधिक की अवधि के बाद प्रकट हुई हो।
- (iii) एक विकलांगता के कारण विशेष विकलांगता छुट्टी की माला 24 महीने तक, जिसमें से पहले 4 महीने भीसत बेतन पर भीर शेष श्रीसत अर्द्ध-वेतन पर सीमित है। कर्मचारी के विकल्प पर भीसत अर्द्ध-वेतन पर विशेष विकलांगता छुट्टी को, सम्बन्धित कर्मचारी को छुट्टी नियमों के भ्रन्तगंत भ्रन्यथा भ्रनुमत्य सीमा तक भ्रीसत वेतन पर छुट्टी में सं-परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन श्रीसत वेतन पर ऐसी छुट्टी की ग्राधी माल्ला सामान्य छुट्टी के खाते में डाली जानी चाहिए।
- (2) विशेष विकलांगता छुट्टी का गणन सेवा के रूप में किया जाता है ग्रीरयह साधारण छुट्टी खाते में नाम नहीं डाली जाती। इसे किसी भन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

127. ग्रस्थायी कर्मचारियों को ग्रनुमत्य छुट्टी

- (1) जब तक ग्रध्यर्म द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अस्थायी कर्मचारियों को निम्नानुसार छुट्टी प्रदान की जा सकती है:--
 - (i) ग्राकस्मिक छुट्टी ग्रौर विशेष ग्राकस्मिक छुट्टी उसी ग्राधार पर दी जायेगी जिस ग्राधार पर स्थायी कर्मचारियों को ग्रनुमत्य है, बणर्ते कि यदि कोई कर्मचारी केलेंडर वर्ष के दौरान सेवा में भ्राता है तो केवल भ्रानुपातिक माक्षा में भ्राकस्मिक छुट्टी प्रतुमत्य होगी;
 - (i) उनकी सेवा के पहले वर्ष के दौरान प्रत्येक बाईस दिन के लिए एक दिन की सीमा तक साम्रारण छुट्टी, भौर उसके बाद उसी आधार पर जिस पर स्थायी कमचारियों को स्वीकार्य होगी।
 - (iii) सेवा के प्रत्येक बाईस दिन के लिए एक दिन की सीमातक बीमारी की छुट्टी, बगर्ते कि जब ऐसे कर्मचारियों को प्राप्य बीमारी की छुट्टीदो महीने की हो जाए तो वह श्रौर बीमारी की छुट्टी अर्जित नहीं कर सकता;
 - (iv) एक वर्ष की शेवा के बाद उसी आधार पर असाधारण छुट्टी जिस आधार पर वह स्थायी कर्म-चारियों को स्वीकार्य है, बगर्ते कि श्रस्थायी सेवा की पूर्व श्रवधि के दौरान ऐसी छुट्टी तीन महीने से फ्राधिक न हो ;
 - (v) एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रस्थायी विवाहित महिला कर्मचारियों को उसी श्राधार पर प्रसूति छुट्टी, जिस म्नाधार पर वह स्थायी कर्मचारियों को स्वीकार्य है।
- (2) उप विनियम (1) के अन्तर्गत छुट्टी उन्हीं मतौं या प्रतिबन्धों के भ्रधीन स्वीकार्य होगी जो स्थायी कर्मजारियों पर लागू होती है।
- (3) ग्रंशकालिक कर्माचारियों को किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं प्रधान की जासकती जब तक कि उसकी सेवा शर्ती में अन्यथा व्यवस्थान की गई हो।

128. छुट्टी का संयोजन

- (1) विनियम 118 के उप-विनियम (2) के खण्ड (घ) के भ्रन्तर्गत प्रदान की गई विशेष भ्राकस्मिक छुट्टी, उक्त खण्ड के श्रन्तर्गत ग्रन्यथा प्रदान की गई श्राकस्मिक छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती और नहीं उसके साथ मिलाई जा सकती है।
- (2) जब तक विनियम 118 के उप-विनियम (3) में श्चन्यथा व्यवस्था न की गई हो भ्रथवा जब तक मामले की विशोष परिस्थितियों में अन्यथा अनुमित न दी गई हो, तब तक म्राकस्मिक छुट्टी किसी ग्रन्य प्रकार की छुट्टी के ग्रनुक्रम में या उसके साथ मिलाकर नहीं ली जा सकती ।

(3) उप-िधनियम (1) और (2) के धधीन छुट्टी प्रवान करने का शक्ति प्राप्त प्राधिकारी, कर्मचारी को किसी प्रकार की छुट्टी केसाथ मिलाकर उसेस्वीकार्य किसी भ्रन्य प्रकार की छुट्टी प्रदान कर सकता है धौर छुट्टी के बिना ग्रनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिणत कर सकता है ।

129. छुट्टी के खाते का रख-रखाव श्रौर ली गई छुट्टी का रिकार्ड

प्रधान कार्यालय में प्रशासन प्रभाग के प्रभारी प्रधन्धक द्वारा प्रधान कार्यालय में कार्यारत प्रत्येक कर्मचारी के मामले यथा निर्धारित रूप में तथा शाखा प्रवन्धक द्वारा, भीर तरीके से छुट्टियों का (भ्राकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) नियमित खाता रखा जायेगा। छुट्टी के रिकार्ड में, ''ग्रन्य बातों के साथ'' कर्मचारी की प्रदान की गई श्रौर उसके द्वारा ली गई विभिन्न प्रकार की छुट्टियां, छुट्टी स्वीकृत या प्रस्वीकृत होंने का ब्यौरा तथा रिकार्ड में दर्ज की गई प्रविष्टियों को सत्यापित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर भीर तारीख निर्दिष्ट की जायेगी।

130. छुट्टी के दौरान बेतन

(1) साधारण छुट्टी पर गया हुम्रा कर्मचारी, उसके श्रौसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा :---

बक्तर्ते कि ऐसे किसी कर्मचारी का छुट्टी वेतन, जिसे विनियम 33 के उप-विनियम (3) के अन्तर्गत साधारण छुट्टी का लाभ उठानेकी श्रनुमित दी गई हो श्रौर साथ-की सेवा में पुन: नियोजित किया गया हो श्रथवा निगम के बाहर पुनः नियो जन की भ्रनुमति दी गई हो, निगम के भ्रध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा ग्रीर ऐसे छुट्टी-वेतन की राशि इस प्रकार पुनः नियोजन पर मिलने वाले वेतन के साथ मिला कर किसी भी दणा में, उसके वेतन महित विनियम 33 के उप-विनियम (1) द्वारा यथा निर्धारित उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसके भर्द्ध-श्रीसत वेतन श्रीर उस भनुमस्य उपदान केसमकक्ष पेंशन की सीमा तक घटाये गए भक्तों की राशि से प्रधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:---इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "वेतन" में सभी प्रकार के जतन और भत्ते शामिल हैं।

(2) बीमारज की छुट्टी पर गया हुन्ना कर्मचारी पहले बारह महीने की प्रविध में ग्रीसत अर्ब-येतन के समकक्ष ग्रीर उसके बाद ग्रीसत एक चौथाई वेतन के समकक्ष छुट्टी-वेतन प्राप्त करेगा:---

बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी ने निगम में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवाकरली हो तो उसे उसकी पूरी सेवा के दौरान इस खण्ड के ग्रन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी की म्रविध की म्राधी से म्रविधक स्रविध तक वेतन पर भीर इस खण्ड के भ्रन्तर्गत स्वीकाय भ्रौसत एक-चौथाई वेतन पर छुट्टी की ग्रवधि की ग्राधी से ग्रनधिक भ्रविध तक भौसत भ्रर्क्च-वेतन पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने की भ्रनुमित दी जा सकती है तथा भ्रौसत वेतन भ्रथ**ना** भौसत भर्ब -वेतन पर इस प्रकार ली गई छुट्टी, उसके बीमारी की छुट्टी के खाते में, जास्तव में ली गई बीमारी की छुट्टी की मबिध की दुगुनी भवधि के रूप में दर्ज की जायेगी।

इसके म्रतिरिक्त, परन्तु यह कि श्रेणी—111 श्रीर IV कम-चारियों के मामले में क्षेत्रा की समग्र श्रविध के दौरान, कर्म-चारी श्रद्ध-वेतन पर 18 महीने के लिए बीमारी की छुट्टी का पाल होगा, िति पूर्ण छुट्टी वेतन पर 9 महीने में परिणत करवाया जा सकता है।

टिप्पणी:-- "छुट्टी वेतन" का तात्पय उस मासिक वेतन से है जिसे कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले ज्यूटी पर होने के दौरान प्राप्त कर रहा था/ रही थी।

इसके ग्रतिरिक्त, कमचारिवृन्द विनियमों के विभिन्न विनियमों में ग्राने वाले शब्द ग्रस्थायी कर्मचारी या श्रस्थायी कमचारियों को परिवीक्षाधीन कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित कर विया गया है।

- (3) विशेष छुट्टी पर गया हुआ कर्मचारी पहले छह महीते के दौरान श्रौसत श्रार्क-वेतन के समकक्ष श्रौर उसके बाद श्रौसत एक-चौथाई वेतन के समकक्ष छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा।
- (4) ग्रध्ययम के लिए छुट्टी पर गमा हुन्ना कर्मचारी ग्रीमत प्रर्श्व-वेतन के बराबर छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा।
- (5) प्रसूति छुट्टी पर गई हुई महिला कमचारी ग्रौसत वेतन के बराबर छुट्टी-वेतन प्राप्त करेगी।
- (6) भ्रसाधारण छुट्टी के दौरान कर्मचारी कोई वेतन प्राप्त नहीं करेगा और ऐसी छुट्टी पर बिताई गई श्रवधि को वेतनबृद्धि के लिए हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

परन्तु---

- (i) यदि वेतनवृद्धि मंजूर करने का शक्ति प्राप्त प्राधि-कारी द्राश्वस्त हो जाए कि असाधारण छुट्टी बीमारी के कारण अथवा कर्मकारी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से ली गई थी, सो प्राधिकारी, ऐसी असाधारण छुट्टी की अवधि को वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में लेने की अनुमति देसकता है; और
- (ii) जिन मामलों में देर से काने के कारण क्रसाधारण छुट्टी जब्त कर ली जाती है उनमें इस प्रकार जब्त की गई छुट्टी की घ्रवधि, ऐसी घ्रवधि के रूप में नहीं मानी जायेगी जो वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में न ली जाती हो भ्रथवा जिसके सम्बन्ध में कोई वेतन या भक्ते क्रतुमस्य न हों।

(7) इस विनियम में 'भौसत वेतन' भभिन्येक्ति से निम्क-लिखित भभिमेत होगा:

किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मामले में साधारण छुट्टी पर जाने के तत्काल पूर्व उसके द्वारा लिया जाने बाला बेतन।

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति पर या भारत से बाहर बाह्य सेवा में बिताई गई किसी प्रविध के सम्बन्ध में ग्रीसत वेतन का हिसाब लगाते समय बास्तव में लिए गए वेतन के स्थान पर वह बेतन प्रतिस्थापित किया आयेगा जो उसे तब प्राप्त हुन्ना होता जब वह भारत में निगम में क्यूटी पर होता।

- (i) उस स्थायी पद का वेतन जिस पर कर्म घारी मूल रूप से नियुक्त हो (मर्थात् जिस पद पर उसकी पुष्टि की गई हो) प्रथवा जिस पर उसका पुनर्ग्रहणा-धिकार हो या रहेगा यदि पुनर्ग्रहणाधिकार निलस्वित न किया गया हो ग्रीर इसमें, उस पद के वेतनमान के भाग के रूप में दिखाया गया विशेष वेतन भी शामिस है;
- (ji) उस पद का वेतन िस पर कर्मचारी को इस मर्त के प्रधीन स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया है कि वह छुट्टी पर जाने के समय लगातार तीन वर्ष से ग्रधिक के लिए स्थानापन्न नियुक्ति पर रहा हो। तीन वर्ष की सीमा में मिम्नलिखित भामिस होगा।
 - (क) छुट्टी की ऐसी सभी 'मन्निधयां जिनके दौरान कर्मकारी उस पद पर स्थानापस्न होता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता; श्रीर
 - (ख) किसी समकक्ष प्रथवा उससे उच्च पद, जिस पद नियुक्त न होने पर वह स्थानापन्न रूप से नियुक्त हुआ होता, पर की गई स्थानापन्न सेवा की सभी ग्रवधियां।

खण्ड IV---काय-ग्रहण भ्रवधि

131. कार्य-ग्रहण श्रवधि

कर्मचारी को काय-ग्रहण अवधि निम्निसिखित उद्देश्यों केलिए प्रदान की जा सकती है:---

- (क) अपने पुराने पद पर रहते हुए नियुक्त किए गए नए पद का कार्य-ग्रहण करने के लिए; अथवा
- (ख) चार महीने से ग्रनिधक ग्रविध की छुट्टी से लौटने पर नए पद का कार्य-ग्रहण करने के लिए;ग्रथका

- (ग) खण्ड (ख) में निर्विष्ट छुट्टी से भिन्न छुट्टी से लीटने पर, यदि कर्मचारी को नए पद पर उसकी नियुक्ति की पर्याप्त सूचना प्राप्त न हो, तो नए पद का कार्य-ग्रहण करने के लिए; प्रथवा
- (ष) बाह्य नियोक्ता के अधीन प्रतिनियुक्ति किए जाने पर उक्त नियोक्ता के अधीन सेवा के लिए पद का कार्य ग्रहण करने और ऐसी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात् निगम की नियुक्ति में वापस आने के लिए परन्तु, यदि कर्मचारी के मुख्यालय में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो कार्यग्रहण अवधि प्रदान न की जायेगी।

132. स्वीकार्य कार्य-ग्रहण भवधि

(1) कमचारी को प्रदान की जाने वाली कार्य-ग्रहण अवधि सात दिन से अधिक नहीं होगी और सम्बन्धित पद या नियुक्त का कार्य-ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए यात्रा पर बिताए गए दिन इसके अतिरिक्त हैं।

परम्तु, यदि कर्मचारी के ग्रयमे श्रनुरोध पर उसे एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो निगम की स्वेष्छा से कार्य-ग्रहण श्रवधि कम की जासकती है।

स्पच्टीकरण:--याज्ञा पर विताए गए समय का हिसाब क्याने के प्रयोजन के किए "एक दिन" से अभिप्रेत होगा प्रस्थान के समय ने गुरू होने वाले 24 घंटे या उसकी कोई फ्रांशिक प्रविध ।

(2) यदि कर्मचारी एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर स्थानास्तरण होने की स्थिति में काय-प्रहण अविध का उपयोग
महीं करता अथवा निगम की संवाझों की आवश्यकताओं के
कारण कार्य-प्रहण अविध कम कर दी गई है, तो उसे नए केन्द्र
पर रिपोर्ट करने की तारीख के किसी समय बाद परन्तु 6
महीने की अविध रें पूर्व अथवा निगम द्वारा सहमत हुई उसके
परिकार अथवा उसके घरेलू सामान के सम्बन्ध में पूरक यात्रा
बिल प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाई गई अविध में उपयोग न
किए गए कार्य-प्रहण अविध की सीमा के अधीन अधिकतम
सात दिन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमित
दी जा सकती है बहार्ते कि उसने इस प्रकार की सूचना स्थानासरण पर जाने से पूर्व निगम को देवी हो। इस प्रकार के विशेष
आकस्मिक अवकाश से पहले और/अथवा मध्य में आने वाले
रिविदारों/छुट्टियों को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में
गणन किया जायेगा।

133. कार्य-ग्रहण ग्रवधि का गणन

- (1) कर्मचारी को स्थीकार्य कार्यग्रहण श्रवधि का गणन करते समय उसे उसके पुराने पद से भारमुक्त किए जाने के दिम को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि कार्य-ग्रहण श्रविध के बाद सार्वजिनक छुट्टी (छुट्टियां) श्राती (हों) हों तो सामान्य कार्य-ग्रहण श्रविध को उस छुट्टी (छुट्टियां) मिलाकर बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

- (3) यदि किसी कर्मचारी को उसके पिछले पद से कार्य-मुक्त कर दिया गया हो अथवा उसके मुख्यालय से अन्यन्न उसके पिछले पद का कार्य-भार सौंपने के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो उसकी कार्य-प्रहण अवधि का गणन उस स्थान से किया जायेगा ज्रहां से उसे कार्य-मुक्त किया गया हो या जहां उसने कार्य-भार सौंपा हो।
- (4) यदि भ्राकिस्मिक छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी पर गए किसी कर्मचारी को नए पव पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी कार्य-ग्रहण भ्रविध का गणन उस कार्य-स्थल से, जहां से वह छुट्टी पर गया हो भ्रथवा उस स्थान से जायेगा जिस स्थान पर उसे ऐसी नियुक्त का श्रादेश प्राप्त हो, जिस की तरीके से वह कम कार्य-ग्रहण भ्रविध का हककार होगा:

परन्तु, यदि कर्मचारी यह प्रमाणित करता है कि उसे उसके निजी कार्यों, ग्रादि को निपटाने के लिए उसके पुराने मुख्यालय पर बापस लौटना था तो उसकी कार्य-ग्रहण प्रविध का गणन, उस स्थान पर ध्यान दिए बिना जहां उसने ग्रपनी छुट्टी बिताई थी या तैनाती-ग्रादेश प्राप्त किए थे, पुराने मुख्यालय से लगाया जायेगा।

134. कार्य-प्रहण अवधि के साथ संयोजन का नियमन

कार्य-ग्रहण श्रवधि के छुट्टी के साथ संयोजन निम्नानुसार नियमित किया जायेगा :----

- (क) यदि काय-प्रहण श्रवधि के साथ ग्राकस्मिक छुट्टी मिलाने की श्रनुमित दी जाए तो पहले कार्य-प्रहण श्रवधि शुरू होगी धौर श्राकस्मिक छुट्टी कार्य-ग्रहण तथा यात्रा पर बिताए गए समय की समास्ति पर शुरू होगी। ऐसी श्राकस्मिक छुट्टी की श्रवधि के तत्काल पहले या बाद श्राने वाली कोई सार्य-अनिक छुट्टी कार्य-ग्रहण श्रवधि या श्राकस्मि कः छट्टी में शामिल नहीं की जायेगी।
- (ख) यदि कार्य-प्रहण भ्रवधि के साथ किसी भ्रन्य प्रकार की छुट्टी मिलाने की श्रनुमति दी आए तो कार्य- प्रहण भ्रवधि उस छटेटी की समाप्ति से शरू होगी तथा उसके बाद काय-प्रहण भ्रवधि के भ्रनुकम में भ्राने वाली सार्वजनिक छुट्टियों से भिन्न मध्यवर्ती सावजनिक छट्टियां कार्य-प्रहण भ्रवधि में शामिल की जायेंगी।

135. सीमा से मधिक कार्य-ग्रहण मनधि

विशेष परिस्थितियों में श्रध्यक्ष की मंजूरी से इन विनि-यमों में निर्धारित सीमा से श्रधिक कार्य-ग्रहण श्रविध प्रदान की जा सकती है।

136. कार्य-प्रहण प्रवधि के बाद प्रतिरिक्त समय तक रुकना

जो कर्मचारी कार्य-ग्रहण श्रवधि श्रौर उस प्रयोजन के लिए उसे स्वीकार्य या ग्रनुमत्य यात्रा पर बिताई गई श्रवधि समाप्त होने के तत्काल बाद, श्रथवा ऐसी कार्य-ग्रहण श्रवधि के ग्रनुक्रम में प्रदान की गई छुटटी ग्रौद याह्ना पर बिताई गई स्रवधि समाप्त होने के बाद स्नाने वाले कार्य-दिवस को प्रपने पद का कार्य-प्रहण नहीं करता, वह ऐसी स्नवधि समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति की किसी स्रवधि के लिए वेतन स्नौर भन्नों का हकदार नहीं होगा तथा ऐसी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विनियम 57 का उल्लंघन किया माना जायेगा।

137. कार्य-ग्रहण भ्रवधि के दौरान वेतन भ्रौर भत्ते

कार्य-प्रहण प्रविध के दौरान कर्मधारी के वेतन ग्रौर भरो विनियम 83 के ग्रनुसार निर्धारित किए जायेंगे।

ग्रध्याय 7--चिकित्सा सुविधाएं

138. चिकित्सा सुविधाएं

(1) निगम ध्रपने कर्मभारियों श्रीर उनके परिवारों के लिए उस सीमा तक श्रीर उस ढंग से चिकित्सा सुविधाश्रों की व्यवस्था कर सकता है जैसी कि बोर्ड बारा समय-समय का पर श्रनुमोदित किसी योजना में व्यवस्था की गई हो।

परन्तु ऐसी सुविधाएं सामान्यतः जहां तक सम्भव हो, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य हैसियत के कर्मणारियों को उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में होगी।

- स्पष्टीकरण: ---इस श्रध्याय के प्रयोजनों के लिए "परिवार" श्रिभव्यक्ति में, कर्मचारी की पत्नी या पित, जैसी भी स्थिति हो, सन्तान, सौतेली सन्तान श्रौर माता-पिता जो सम्बन्धित कर्मचारी पर मुख्य रूप से श्राश्रित हों, शामिल होंगे।
- (2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, निगम के जिन कर्म चारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के० स० स्वा० यो०) की सुविधा दी गई है अथवा दी जा सकती है, वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर हिताधिकारियों के लिए यथा-निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।
- (3) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के श्रन्तर्गत न ग्राने वाले स्टाफ सदस्यों के मामले में उन्हें वी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय सेवायें (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के श्रनुसार होंगी।

ग्रध्याय 8--बाह्य सेवा

139. सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति

जिन शतों के भिधीन कमचारी को सैनिक सेवा में भर्ती होने की धनुमति दी जा सकती है, उनका निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

140. अन्य सेवाओं में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

(1) विनियम 139 के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, निगम का कोई घी कर्मचारी, किसी भ्रन्य नियोक्ता के भ्रधीन सेवा करने के लिए श्रध्यक्ष के भ्रनुमोदन के बिना प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा और ऐसी प्रतिनियुक्त की अविध और शतों का निर्धारण प्रध्यक्ष द्वारा किया जायेगा —

परन्तु किसी घी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाह्य सेवा में स्थानान्तरित न किया जाये।

- (2) जिन मामलों में निगम के कर्मचारी की सेवायें किसी बाह्य नियोक्ता को उपलब्ध कराई जायें, उनमें प्रतिनियुक्ति की श्रवधि के दौरान बाह्य नियोक्ता, समय-समय पर यथा संशोधित इन विनियमों के श्रन्तर्गत या निगम में कर्मचारी की सेवा के सम्बन्ध में लागू शतों के श्रनुसार श्रमुमत्य श्रथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्रन्यथा निर्धारित, कर्मचारी का समग्र वेतन श्रौर भन्ते तथा इन विनियमों के श्रधीन कर्मचारियों की सेवाभों की श्रन्य सारी लागत वहन करेगा जिनमें "श्रन्य वातों के साय-साथ" निम्नलिखित भी शामिल होंगे :—
 - (क) कार्य-प्रहण प्रवधि के वौरान वेतन भौर भत्ते :
 - (ख) बाह्य नियोक्ता के ग्रधीन ग्रपने पद का कार्य-भार ग्रहण करने तथा प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर निगम में भ्रपने पद पर लौटने के लिए कर्मचारी को देय यात्रा भक्ता:
 - (ग) प्रतिनियुक्ति की भवधि के दौरान भ्राणित छुट्टी;
 - (ध) निगम की भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता का श्रंशदान;
 - (ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा में उपदान या ऐसी किसी भ्रन्य राशि, जिसका कर्मचारी भ्रपनी सेवा-निवृत्ति के समय पात्र होगा, के लिए श्रंशदान;
 - (च) यदि कर्मचारी निगम के किसी अन्य सेवा-निषृत्ति लाभ का हकदार हो तो, कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उस लाभ के संदर्भ में निगम का दायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जायेगी;
 - (छ) प्रतिनियुक्ति की श्रवधि के श्रनुपात में छुट्टी किराया रियायत की सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागत;
 - (ज) यदि बाह्य नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधाश्रों की व्यवस्था न हो तो इन विनियमों के श्रधीन उपलब्ध की जाने वाली चिकित्सा सुविधाश्रों की लागत।

141. बाह्य नियोक्ता द्वारा प्रदत्त श्रंशदानों में कोई श्रधिकार नहीं होगा

बाह्य सेवा में कोई कर्मचारी श्रंशदान देने से इंकार नहीं करेगा और बाह्य सेवा में बिताए गए समय को निगम की सेवा में ड्यूटी के रूप में मानने के श्रधिकार को जब्त करने का भयन नहीं कर सकता। नहीं कर्मचारी धीर नहीं बाह्य नियोक्ता को, प्रदत्त श्रंशवान में समाप्ति का श्रधिकार होगा तथा उसकी वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। 142. आह्य सेवा पर गए कर्मचारी बाह्य नियोक्ता से पेंशन या उपदान स्वीकार नहीं करेंगे:

बाह्य सेवा में स्थानान्तरित कोई कर्मचारी, निगम की मंजूरी के बिना ऐसी सेवा के सम्बन्ध में अपने बाह्य नियोक्ता से पेंशन या उपवान स्वीकार नहीं करेगा।

143. बाह्य सेवा के दौरान छुट्टी

आह्य सेवा में कर्मचारी को इन विनियमों से अन्यथा छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकती और वह तब तक निगम से छुट्टी या छुट्टी वेतन नहीं ले सकता जब तक वह वास्सव में इयूटी नहीं छोड़ देता और छुट्टी पर नहीं जाता।

144. निगम में स्थानापन्न नियुक्ति होने पर बाह्य सेवा में लिए जाने वाले वेतन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा

यवि ब्राह्म सेवा ; गया कोई कर्मचारी निगम में किसी पद पर स्थानापम्न रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो वह निगम में उस पद के वेतन, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा उसका पुनर्ग्रहणाधिकार निलम्बित होने पर जिस पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता, और उस पद के वेतन, जिस पर वह स्थामापन रूप से नियुक्त है, के आधार पर परिकलित वेतन प्राप्त करेगा। उसका वेतन निर्धारित करते समय बाह्म सेवा में उसके वेतन पर विचार नहीं किया जायेगा।

145. बाह्य सेवा से प्रत्यार्वतन

- (1) कोई कर्मचारी, निगम में अपने पद का कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से, बाह्य सेवा से निगम की सेवा में प्रत्यावर्तित हो जाता है, परन्तु यदि वह अपने पद का कार्य-भार ग्रहण करने से पहले बाह्य सेवा की समाप्ति पर छुट्टी ले लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित तारीख से लागू होगा।
- (2) जब कोई कर्मचारी बाह्य सेवा से निगम की सेवा में प्रत्यावर्तित हो जाता है तो बाह्य नियोक्ता द्वारा उसके वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा और प्रत्यावर्तन की तारीख से उसका अंगदान बन्द कर दिया जायेगा।

अध्याय IX---विविध

146. भिषष्य तथा अन्य हितकारी निधियों में अभिदाम करने की बाध्यता

जब तक बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रत्येक कर्मचारी सम्बन्धित निधि के विनियमों की अपेक्षा के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य हितकारी निधियों, यदि कोई हों, का सदस्य बनेगा और उन निधियों के विनियमों के अधीस वाध्यता स्वीकार करेगा।

147. निगम द्वारा प्रारम्भ बीमा योजनाया निधि में अभिदान करने की बाध्यता

निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए जो भी बीमा योजना या निधि प्रारम्भ करे उसमें अभिदान करना प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए, जो इन विनियमों से बाध्य है, अत्यावश्यक होगा और वह उक्त योजना या निधि के नियमों से बाध्य होगा:

परन्तु, इस विनियम में निहित कोई भी बात किसी कर्म-चारी को अन्यथा अनुमत्य निवृत्ति लाभों में कटौती महीं करेगी;

परन्तु, इस विनियम में निहित कोई भी बात, किसी कर्मचारी से उक्त योजना या निधि में उस हालत में अभिवान करने की अपेक्षा नहीं करेगी जब उक्त योजना या निधि के नियमों के अधीन उसे ऐसा करने से छूट वी गई हो।

148. ये विनियम, सिवास अपनाई गई सीमा तक वर्तमान विनियमों और सम्बन्धित आदेशों, प्रशासनिक अनुदेशों आवि का अधिलंघन करेंगे

ये विनियम, वर्तमान विनियमों के उपबंधों और निगम के कर्मचारियों के कर्त्तच्यों, आचरण, घेतन, भत्तों और सेवा-शर्तों को नियमित करने के लिए उनके अन्तर्गत जारी किए गए सभी सम्बन्धित आदेशों, प्रशासनिक अनुदेशों, आदि का अधिलंघन करेंगे:

परन्तु बोर्ड या अध्यक्ष, जैसा कि इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत किया गया है, इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पहली तारीख को लागू विनियमों के उपबंध या उपबंधों, आदेशों, प्रशासनिक अनुदेशों और व्यवस्थाओं को अपना सकता है अथवा ऐसे गौण मामलों की व्यवस्था कर सकता है जिनकी व्यवस्था इन विनियमों में न की गई हो अथवा इन विनियमों में न की गई हो अथवा इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नए अनुदेशों या कार्य-विधियों, व्यवस्थाओं, नीतियों, फामों, आदि के जारी किए जाने के समय तक इन विनियमों के अधीन कार्यविधियों, व्यवस्थाओं, नीतियों, फामों, आदि को जारी रख सकता है, अपना सकता है या बनाए रख सकता है।

149. संक्रमणकालीन उपबंध

विनियम 1 के उप-विनियम (2) और विनियम 148 में, जहां इन विनियमों के अधीन कुछ मामलों के सम्बन्ध में, अथवा ऐसे कुछ गौण मामलों के सम्बन्ध में जिनकी व्यवस्था इन विनियमों में न की गई हो, बोई या अध्यक्ष द्वारा कुछ उपबंध, वेतनमान, दरें, कार्यविधियों, व्यवस्थाएं, फार्म, आवि अपनाए जाने या निर्धारित किए जाने होते हैं, निहित किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों हारा लागू बोई या अध्यक्ष की शक्तियों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना और किसी प्रतिकृत अधिश के न होने पर इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय वास्तव में लागू उपबंध, वेतनमान, दरें, कार्यविधियां, व्यवस्थाएं,

फार्म, आदि लागू रहेंगे और इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से वह महीने की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वैधता के साथ लागू रहेंगे।

150. पुराने या अन्यथा निपटाए जा चुके मामलों को दोबारा खोलने के लिए इन विनियमों को लागू नहीं किया जायेगा

जब तक किसी मामले में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, किसी भी परिस्थित में पुराने या अन्यथा निषटाए जा शुके मामले, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित किए जाने के लिए दोबारा खोले नहीं जायेंगे सथा निलम्बित मामलों का निर्णय, विनियम 149 के अधीन लागू संक्रमणकालीन उपबंधों या इन विमियमों के उपबंधों, जैसा भी उचित समझा जाए, को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। 151. कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और म की जाने वाली घोषणाएं

ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, विनियम 2 में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित फार्म "क" में देश और विधि सम्मत संविधान के प्रति सत्य-निष्ठा की शपथ ग्रहण करेगा और फार्म "ख" और "ग" में घोषणाएं भी करेगा:—

फार्म "क"

देश और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ

"मैं, सत्यनिष्ठा से श्रपण केता हें नि मैं भारत हैं जोर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के प्रति और विधि सम्मत संविधान के प्रति निष्ठावान होऊंगा, और सस्य निष्ठ रहूंगा, कि मैं भारत की प्रभुसत्ता और अर्खंबता बनाए रखूंगा और कि मैं अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक ईमानदारीपूर्वक और निष्पक्षता से करूंगा।

(भन्नवान मेरी सहायता करे)"	
	(हस्ताक्षर)

फार्म−"ख"

दिनांक

कर्मचारिवृत्व विनियमों द्वारा बाध्य होने के सम्बन्ध में घोषणा

स्यान					•	•	•	
दिनांक								

मैं एतद्दारा यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय शौधोगिक वित्त निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1974 को पढ़ और समझ लिया है और मैं एतद्दारा उक्त विनियमों के अधीन बाध्यसा स्वीकार करता हूं।

							•						
पूरा नाम				٠		•		•		•	٠		
ब्रियुषित कास्वरूप							٠				•	•	•
विवृक्तिस की दारीस		•	•		•	•	•	•	•	•	٠	•	•
प्रस्तावार						٠		,		•			•

फार्म-"ग"

विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा

में, शोषणा करता हूं कि
मैं वफादारी, सच्चाई और अपनी सर्वोक्तम विवेक-बुद्धि, कौसल
और योग्यता से उन कर्त्तन्यों का निष्पादन और पालन करूंगा
जो भारतीय औद्योगिक विश्व मिगम के कर्मचारी के रूप में
मुझसे अपेक्षित हैं और जो उक्त निगम में मेरे द्वारा धारित
किसी पद या हैसियत से उचित रूप से सम्बन्धित हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं निगम के कार्यकलाओं से सम्बन्धित कोई जानकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को सूचित नहीं करूंगा या नहीं होने दूंगा, जो वैध रूप से उसका हकदार न हो और न मैं ऐसे किसी व्यक्ति को, निगम से सम्बन्धित या उसके करूजे में और निगम के कारोबार से सम्बन्धित किन्हीं भी बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा और न उन तक उसकी पहुंच होने दुंगा।

(हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

दिनांक

परिशिष्ट

भत्त

- (1) निगम के कर्मचारी, भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आगू होने वाले और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अथनाई मई बरों पर और लागू शतों के अधीन निम्नलिखित भत्तों के पास होंगे:
 - (i) महंगाई भसा
 - (ii) मकान किराया भशा
 - (iii) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता
 - (iv) परिवार भत्ता
 - (v) स्थानीय वेतन
- (vi) निगम के कर्मधारी, दौरे पर रहते समय याद्रा भत्ते और विराम भत्ते तथा स्थानांतरण होने पर याद्रा भत्ते के भी पाल होंगे। जब तक इस सम्बन्ध में संचालक बोर्ड द्वारा नए नियम नहीं बना लिए जाते तब तक इन भत्तों की अदायगी के गियमन के लिए इन विनियमों के प्रभावी होते से पहले लागू नियम जारी रहेंगे।

STATE BANK OF INDIA 1 2 3 4 CENTRAL OFFICE 3. 70064 Shri Sunil Kumar Gupta, 1-1-87 Bombay, the 14th August 1987 ACA, Kothi No. 3348, Sector -23-D, ADM/35570.—The following appointment on the Bank's Chandigarh-160023. Staff is hereby notified: 4. 82032 Shri Setjit Singh, 1-4-87 Shri S.V. Chetty, Officer, Тор Fxecutive Grade ACA, Hency Freight Ltd., Hency House, Ascot Road, Scale VI has assumed charge as Dv. General Manager (Provident Fund), Central Office as at the close of the business on August 8, 1987. Bedfont, Feltham, Sd/- ILLEGIBLE CHIEF GENERAL MANAGER Middlesex TW 148QH (Personnel and H.R.D.) Shri Pankaj Gupta, 5. 82444 4-5-87 ACA, C-60 N.D.S.E., Part I, New Delhi. ALLAHABAD BANK HEAD OFFICE: 2, NETAII SUBHAS ROAD 6 83018 Shri Rajan Chowdhry, 1-4-87 ACA, A-3/68, Paschim Vihar Calcutta-700 001, the 19th August 1987 No. Legal/1/87-GSR.—In exercise of the nowers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the New Delhi-110063. 7. 83280 Shri Rahul Sanon, 1-4-87 Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regula-tions further to amend the Allahabad Bank (Officers') Ser-ACA, M/s Home Builder Syndicate, Jindal Trust Building. Asaf Ali Road, New Delhi-110002. vice Regulations, 1979. 2. Short title and commencement: -- (1) These regulations 8. 84667 Shri Bimal Kumar Luthra, 1-4-87 may be called the Allahabad (Amendment) Regulations, 1986. Allahabad Bank (Officers) Service II-B/10, I.A.R.I., Pusa Institute, (2) This has come into force w.c.f. 25-7-1986. 3. After second proviso to Sub-regulation (1) of Regulation 19 of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations 1979, the following proviso has since been added, namely:— New Delhi-110012. 9 84822 Shri Gulshan Kumar Sethi, 6-3-87 ACA A-55, Subhadra Colony, "Provided further that an officer aggrieved by the order of Sarai Rohilla, the Competent Authority, as provided in Sub-regulation (2), Delhi-110035. may, within one month of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against the decision of the Competent Authority, and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three months. Where the Board of Directors decides that the order passed by the Competent Authority is not justified, the concerned officer shall be reinstated as though the Competent Authority has not passed the order." writing a representation to the Board of Directors against the Shri Naveen Bhushan Gupta, 10. 84864 9-4-87 ACA 862, Vikash Punj Vikas Puri, New Delhi-110013. 11. 84899 1-4-87 Mrs. Anita Anand, ACA, B-93. Amar Colony, Lajpet Nagar IV, M. R. SARBADHIKARI New Delh. Asstt. General Manager (Law) Mrs. Neeraj Ghei, ACA, D-232, Defence Colony, 12. 85103 1-3-87 THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF New Delhi-110024. INDIA 85357 Shri Sanjeev Kamal, 1-4-87 13. New Delhi-110002, the 21st August 1987 ACA 35A, Single Storey (CHARTERFD ACCOUNTANTS) Ramesh Nagar, New Delhi. 3NCA (8)/2/87-88.—In pursuance of Regulation 10 (1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the certificate of Practice issued to the following members has been cancelled from the dates mentioned against Shri Manohar Lal, ACA, C-16/75A, Lawrence Road, 14. 85725 18-2-87 their names as they do not desire to hold the same. Delhi-110035. No. 3NCA (8)/3/87-88.—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10 (1) read with Regulation 10 (2) (b) of the Chartered Accountant Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August, 1986 as they had not paid their annual fee for Certificate of Practice for the year 1986-87. Member-Name and Address Date of No ship No Cancellas

1401	Ship 1807		tion
1	2	3	4
1.	17785	Shri Pratish Narayan Bhattacharjee, FCA, 7371, F.N. Ghthawk Chele, Anahe in 92807, California (U.S.A.).	1-4-1987
2	24562	Shri Vaddiparti Bhaskar, ACA, C/o M/s Ferro Al- loys Corpn. Ltd., Shreeram Nagar-532101, Distt. Vizianagram. (A.P.).	

Sl. MemberNo. ship No.

1 2 3

1. 8J284 Shri Gurmeet Singh Arora,
1°CA D-305,
Anand Vihar,
Delhi-110092.

1	2	3		1	2	3
2.	83057	Shri Chandra Parkash Bahri, ACA 152, Shakti Vihar, Dclhi-110034.		8.	82654	Shri Rajesh Kumar Arora, ACA 44/A, Single Storey, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
3.	83991	Shri Purneshwar Shrestha, ACA 8/199, Makhan Tole, Kathmandu, Nopal.		9.	82859	Shri Rajesh Bansal, ACA B-XX-364, Baba Balak Nath Mandir, Ghumir Mandi, Ludhiana.
4.	84546	Shri R. Ramani, ACA D-658, DIZ Area Mandir Marg.,		10.	82905	Shri Sunil Datt Uppal, ACA F-5. Nizamuddin West, New Delhi-110013.
		New Delhi-110001. The 24th August 1987		11.	83036	Shri Raj Kamal Goel, ACA 14A/79, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005.
ii) of	CA (8)/4/87-8 the Chartered	RTERED ACCOUNTANTS 18—In pursuance of Regula 1 Accountant Regulation, 196	ation 10 (1)	12.	83353	Shri Madhu Vennalaganti, ACA 74, DDA MIG Flats,
		rtificate of Practice issued to cancelled from the date ment	the following			Prasad Nagar, New Delhi-1 10005.
embe icir n	ers has been o		the following ioned against	13.	83438	Prasad Nagar,
embern leir n	Member- ship No.	Name and Address Shri Rajesh Kumar Saxena, FCA, P.O. Box 50584, Lusaka, Zambia.	Date of Cancellation	13. 14.	83438 33998	Prasad Nagar, New Delhi-1 10005. Shri Rakesh Kumar Arora, ACA DA/115A. LIG Flats, G-8 Area, Hari Nagar, New Delhi-1 10064. Shri Bhupinder Singh, ACA C/o Ernst & Whinney, P.O. Box 9267,
emb	ers has been cames as they Membership No.	Name and Address Shri Rajesh Kumer Saxena, FCA, P.O. Box 50584, Lusaka,	Date of Cancella-			Prasad Nagar, New Delhi-110005. Shri Rakesh Kumar Arora, ACA DA/115A. LIG Flats, G-8 Aroa, Hari Nagar, New Delhi-110064. Shri Bhupinder Singh, ACA C/o Ernst & Whinney,

SI. No.	Member- ship No.	Name and Address
1	2	3
1.	80079	Shri Karan Anand, ACA, E-160, Masjid Moth, New Delhi-110048.
2.	81211	Shri Krishuaswami Srinivasan, ACA 9A/51, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110003.
3.	81661	Shri Nirbhaya Lodha, FCA 785, Mukerjee Nagar Near Batra Cinema, New Delhi.
4.	81721	Shri Rakesh Kumar, ACA D-23, Hauz Khas, New Delhi.
5.	81825	Shri Raj Pal Gandhi, ACA/9/26, Moti Nagar, New Delhi.
6.	82005	Shri Sanjeev Kumar Sin- ghal, ACA 4726, Deputy Ganj, Sadar Bazar, Delhi-110006.
7.	82543	Shri Chavijit Singh Bawa, ACA 532, Sector 8-B, Chandigarh-160008.

No. 3NCA (8)/6/87-88—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10 (1) read with Regulation 10 (2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following member shell stand cancelled with effect from 1st August, 1981 as he had not paid the annual fee for Certificate of Practice for the year 1981-82.

Sl. No.	Member- ship No.	Name and Address
1.	11759	Shri Vorshal Handa, ACA P.O. Box-9, 1 Keja (Lagos), Nigeria.

No. 28-RC(2)/25/87—In pursuance of Regulation 136 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, is pleased to notify the setting up of a branch of the Southern India Regional Council at Quilon with effect from 18th July, 1987.

The Branch shall be known as Quilon Branch o' the Southern India Regional Council.

As prescribed under Regulation 136(3) the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council,

No. 28-RC(5)/7/87.—In pursuance of Regulation 136(2) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Northern India Regional Council at Jammu with effect from 18th July, 1987.

The	Branch shall	be known as Jammu Bra	nch of the	·	······································		
Norther	n India Reg	ional Council.	nen of the	1	2	3	4
function the Cou	subject to incil through h directions	der Regulation 136(3) the the control, supervision and the Regional Council and as may from time to time to	direction of shall carry	6.	70093	Shri Varinder Kumar, A.C.A., M/s. Indeco Ltd., P. Box 31935,	14-5-87
No the Cha fied tha (a) of	3NCA (4)/1 artered According in exercise the Charter	/87-88:—In pursuance of Regu untants Regulations, 1964, it is of the powers conferred by s ed Accountants Act, 1949, the	hereby noti- section 20(1) Council of			Lusaka—Zambia. Shri Varinder Kumar, A.C.A., C/o Sh. Yash Pal Verma, Gandhi Gate, Dina Nagar-143531	
		tered Accountants of India has renders of the Institute on accoun				(Punjab).	
		lowing members with effect from their names:—	m the dates	7.	80968	Shri Rakesh Kumar Gupta, F.C.A.,	21-4-87
Sl. No.	Member-	Name and Address	Date of			S.C.O. 1116, Sector 22-B, Chandigarh-160022.	
<u>-</u>	ship No.	Shri Kishen Prasada Soni, M/s Soni, Chatrath & Co.,	17-1-87	8.	81362	Shri Manohar Lal, A.C.A., S.C.O. 10-4-95, Sector 22-B, Chandigarh-160022.	4-5-87
		Chartered Accountants, 15, Asaf Ali Road, New Delhi-110002.		9.	82009	Shri Rakesh Kumar Mangla, A.C.A., 8/11, South Patel Nagar, New Delhi.	18-5-87
2. _	2906	Shri Mohinder Pal Puri, 118, Malcha Marg, New Delhi.	28-6-87	10.	82874	Shri Arun Tuli, A.C.A., J-37 (G/F), N.D.S.E. Part I, New Delhi-110049.	16-6-87
3.	81443	Shri Arvind Chowdhary, 47-C/C, Gandhi Nagar, Jammu-180004.	3-7-87	11.	82877	Shri Rajan Soni, A.C.A., 18/3, Shakti Nagar, Delhi-110007.	11-5-87
4.	82823	Shri Naresh Kumar Sood, 90, Golf Links, (1st Floor), New Delhi-110003.	17-4-87			Shri Rajan Soni, A.C.A., 4710, Arbor Drive, Apt. 203, Rolling Meadows, IL 60008 (U.S.A.),	
5.	85904	Shri Vinod Kumar Arora, J-II, 112B, DDA Flats, Kalkaji, New Dell'i-110019.	14-6-87	12.	82889	Shri Ashwani Kumar, A.C.A., B-I/103, Lajpat Nagar, New Delhi-110024.	27:2-87
tute's N (1)/19/7 3-CA (31-3-80, Charter powers	lotification N 2-73 dated 1 4)/15/82-83 d it is hereby red Accountar conferred by	/1/87-88.—With reference to los. 3 NCA (4)/9/83-86 dated 31 (7-1-73, 3 NCA (4)/3/86-87 datated 30-3-83 and 4CCA (7)/motified in pursuance of Regulations, 1964, that in excregulation 17 of the said Regulation 17 of the said Regulation 18 (4)/4 (4)	-3-86, 4 CA ted 27-2-87, 79-80 dated lon 18 of the ercise of the ulations, the	13.	83621	Shri Alok Tandon, A.C.A., M/s. R.K. Sharma & Associates, Chartered Accountants, 126, Golf Links, New Delhi-110003.	23-4-87
Council restored	of the Instit to the Regis led against th	ute of Chartered Accountants of Members, with effect from the names of the following t	of India has om the dates	14.	83716	Shri Krishan Kumar Gupta, A.C.A., B-4, Lajpat Nagar II, New Delhi-110024.	2-6-87
SI. No.	Member- ship No.	Name and Address	Date of Restoration	15.	83759	Shri Rohit Kapoor, A.C.A., 191, Flyover Market, Delence Colony, New Delhi.	1-8-86
1.	1709	Shri Ram Charan Das, F.C.A., 6, Alipur Road, Civil Lines,	1-5-87	16.	83760	Shri Rahul Kapoer, A.C.A., 191, Flyover Market, Defence Colony, New Delhi.	1-8-86
2.	4053	Delhi-110054. Shri Vidya Bhushan Chadha A.C.A., E/27A, Rajouri Gardens,	ı, 13-4 - 87	17.	84224	Shri Rajeev Kumar Gupta, A.C.A., E-7/8, Krishan Nagar, Delhi-110051.	1-5-87
3.	17008	New Delhi-110027. Shri Devender Pal Kanwar, A.C.A., E-3/51, Arora Colony, Bhopal-462014.	16-4-87	-			CHOPRA Secretary
4.	15934	Shri Shiv Narain Sharma, F.C.A., 502, Katra Neel, Chandni Chowk, Delhi-110006.	8-5-87	No.	LOYEES' S' Bombay- 31-V-34-11(AL OFFICE MAIIARASHTRA TATE INSURANCE CORPOR 400 031, the 4th August 1987 51)Cord. Cell.—It is hereby no	ATION
5.	16411	Shri Narsingh Dev Sharda, F.C.A., C-77, Pushpanjali Enclave, New Delhi.	18-7-86	the Loc 31-V-34 under F (Genera	al Committe -11(51)AG. Regulation 1 (1) Regulation	te set up vide this office notific III dated 10-12-1982 for Ba 0-A-1 of the Employees' State on 1950 has been reconstituted with effect from the date of no	ation No. rshi area Insurance with the

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-A-1(a)

1. The Asstt. Commissioner for Labour, Sholapur.

Members

UNDER REGULATION 10-A-1(b)

 The Administrative Officer to the Administrative Medical Officer, E.S.I. Scheme, (W.M.R.), Aundh Camp, Pune-27.

UNDER REGULATION 10-A-1(c)

3. The Medical Officer I/C., ESIS Dispensary, Barshi.

UNDER REGULATION 10-A-1(d)

- Shri Anil Bhimashankar Bandewar, Director,
 Barshi Taluka Udyog Vikas Cooperative Society Ltd., Barshi,
 Gaonsane Bunglow Compound, Agalgaon Road, Barshi, Dist. Sholapur.
- Shri Suresh Bhagvantrao Sulave, Managing Director, The Lokmanya Mills Barshi Ltd., Barshi Town, Barshi, Dist. Sholapur, Pin Code 413 401.

UNDER REGULATION 10-A-1(e)

- Shri Kamaldas Madanlal Lohe, General Secretary, Janta Mill Mazdoor Union, Barshi, C/o. Satkar Hotel, Hald Galli, Saraf Katta, Barshi, Dist. Sholapur.
- Shri Shrikant Bhagwan Kashid, Treasurer, Rashtriya Girni Kamgar Sangh (INTUC), Barshi, Room No. 2068, Dane Galli, Barshi, Dist. Sholapur.

UNDER REGULATION 10-A-1(F)

 The Manager, Local Office Barshi, E.S.I. Corporation.

By order

B. K. GUPTA, Regional Director

CORRIGENDUM

The 28th August 1987

DISCREPANCIES FOUND IN ENGLISH VERSION GAZETTE NOTIFICATION PART-III, SECTION-4

- (1) At the page No. 2450 of English Gazette Notification there has been printed 'Regional Office Faridabad' instead of Regional Office, ESI Corporation, Faridabad.
- (2) At page No. 2450 of English Gazette notification of Local Committee, Bahadurgarh, the correct name of employer's representative may kindly be printed Sh. D. N. Sharma instead of Sh. N. D. Sharma.

By order

R. S. RAWAT Regional Director

MINISTRY OF COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 26th August 1987

NOTICE

No. 25-16/86-L1.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to

is ue duplicate policies in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. Policy No. & No. Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1, 231296-P	Shri Surl-aram	2000/-
2. 564046-C dt, 6-3-85	Shri Om Parka;h	5000/-

No. 25-7/87-L1.—P.L.J. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No	Policy No. &	Name of Incurant	Amount (R _S .)
1.	331850-C dt. 18-12-80	Shri Y. Ganapathi Rao	10,000
2.	456125-C dt. 21-1-83	Shri Karunama(hur (E)	20,000
3.	184372-P dt. 8-7-71	Shrì B. Anjanappa	1,000

No. 25-31/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned again, t dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	524336-P dt. 19-10-83	Shri B.K. Biswas	10,000
2.	426743-C dt. 8-7-82	Shri Hali Ram Sharma	10,000

The 28th August 1987

NOTICE

No. 25-10/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

Sl. Policy No. & No. Date	Name of the Insurant	Amount (Rs.)
1. 49257-NM dt. 15-6-81	Shri V. P. Sadanendan	6,000
2. A-7976 dt. 1-4-77	Shri Badrinath	2,000

JYOTSNA DIESH Director (PLI)

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 25th August 1987

No. NCDC: 1-4/83-Admn.—In exercise of the powers conferred by Section 23(1) of National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (No. 26 of 1962) the National Cooperative Development Corporation with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments to the National Cooperative Development Corporation Service Regulation, 1967, namely:—

- (1) These Regulations may be called NCDC Service (Second Amendment) Regulations, 1987.
 - (2) These shall come into effect from the date of their publication in the Gazette of India.
 - II. In Regulation 32(3), for the abbreviations and figures "Rs. 2,000" and 'Rs. 1,000', the abbreviations and figures 'Rs. 5,000', and 'Rs. 2,500', shall respectively be substituted.

R. V. GUPTA Managing Director

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 5th June 1987

No. 10/87.—In terms of Advice from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, Jeevan Deep, Sansad Marg, New Delhi-110 001 vide letter No. F. 2(6)87-IF. I dated the 23rd April 1987 from the Under Secretary to the Government of India, the IFCI Staff Regulations, 1974 framed by the Industrial Finance Corporation of India, in terms of Section 43(1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 with amendments upto the 27th October 1986 is hereby published in the official gazette.

M. L. KAPOOR

Asstt. General Manager (Admn. & Pers.)

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

IFCI STAFF REGULATIONS, 1974

Framed by the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India with the previous approval of Industrial Development Bank of India under Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

In exercise of the powers conferred by Section 43 (1) read with clause (k) of sub-section (2) of Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, (XV of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India hereby make the following Regulations to govern the duties and conduct, salaries, allowances and conditions of service of the Staff of the Corporation.

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short Title & Commencement:

- (1) These Regulations may be called the Industrial Finance Corporation of India (Staff) Regulations, 1974.
- (2) These Regulations shall come into force from the 1st April, 1974.

2. Applicability

- (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), these Regulations shall apply to every whole-time employee of the Corporation:
 - (a) who was in the service of the Corporation on the date of commencement of these Regulations, or
 - (b) who is or has been appointed or taken in the service of the Corporation on or after the said date of commencement of these Regulations.
- (2) These Regulations shall not apply, except as otherwise provided by or in pursuance of these Regulations, or to such extent as may be specially or generally prescribed by the Board, to—
 - (a) Staff employed on a part-time basis or on special contracts.
 - (b) apprentices, casual workers, workers employed on daily wages and job workers,
 - (c) employees who are on deputation from the Central or State Governments or from any other body for whom special terms have been laid down in agreement with the respective lending authorities, as the case may be, and
 - (d) the Chairman of the Corporation who is appointed by the Central Government, in consultation with the Industrial Development Bank of India in terms of Section 10 (1) (a) of the IFC Act, 1948 and whose salary and allowances are determined by the Industrial Development Bank of India with the approval

of the Central Government in terms of Section 10 A (1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, except, to the extent, if any, that may be stipulated in the terms of his appointment.

(3) Nothing in these Regulations shall operate to override any special agreement entered into by the Corporation with any employee or employees of the Corporation.

3. Definitions

In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "appellate authority" means the appropriate authority specified in Regulation 66;
- (b) "Board" means the Board of Directors of the Corporation;
- (c) "calendar month" means any of the complete months of January to December in any year;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board of Directors of the Corporation, and in relation to any powers exercisable by him includes any person whom the Central Government after consultation with the Industrial Development Bank of India may appoint in terms of Section 13 A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, to act in his place during the period of his temporary absence for any reason not involving the vacation of his appointment;
- (e) "Competent authority" means unless otherwise specifically stated in these Regulations, the Chairman in the case of employees holding Class I post and the General Manager in the case of other employees as also such other officer or officers of the Corporation to whom authority is delegated by the Board for the disposal of the matter or the exercise of the power for such purpose as may be specified by the Board;
- (f) "Corporation" means the Industrial Finance Corporation of India;
- (g) "Duty" includes---
 - (i) Service as a probationer provided that such probationary service is followed by confirmation;
 - (ii) duty rendered during the period of deputation on foreign service;
 - (iii) period during which an employee is on joining time;
 - (iv) period spent on casual leave duly authorised by the authority empowered to grant leave;
 - (v) period spent on attending a course of instruction or training under such authority or organisation and subject to such conditions or limitations as the Chairman may specify;
 - (vi) any other period which may be specially classed as 'duty' by the Chairman;
- (h) "family" means an employee's wife/husband and children ordinarily residing with and wholly dependant on the empolyce;
- (i) "Foreign Service" means service in which an employee receives his pay and allowances with the sanction of the Corporation from any source other than the Corporation;
- (j) "General Manager" means the officer who for the time being holds the office of the General Manager of the Corporation and in relation to any matter or power to be dealt with or exercisable by him, includes Deputy General Manager, Assistant General Manager and Chief Accountant;
- (k) "lien" means the title of an employee to hold substantively, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a permanent post to which he has been appointed substantively, i.e., held in a permanent vacancy;
- (1) "Manager" in relation to:
 - (i) Head Office. means, the officers in charge of the various Departments/Divisions, and who for the time being perform the duties of the said offices;
 - (ii) any other office or any branch, means the officer in charge of that office or branch;

(n) "officiate" means performing the duties of a post on which another employee holds a lien, or of a temporary post to which a permanent employee has been appointed.

Provided that the appointing authority may, if it thinks fit, appoint an employee in any officiating capacity to perform the duties of a vacant post on which no other employee holds a lien;

- (o) "pay" means the amount drawn monthly by an employee as—
 - (i) the pay which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity, or to which he is entitled by reason of his position in a cadre;
 - (ii) special pay and personal pay; and
 - (iii) any other emoluments which may be specially classed as pay by the Board;
- (p) "probationer" means an employee employed on probation in or against a substantive vacancy in the corporation;
- (q) "personal pay" means additional pay granted to an employee—
 - (i) to save him from a loss of substantive pay in respect of a permanent post due to a revision of pay or to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure; or
 - (ii) in exceptional circumstances, on other personal considerations;
- (qq) "public servant" means and includes a person as mentioned in section 21 of the Indian Penal Code as amended from time to time;
- (r) "service" includes the period during which an employee is on duty, on deputation to foreign service and on leave duly authorised, but does not, unless specially permitted by the authority empowered to grant leave, include any period during which an employee is absent from duty without permission or overstays his leave;
- (s) "Special pay" means an addition, in the nature of pay, to the emoluments of a post or of an employee granted in consideration of—
 - (i) the specially arduous nature of the duties; or
 - (ii) a specific addition to the work or responsibility;

Regulation after amendment

- (t) "substantive pay" means the pay to which an employee is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in a cadre;
- (u) "temporary post" means a post carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time, the incumbent holding such a post, being called a temporary employee.

4. Change in Regulations

The Board may amend the Regulations laid down herein from time to time with the previous approval of Industrial Development Bank of India in the manner prescribed in Section 43 (1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948.

Provided that no new Regulation or an alteration in an existing Regulation shall operate to reduce the scale of pay of an employee on which he is entitled to draw pay in a substantive capacity on the day the new Regulation or alteration comes into force.

5. Delegation of Powers

For the purpose of giving effect to the provisions of these Regulations, the Board may, by general or special order, under Section 40A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, delegate to the Chairman, General Manager, Deputy General Manager or Assistant General Manager or Chief Accountant, or to any other officer or officers of the Corporation, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such powers as it may deem necessary.

6. Power to Interpret and Implement Regulations

The power to interpret the Regulations shall vest in the Chairman of the Corporation who is also hereby empowered to issue from time to time such administrative instructions as may be necessary to give effect to, and carry out the purposes of the provisions of these Regulations or otherwise to secure effective control of the staff.

Explanation—Any interpretation made or instructions issued under this Regulation shall not be deemed to constitute any change or alteration of these Regulations within the meaning of Regulation 4.

CHAPTER II

APPOINTMENTS, PROBATION, LIEN & TERMINATION OF SERVICES

Section I-Appointments

7. Classification of Staff

(1) The staff of the Corporation to whom these Regulations apply shall be classified as under:—

Class I : Senior Officers
Class II : Junior Officers
Class III : Clerical Staff
Class IV : Subordinate Staff

- (2) The Board of Directors shall prescribe from time to time the pay of each post or group of posts and the Chairman the number of posts in each group.
- (3) Nothing in this Regulation shall be construed as authorising the Chairman, without the previous approval of the Board, to create a post the starting pay of which exceeds Rs. 1,000/- per mensem.
- 8. Authorities Empowered to make Appointments

Appointments to the service of the Corporation may be made as follows:

- (a) to posts in Class I by the Chairman provided that ex-post-facto approval of the Board shall be necessary for all appointments to the posts in Senior Officers' cadre.
- (b) to posts in Class II by the General Manager subject to such general or special directions as may be issued from time to time by the Board and/or by the Chairman.
- (c) to posts in Class III and IV by the Head of the Administration Department at Head Office, so far as Head Office staff are concerned, and by the Officer in Charge of the Branch Office, in the case of Branch Office Staff as also to posts in Class III of the Sub-Offices under their jurisdiction, and by the Officer in Charge of Sub-Office to posts in Class IV, subject to such general or special directions as may be issued from time to time by the Chairman or the General Manager.
- Appointments in Class III and IV posts, on probation, temporary or part-time basis
 - Appointments in the service of the Corporation in Class III and IV posts where the vacancies and the posts are of permanent nature shall be made on probation.
 - (2) Notwithstanding anything contained in these Regulations and subject to sub-Regulation (1) and such general or special directions as may be given in this behalf, the appointing authority may make appointments against temporary vacancies in Class-III and

Class-IV on a temporary or part-time basis on such terms and conditions as may be prescribed by the chairman but in no case shall the terms and conditions so prescribed be more favourable than those laid down in these Regulations for a permanent appointment carrying equivalent status or responsi-

10. Appointments

PART III—SEC. 4]

Appointments to the various posts in the Corporation—officers and others—by way of direct recruitment shall be according to the rules/procedure as may be framed/decided upon by the Board.

11. Certificate of Health

bility.

No person shall be appointed to the service of the Corporation unless he has been certified by a medical authority acceptable to the Corporation to be of sound constitution and medically fit. The fees payable for the medical test shall be reimbursed by the Corporation, at such rates as may be decided by the Corporation from time to time.

12. Verification of Character and Antecedents

- (1) No person shall be directly appointed to the service of the Corporation unless his character and antecedents are found satisfactory to the Corporation by verification in the case of appointments to all officer posts.
- (2) In respect of other direct appointments to the service of the Corporation, every person so appointed shall furnish at the time of his appointment a certificate of good moral character from a trustworthy person duly attested by a Subdivisional Magistrate or an officer superior to him or from a Gazetted Officer:

Provided that-

- (a) Where such a person is unable to produce the certificate, or
- (b) where a verification of character and antecedents is considered necessary for any other reason as e.g., security consideration, the detailed verification may be carried out.

13. Age

The age of a person at the time of his first entry into the service of the Corporation shall not be less than 21 years in the case of appointment to the posts in Class I & II and not less than 18 years in the case of other appointments.

14. Appointments to be made on minimum pay of grade

All first appointments shall be made on the minimum pay of the grade to which the appointment is made:

Provided that the Chairman may authorise the grant of not more than four initial increments in the scale of pay fixed for the grade in which the appointment is made, if the candidate---

- (a) possesses good academic or technical or professional qualifications, or
- (b) was in the temporary employ of the Corporation prior to such appointment, or
- (c) possesses special experience of particular value to the Corporation.

Provided further that the Board may on the recommendations of the Chariman, grant more than four increments in exceptional cases.

15. Reappointment in the Corporation's Service

- (1) No person who has been dismissed or who has ceased to be in the service of the Corporation, otherwise than on medical grounds or retrenchment, may be re-en-ployed except with the specific sanction of, and upon such terms and conditions as may be prescribed by the Board in the case of appointment to class I posts and the Chairman in other cases.
- (2) Except as otherwise provided by the Board or the Chairman, as the case may be, under sub-regulation (1), these Regulations shall apply to a person who is re-employed in the Corporation's service as if he had entered the service for the first time on the date of his re-employment.

16. Commencement of Service

Except as otherwise provided by or under these Regulations, 'service' of an employee shall be deemed to commence from the working day on which the employee reports for duty in an appointment under these Regulations at the place intimated to him by the Corporation, provided that if he reports in the afternoon, his service shall commence from the next following working day.

17. Provisions as to Substantive Appointments

- (1) Except as otherwise provided in these Regulations, two or more employees cannot be appointed substantively to the same permanent post at the same time.
- (2) An employee cannot be appointed substantively, except as a temporary measure, to two or more permanent posts at the same time.
- (3) An employee cannot be appointed substantively to a post on which another employee holds a lien.

Section II-Probation

18, Employees in Class I & II

An employee in Class I & II directly recruited to the Corporation's service shall be required to be on probation for a period which shall not be less than one year and not more than two years as may be fixed by the appointing authority at the time of his appointment:

- (i) Provided that the appointing authority may at his discretion waive, in special cases, the period of probation of any individual employee directly recruited to Corporation's service.
- (ii) Provided that where an employee is appointed to a Class I & II post by promotion or selection in a permanent vacancy, he shall be deemed to be holding that post in an officiating capacity, until he is confirmed in that post and shall not, unless otherwise specifically provided, be deemed to be on probation.

19. Other Employees

Employees other than employees in Class I and II, who are directly recruited against permanent vacancies, shall be required to be on probation for a period of one year or such extended period as the corporation may decide in its own discretion.

20. Power to Extend Period of Probation

Notwithstanding anything contained in Regulations 18 and 19, the period of probation of an employee may be extended at the discretion of the authority competent to appoint, but in no case may this period exceed three years.

21. Temporary Service in Lieu of Probation

Where an employee has rendered continuous temporary service prior to his confirmation in the Corporation's service, the provisions regarding the period to be spent on probation may be waived, at the discretion of the appointing authority, to the extent of the period of such temporary service.

Section III-Lien

22. Lien

Unless, in any case it be otherwise provided, an employee on substantive appointment to any permanent post acquires a lien on that post and ceases to hold any lien previously acquired on any other post.

23. Lieu when Retained

Unless his lice be suspended under Regulation 24, an employee holding substantively a permanent post retains a lien on that post—

- (a) while performing the duties of that post;
- (b) while deputed to foreign service or holding a temporary post or officiating in another post;
- (c) during joining time on transfer to another post, provided that if he is transferred substantively to a lower post or a post on lower pay or grade his lien will be transferred to the new post from the day next to the date on which he is relieved of his duties in the post from which he is transferred;
- (d) while on leave; and

(e) while under suspension, under Regulation 64.

24. Suspension of Lien

- (1) A lien of an employee on a permanent post which he holds substantively be suspended—
 - (a) if he is appointed in a substantive capacity to any other permanent post;
 - (b) if he is appointed provisionally to a post on which another employee would hold a lien had such lien not been suspended under this Regulation;
 - (c) if he is deputed to foreign service or transferred, whether in a substantive or officiating capacity, to another post and there is reason to believe that he will remain absent from the post on which he holds a lien for a period of not less than three years; and
 - (d) if there is reason to believe that the employee, by reason of illness or other special circumstances, will remain absent from the post on which he holds a lien for a period of not less than three years
- (2) An employee's lien which is suspended under this Regulation shall be revived if he ceases to hold a lien on any permanent post or if the circumstances in which the lien was suspended ceases to exist.
- (3) If an employee's lien on a post is suspended under this Regulation, the post may be filled substantively and the employee appointed to hold the post substantively shall acquire a lien on it provided that arrangement shall be reversed as soon as the suspended lien revives.
- 25. Cancellation of lien during absence from duty for a long time and Leave Preparatory to Retirement

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the lien of an employee shall be cancelled if he remains absent from duty after exhausting all leave admissible to him under these Regulations, after giving him a notice of 14 days and an employee shall have, during the period of his leave preparatory to retirement, no lien on any post held by him immediately preceding such leave or any time previously thereto.

Section IV-Termination of Service

26. Discharge during probation

During the period of his probation, an employee shall be liable to discharge at one month's notice or by payment of substantive pay for one month in lieu thereof. An employee may also resign from the Corporation's service by giving similar notice, or paying the substantive pay in lieu thereof, as the case may be:

Provided that nothing in this Regulation shall apply in cases where an employee holding a post substantively is appointed to a higher post on probation or officiates in a higher grade; who shall be liable to be reverted. Without notice or pay in lieu thereof, to his previous substantive grade if he fails to show satisfactory promise during such appointment.

27. Determination of Service by Notice

- (1) An employee shall not leave or discontniue his service in the Corporation without first giving notice, in writing, to the competent authority of his intention to leave or discontinue the service. The period of notice required shall be three months in the case of employees in Class I and II and one month in other cases. In case of breach by an employee of provisions of this subregulation he shall be liable to pay to the corporation as compensation a sum equal to his substantive pay for the period of notice required by him. The Competent Authority shall have the right to refuse for reasons to be communicated to the employee in writing, to accept resignation in a case where disciplinary proceedings against the concerned employee are contemplated or have been initiated or are pending.
- (2) A notice given by an employee under sub-regulation
 - (a) shall be valid or deemed to be proper only if the employee remains in the service of the Corporation

- on duty or on leave if so authorised by the competent authority, during the period of notice;
- (b) cannot be withdrawn once the resignation has been accepted by the competent authority;

Provided that all or any of the foregoing provisions contained in sub-regulations (1) and (2) may be relaxed or waived, either wholly or in part, by the competent authority at its discretion.

- Note: I.—The authority competent to make appointments in a particular post is the authority competent to accept the resignation of an employee from that post.
- Note: 2.—A resignation becomes effective only when the same has been accepted in writing by the competent authority and the employee is relieved of his duties. It is open to the competent authority to decide while accepting the resignation whether the resignation is to be given effect immediately after its acceptance or with effect from some prospective date. In the latter case, the date of its effect should be specified.
- Note: 3.—Where a resignation has become effective the employee ceases to be in the service of the Corporation. Any request for withdrawal of resignation, at that stage, if accepted, would amount to reemploying him in the service after condoning the period of break. Since this would involve financial commitment, ex-post-facto approval of the Board in the case of an employee in Class I and of the Chairman in other cases shall be obtained before a request for withdrawal of resignation, which has already become effective, is accepted.
- (3) The Corporation may determine the service of an employee after his confirmation in the Corporation's service, by giving him three month notice or pay in lieu thereof in the case of Class I and Π employees and one month's notice or pay in lieu thereof in the case of others.
- (4) The power to determine the service of an employee under sub-regulation (3) shall be exercised by the Chairman with the prior approval of the Board in the case of an employee in Class I and by the Chairman in the case of other employees.
- (5) Nothing in sub-regulation (3) shall affect the right of the appointing authority—
 - (a) to retire or dismiss an employee in accordance with the provisions of Regulations 33 and 61.
 - (b) to determine the service of an employee by giving him one month's notice or pay in lieu thereof on his being certified by a qualified medeial authority approved by the Corporation to be permanently incapacitated for further continuous service in the Corporation

Explanation 1—Discharge from the service of an employee who is not confirmed at the expiry of or during the period of his probation, in accordance with the provisions of Regulation 26. shall not be deemed to be the determination of service within the meaning of this Regulation.

CHAPTER—III

RECORD AND GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

28. Record of Service

A service record shall be maintained by the Corporation at Head Office in the case of employees in Classes I and II and at the office or branch in which the employee is serving in the case of other employees. The record shall be kept in such form and shall contain such information as may be prescribed in this behalf.

29. Confirmation

(1) Subject to the provision of sub-regulation (2) below, on the successful completion of the probationary period (including extended period or periods if any, an employee appointed on probation may be confirmed in the post or cadre on which he is borne with effect from the date of completion of his probationary period.

- (2) If in the cadic there is an employee who is holding an officiating appointment on probation (otherwise than on purely temporary basis), to a post in the same cadre, from a date earlier than the date of appointment of an employee on probation referred to in sub-regulation (1) above, the former employee shall have a prior claim for being confirmed in the service of the Corporation than the latter.
- (3) An employee holding an appointment against a temporary post shall be confirmed subject to such other considerations as e.g. suitability from the point of view of character, conduct and work, when a permanent post is available
- (4) Notwithstanding anything contained in this Regulation, the Board of Directors reserves the right to frame rules, laying down any general or special conditions for the confirmation of the staff.

30 Seniority

The seniority of an employee in any particular grade shall be determined according to the rules which may be approved by the Board in this behalf.

31. Promatton

All promotions shall be made at the discretion of the Corporation on the basis of the rules framed for the purpose by the Board and no employee have a right to be promoted to any post or grade.

32. Reversion

- (1) An employee transferred from one appointment to another shall be lable to be reverted or re-transferred to his former appointment without notice at any time within one year of such transfer.
- (2) An employee who has been appointed to officiate in a higher grade or appointment or whose confirmation in a higher grade or appointment is subject to his undergoing probation for any specified period shall be liable to be reverted without notice at any time, when he is so officiating or undergoing probation.
- (3) Where an employee is appointed by selection from the Corporation's staff to a post in Class I, he shall at any time during the period of his probation in respect of such post be liable to be reverted without notice to his previous substantive grade if in the opinion of the appointing authority, he has failed to show satisfactory promise or progress or is found otherwise unsuitable.
- (4) Nothing in this Regulation shall affect the provisions of Regulateion 61.

33. Superannuation and Retirement

(1) An employee other than an employee in Class IV, shall retire on the last day of the month in which he completes 58 years of age, whereas an employee in Class IV, shall retire on the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

The Corporation shall, however, have absolute right to retire an employee, if it considers necessary to do so in the interest of the Corporation, by giving him notice of not less than three months in writing, on completion of 30 years of service or 50 years of age, whichever shall first happen, or at any time thereafter. Such option to retire from the service shall also be available to an employee, in any class, after he completes 30 years of service or attains the age of 55 years, by giving three months notice in writing to the competent authority.

(2) The power conferred by sub-regulation (1) to retire an employee on completion of 30 years of service or on attaining the age of 50 years, or at any time thereafter, shall be exercisable by the Chairman in the care of officers in Class I, prior approal of the Board shall be necessary.

Explanation I.—For the purpose of this Regulation, service shall not include any period of service renederd by an employee before attaining the age of 21 years.

Explanation II.—Notwithstanding anything contained in this Regulation, where an employee has ordinary leave carned but not availed of as on the date of retirement, he may, at his option:

8-239 GI/87

(a) be permitted to avail of leave subject to a maximum of six months in respect of leave earned under these Regulations and in that case the employee will be deemed to retire from service at the expiry of the leave.

OR

(b) be paid a lumpsum amount which would be equivalent of pay as defined in Regulation 3(0) of these Regulations as on the date of his retirement, for the unavailed ordinary leave earned subject to a maximum of six months plus dearness allowance in respect thereof.

Explanation III.—In order to implement the power to retire an employee as mentioned in subregulation (1) above, the Corporation shall review the cases of such employees six months before they attain the age of 50 years and 55 years or before they complete 30 years of service for which purpose special review Committees shall be constituted by the Chairman for making recommendations in the matter.

- (3) Where an employee is re-employed in the Corporation's service or is permitted to be employed outside the Corporation while he is on leave preparatory to retirement he may be required or permitted to avail of such leave or any part thereof immediately after he ceases to be so employed but the period during which he is so employed shall not—
 - (i) if the re-employment is in the Corporation's service count for any purpose as service or duty in relation to his previous employment in the Corporation except to the extent provided for in the terms of reemployment.
 - if the employment is outside the Corporation, count for any purpose as service or duty in the Corporation except for purposes of Regulation 130 and Chapter IV of these Regulations.

Explanation IV.—'Date of Retirement' means the date on which the employee attains the age of superannuation in accordance with the provisions of this Regulation or the don which he is retired by the Corporation under sub-Regulation (1) of the Regulation or the date on which the employee voluntarily retires in terms of said sub-Regulation (1) as the case may be.

CHAPTER-IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

Section 1-Conduct and Disciplines

34. Scope of Employee's service

- (1) Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of an employed shall be at the disposal of the Corporation and he shall serve the Corporation in its business in such capacity, at such time and at such place and in respect of such duties as he may from time to time be directed.
- (2) Without prejudice to sub-regulation (1) the Corporation may—
 - (a) fix hours of work for its employees generally or differently for different employees or for different offices, branches or departments;
 - (b) require employees to be on active duty in shifts.
- (3) Notwithstanding anything contained in Regulation 140, it shall be open to the Corporation, subject to such terms and conditions as it may determine, to nost members of its staff, officers and others to its assisted concerns, other central and state level financial institutions etc. anywhere in India where exigencies of work call for such posting for such period as may be decided by the Corporation.
- 35. Duty to abide by Regulations, Orders and Instructions.
- (1) Every employee of the Corporation shall conform to and abide by these Regulations and shall observe and obey all orders, directions or instructions given to him by the Corporation or by any person or persons under whose lurisdiction, superintendence or control he may for the time being the place. He shall maintain at all times absolute integrity and devotion to duty and do nothing unbecoming of an employee of the Corporation.

- (2) Every employee shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees of the Corporation for the time being under his control and autho-
- (3) No employee shall, in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgement except when he is acting under the direction of his official superior and shall, where he is acting under such direction obtain the direction in writing, wherever practicable, and where it is not practicable to obtain the direction in writing, he shall obtain written confirmation of the direction as soon as thereafter as possible.

Provided that nothing contained in sub-regulation (3) shall be construed as empowering an employee to evade his respoinsibilities by seeking instructions from, or approval of, a superior official or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities.

36. Obligation to Maintain Secrecy

Every employee shall maintain the strictest secrecy regarding the Corporation's affairs and affairs of its constituents and shall not divulge, directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or of the Corporation's staff, unless compelled to do so by judicial or other authority in pursuance of any law for the time being in force or unless instructed to do so by a superior official in the discharge of his duties.

37. Employees to Promote Corporation's Interests

Every employee shall serve the Corporation honestly and faithfully and shall use his utmost endeavour to promote the interests of the Corporation and shall show courtesy and attention in all transactions and intercourse with the officers or representatives of any Government and Corporation's constituents or any other person who has dealings with the Corporation, as also any officers or employees of the Corporation.

- 38. Prohibition against Participation in Politics and Elections.
- (1) No employee shall be a member of, or, be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.
- (2) It shall be the duty of every employee to endeavour prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be subversive of the Corporation or of Government as by law established, and where an employee is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of, or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Corporation.
- (3) If any question arises, whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of the Chairman thereon shall this regulation, the decision of the Chairman thereon shall be final.
- (4) No employee shall canvass or otherwise interfere with, or use his influence in connection with, or take part, in an election to any legislature or local authority:

Provided that-

- (i) an employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted.
- (ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this Regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in

Explanation—The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-regulation.

39 Joining of Associations by employees

No employee shall join, or continue to be a member of, an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

40. Demonstration and Strikes

- (i) No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State the interests of the Corporation, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or which involves contempt of court, defamation or incitement to an office, and
- (ii) No employee who is not a "workman" within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947, shall resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other employee or employees of the Corporation.

Explanation I.—In the above Regulation, the term 'demonstration' includes wearing of badges with inscriptions expressing protest or resentment, organising processions with slogans, convening meetings open to public, displaying objectionable posters, issuing bulletins addressed to general public and deputation of large number of staff shouting slogans.

Explanation II.—In the above Regulation, the term 'strike means refusal to work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination, and includes

- (i) mass abstention from work without permission (which is wrongly described as "mass casual leave").
- (ii) refusal to work overtime where such overtime work is necessary in the Corporation's interest,
- (ili) resort to practices or conduct which is likely to result in, or results in the cessation or substantial retardation of work in the cessation of substantices would include what are called 'go-slow' work to rule', 'sit down', 'Pen-down', 'stay-in', 'token', 'sympathetic' or any other similar strike; absence from work for participation in a 'Bandh' or any similar movements.

41. Connection with Press and Radio

- (1) No employee shall; except, with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct, or participate in the editing or management of any newspapers or other periodical publication or make public or publish any document, paper, or information which may come into his possession in his official capacity.
- 2) No employee shall except with the previous sanction of the competent authority or except in bonafide discharge of his duties-
 - (a) publish a book himself or through a publisher, or contribute an article to a book or a compilation of articles, or
 - (b) participate in a radio broadcast or contribute an article or write a letter to a newspaper or periodical,

either in his own name or anonymously or pseudonymously or in the name of any other person:

Provided that no such sanction shall be required-

- (i) if such publication is through a publisher and is of a purely literary, artistic or scientific character;
- (ii) if such contribution, broadcast or writing is occasional and of a purely literary, artistic or scientific character.
- (3) For obtaining permission under clause (2) above, the employee is required to submit to the Competent Authority the full text of the talk-
 - (i) on a subject directly or indirectly connected with his official work;
 - (ii) of a purely literary, artistic or scientific character if any of the statement made therein is liable to be misinterpreted.

- Note: For the purpose of the above, the Competent Authority shall mean the Chairman in the case of Officers, and General Manager in the case of other staff.
- (4) The employee himself is responsible for ensuring that the broadcast or contribution made by him is covered under the proviso to Clause (2) above.
- 42. Criticism of the Corporation and the Government.
- (1) Save as provided for in sub-regulation (2) below, no employee shall in any radio broadcast or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion—
 - (i) which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Corporation or the Central Government or any State Government; or
 - (ii) which has the effect of disparaging the Corporation or its management or bringing the same into disrepute;
 - (iii) which is capable of embarassing the relations between the Corporation and the Central Government, or any State Government, or the Central Government and the Government of any State or between the Corporation and any other financial institution or institutions whether in India or outside or between the Corporation and any of its assisted concerns;
 - (iv) which is capable of embarassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State.

Provided that nothing in Clause (1) shall apply to any statement made or views expressed by an employee in his official capacity or in due performance of the duties assigned to him.

- (2) Nothing contained in sub-regulation (1) (i) above shall apply to 'bonafide' expression of views by an employee as an office-bearer of the IFC Employees' Association or any other recognised trade union of the employees for the purpose of safeguarding the conditions of service of such employees or for securing an improvement thereof.
- (3) Employees of the Corporation visiting foreign countries should refrain from giving expression to views on Indian or foreign affairs, and in particular, from making any written or oral statement, without specific prior approval of the head of the Indian Mission in the country visited.
- 43. Evidence before Committee or other Authority.
- (1) Save as provided in sub-regulation (3), no employee shall, except with the previous sanction of the General Manager give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority.
- (2) Where any sanction has been accorded under subregulation (1), no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Corporation or of the Central Government or of a State Government or any other financial institution.
 - (3) Nothing in this Regulation shall apply to-
 - (a) Evidence given at any inquiry before an authority appointed by the Government, Parliament or a State legislature, or the Corporation;
 - (b) evidence given in any judicial inquiry; or
 - (c) evidence given at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to Government or the Corporation.
- 44. Canvassing of non-official or other Inflence.

No employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any authority of the Corporation to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Corporation.

- 45. Employment of near relatives in firms having dealilngs with Corporation.
- (1) No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of

- his family in any company or firm, having dealings with the Corporation.
- (2) No employee belonging to Class I shall, except with the previous sanction of the competent authority, permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm having official dealings with the Corporation

Provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the Corporation or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the Corporation and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Corporation.

- (3) An employee shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm, initimate such acceptance to the competent authority and shal lalso intimate whether he has or has had any official dealings with the company or firm.
- (4) No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner the employee shall refer every such matter or contract to his superior authority and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

Explanation: In this Regulation, the expression member of the family in relation to the employee shall include:—

- (i) The wife or husband as the case may be, of the employee whether residing with him or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the employees by a decree or order of a competent court;
- (ii) Son or daughter or step-son or step-daughter of the employee wholly dependent on hm, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived by or under any law;
- (iii) Any other person related, whether by blood or marriage to the employee or to his/her wife or husband, and wholly dependent on him.
- 46. Acceptance of Gifts.
- (1) Save as otherwise provided for in these Regulations, no employee shall, except with the previous sanction of the competent authority solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to solicit or accept any gift of more than trifling value from any other person having official dealings with the Corporation or from any subordinate staff.
- (2) If the question arises whether any gift is of triffing value or not or where an employee is in doubt whether the gift offered to him is of a triffing value or not, a reference shall be made to the competent authority, whose decision thereon shall be final.

Explanation—The expression 'gift' shall include free transport, boarding, lodging or other services or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the Corporation or the employee.

- Note—I. A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.
- Note—II. An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealings with him or from industrial or commercial firms, or organisations etc.
- (3) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, an employee shall not accept any gift from persons with whom he has official dealings.
- 46. A. Givinfg or Taking of Dowry.

No employee shall-

- give or take or abet the giving or taking of dowry, or
- (ii) demand directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case maybe, any dowry.

Explanation—For the purposes of this rule 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

47: Subscriptions.

No employee shall, except with the previous sanction of the Corporation, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of any lunds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

- 48. Investments, Leading and Borrowings.
- (1) No employee shall speculate in any stock, share or other investment or other commodities of any description:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prohibit an employee from making a bona-fide investment of his own savings in such a manner as he may wish.

Explanation—The habitual purchase or sale or both of stocks, shares, securities or other investments shall be deemed to the speculation within the meaning of this sub-regulation.

(2) No employee shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

Explanation—For the purpose of this sub-regulation, the expression 'members of family' shall have the same meaning as given in Explanation to Regulation 45.

- (3) If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the decision of the Chairman thereon shall be final.
- (4) No employee, shall, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf, except with the previous sanction of the competent authority, lend money as principal or agent to any person within the local limit, of the station in which the employee is for time being on duty, at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid:

Provided that an employee may, without such sanction make an advance or pay or lend small amounts to a private servant or give a purely temporary loan of small amount free of interest to a personal friend or relative.

Explanation—For the purpose of this sub-regulation, lending will not include the deposit of money with the Post Office and commercial and co-operative banks.

(5) No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank or a firm of standing duly authorised to conduct banking business, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf, bortow money from or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person within the local limits of the station in which the employee is for the time being on duty or with whom he is likely to have official dealings, nor shall he permit any member of his family, except with the previous sanction of the competent authority, to enter into any such transaction:

Provided that an employee may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a bonafide tradesman.

Provided further that nothing in this sub-regulation shall apply in respect of any transactions entered into by an employee with the previous sanction of the competent authority.

(6) Where an employee is appointed or transferred to a post of such a nature or at such a station as would involve him in the breach of the provisions of sub-regulation (2) or sub-regulation (4) or sub-regulation (5), he shall forthwith report the circumstances, to the competent authority and shall, thereafter, act in accordance with such direction or instructions as may be given by that authority.

49. Private Trade and Employment

(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment:

Provided that an employee may without sanction, undertake honorary work of religions, social or charitable

nature or undertake occasionally work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer, but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority.

Explanation—Canvassing by an employee in support of the business of insurance agency, commission agency etc., undertaken, owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this sub-regulation.

- (2) Every employee shall report to the competent authority if any member of his family is engaged in any trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.
- (3) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority and except in the discharge of his official duties take part in the registration, promotion or management of any bank or a company which is required to be registered under any law for the time being in force or a co-operative society for commercial purposes:

Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to any employee in relation to a company, co-operate society or a State Financial Corporation or any other concern on whose Board or other body entrusted with the management thereof, he is nominated by the Corporation as its nominee.

Provided further that nothing in this sub-regulation shall preclude an employee from taking part in the registration, promotion or management of a co-operative society formed by and substantially for the benefit of the employees of the Corporation and registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force or of a society or company for promoting art, science, religion or charity and registered under any law for the time being in force.

- (4) No employee may accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.
- 50. Insolvency and Habitual Indebtedness.
- (1) An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. An employee against whom any legal proceedings is instituted for the recovery of any debt due from him for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the competent authority .
 - Note—The burden of proving that the insolvency or indebtedness was the result of circumstances which, with the exercise of ordinary diligence, the employee could not have foreseen, or over which he had no control and had not proceeded from extravagant or dissipated habits shall be upon the employee.
- Acquisition and disposal of movable and immovable property.
- (1) No employee shall, except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovables property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the employee if any such transaction is—

- with a person having official dealings with the employee; or
- (ii) otherwise than through a regular or reputed dealer,
- (2) Every employee shall report to the prescribed authority every transaction entered into by him either in his own name or in the name of his family, in respect of movable property if the value of such property exceeds Rs. 1.000/- in the case of an employee holding any Class I or Class II post or Rs. 500/- in the case of an employee holding any Class III or Class IV post.

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained if any such transaction is—

- (i) with a person having official dealings with the employee; or
- (ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

Explanation—For the puropse of this sub-regulation the expression 'movable property' includes, 'inter-alia', the following property namely—

- (a) jewellery, insurance policies the annual premia of which exceeds Rs. 1,000/- or one sixth or the total annual emoluments of the employee whichever is less, shares, securities and debentures;
- (b) loans advanced by such an employee whether secured or not:
- (c) motor cars, metor cycles, horses or any other means of conveyance; and
- (d) refrigerators, radios and radiograms.
- (3) Every employee shall on his first appointment in the Corporation's service and thereafter within the first week of January in each year submit a return of his assets and liabilities in such form as the Chairman may prescribe in this behalf giving the full particulars regarding—
 - (a) all immovable properly owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;
 - (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;
 - (c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him; and
 - (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.
 - Note—In all returns, the values of items of movable property worth less than Rs. 1,000/- may be added and shown as a lump sum. The values of articles of daily use such as clothes, utensils, crockery, books etc., need not be included in such return.
- (4) The provisions of sub-regulations (1) and (3) of this Regulation shall apply ordinarily to all Class I employees serving whether in a temporary, probationary, officiating, or substantive capacity or deputed, or placed on foreign service but at the discretion of the Chairman, may be applied by a general or special order in this behalf to employees in other classes also.
- (5) The Chairman may, at any time, by general or special order, require any employee to submit, within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the competent authority, include the details of the means by which, or the source from which, such property was acquired.
- 52. Employees of the Corporation to be deemed for certain purposes as Public Servants.

The employees of the Corporation shall be deemed 'public servants' under clause 12 of Section 21 of the Indian Penal Code as provided by the Criminal Law Amendment Act, 1958 and the provisions of the said Penal Code and the Prevention of Corruption Act, 1947 in relation to public servants shall be applicable to them.

53. Vindication of acts and character of employees.

No employee holding any Class I or Class II post shall, except with the previous sanction of the competent authority have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.

Explanation—Nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity, and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the competent authority regarding such action.

54. Bigamous Marriages.

(1) No employee who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the competent authority, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.

- (2) No female employee shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the competent authority.
- 55. Consumption of intoxicating drinks and drugs, An employee shall—
 - (a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;
 - (b) not be under the influence of any intoxicating drinks or drugs during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not effected in any way by the influence of such drink or drug;
 - (c) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;
 - (d) not appear in a public place in a state of intoxication; and
 - (e) not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation:—For the purpose of this Regulation, public place means 'any place or permises (including clubs, even exclusively means for members where it is permissible for the members to invite nots members as guests, bars and restaurants, conveyance) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.—.

56. Public Demonstration in Honour of an employee.

No employee holding any Class I or Class II post shall, except with the general or special sanction of the competent authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee:

Provided that nothing in this Regulation shall apply to-

- (i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of an employee or any other employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quitted the service of the Corporation; or
- (ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainments arranged by public bodies or institutions.
- Note—Exercise of pressure or influence of any sort on an employee to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially private or informal character, and the collection of subscription from Class III or Class IV employees under any circumstances for the entertainment of any employee of the Corporation not belonging to Class III or Class IV is forbidden.

57. Absence from Duty.

(1) An employee shall not absent himself from his duties without having first obtained the permission of the competent authority, nor shall he absent himself in case of sickness or accident without submitting a sufficient medical certificate:

Provided that in the case of temporary indisposition the production of a medical certificate may at the absolute discretion of the competent authority, be dispensed with.

- (2) An employee who absent himself from duty without leave or overstays his leave, except under circumstances beyond his control for which he must tender a satisfactory explanation shall not be entitled to draw any pay and allowances during such absence or overstayal, and shall further be liable to such disciplinary measures as the competent authority may impose. The period of such absence or overstayal may, if not followed by termination of services under Regulation 27 or dismissal under Regulation 61, be treated as period spent on ordinary, sick, special or extraordinary leave as the competent authority may determine.
- 58. Absence from Station.

An employee holding a Class I or II post, must not absent himself from his station overnight without obtaining the previous sanction of—

(a) the Chairman if the employee himself holds the post of the General Manager;

- (b) the General Manager in case of Class I employees; and
- (c) Head of the Department, in other cases.

Provided that the competent authority, as aforesaid, may dispense with the above requirement where it so deems fit or where it is satisfied that having regard to the nature of the circumstances in each case, it was not possible for the employee to obtain the previous sanction before leaving the station overnight.

- Employees to conform to hours of work and not to be late in attendance.
- (1) Unless otherwise required or permitted, every employee shall conform to the hours of work fixed for him and shall not be late in attendance.
- (2) An employee who is habitually late in attendance shall, in addition to such other penalty as the competent authority may deem fit to impose, have one day of casual leave forfeited for every three days he is late in a month. Where such an employee has no casual leave due to him the period of leave to be so forfeited may be treated as ordinary or extra-ordinary leave as the competent authority may determine
- Employees detained or arrested for debt or on criminal charge.
- (1) An employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in pursuance of any process of law, shall forthwith report or cause to be reported to the competent authority the fact of such arrest or detention together with such facts and information leading to the arrest or detention as the case may be, as are within his knowledge.
- (2) An employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 61 if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the competent authority, either involves gross moral turpitude or has a hearing on any of the affairs of the Corporation or on the discharge by the employee of his duties in the Corporation the opinion in this respect of the competent authority shall be conclusive and binding on the employee. Such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in Regulation 61 shall apply to such imposition.
- (3) Where an employee has been dismissed in 'pursuance of sub-regulation (2) and the relative committal or conviction is set side by a higher court and further in the case of a convision, the employee is acquitted of all blame, he will be reinstated in service.
- (4) Where an employee is reinstated in service under sub-regulation (3), the period for which he was absent from duty by reason of dismissal under sub-regulation (2), shall be treated as a period spent on duty and the employee shall be entitled to pay and allowances to which he would have been entitled if he had not been so dismissed:

Provided that such pay and allowances shall be payable subject to adjustment of any subsistence allowance or, other amount paid to him by the Corporation in respect of the period concerned.

Explanation—In this Regulation, committal or conviction shall mean committal or conviction by the lowest court or any appellate court.

60-A. Misconduct:

Without prejudice to the generality of the term 'misconduct', the following acts of omission and commission, in addition to those mentioned under Regulations 44 to 60 of these Regulations, would be treated as 'misconduct':

- (1) Theft, fraud or dishonesty in connection with the business or property of the Corporation or of property of another person within the premises of the Corporation.
 - (2) Taking or giving bribes or any illegal gratification.
- (3) Possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known sources of income by the employee or on his behalf by another person, which the employee cannot satisfactorily account for.

- (4) Furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment.
- (5) Acting in a manner prejudicial to the interests of the Corporation.
- (6) Wilful insubordination or disobedience, whether or not in combination with others, of any lawful and reasonable order of his superior.
- (7) Absence without leave or over-staying the sanctioned leave for more than 4 consecutive days without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation.
 - (8) Habitual late or irregular attendance.
- (9) Neglect of work or negligence in the performance of duty including malingering or slowing down of work.
 - (10) Damage to any property of the Corporation.
- (11) Interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the Corporation.
- (12) Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the Corporation or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment.
 - (13) Gambling within the premises of the establishment.
- (14) Smoking within the premises of the establishment where it is prohibited.
- (15) Collection, without the permission of the competent authority, of any money within the premises of the Corporation except as sanctioned by any law of the land for the time being in force or rules of the Corporation.
 - (16) Sleeping while on duty.
- (17) Commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude.
- (18) Absence from the employee's appointed place of work without permission or sufficient cause.
- (19) Purchasing properties, machinery, stores, etc., from or selling properties, machinery, stores etc., to the Corporation without express permission in writing from the competent authority.
- (20) Commission of any act subversive of discipline or of good behaviour.
- (21) Abetment of or attempt at abetment of any act which amounts to misconduct.

Note: The above instances of 'misconduct' are illustrative in nature, and not exhaustive.

61. Penaltics

The following penalties may be imposed on an employee, as hereinafter provided, for misconduct committed by him or for any other good and sufficient reasons:

Minor Penaltles.

- (a) Censure;
- (b) Withholding of increments of pay with or without cumulative effect;
- (c) Withholding of promotion;
- (d) Recovery, from pay or such other amount as may be due to him, of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation by negligence or breach of orders.

Major Penaltles.

- (e) Reduction to a lower grade or post;
- (f) Reduction to a lower stage in time scale;
- (g) Removal from service which shall not be a disqualffication for future employment; and
- (h) Dismissal.

Exploration:—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulation:—

(i) Withholding of increment of an employee on account of his work being found unsatisfactory or not being of the

required standard, or for failure to pass a prescribed test or examination;

- (ii) Stoppage of an employee at the efficiency bar in a time scale, on the grounds of his unfitness to cross the bar;
- (iii) Non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee to a higher post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;
- (iv) Reversion to a lower grade or post, of an employee officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct;
- (v) Reversion to his previous grade or post, of an employee appointed on probation to another grade or post, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment.
 - (vi) Termination of service:-
 - (a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment;
 - (b) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement, on the expiration of the period for which he was appointed or earlier in accordance with the terms of his appointment;
 - (c) of an employee appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement;
 - (d) of an employee on reduction of establishment;
 - (e) calling for the explanation of an employee or requiring to show improvement in his work; and
 - (f) termination of service or retirement under Chapter II.
 - (vli) Suspension under Regulation 64.
- (viii) Retirement of an employee by the Corporation under Regulation 33.
- 62. Procedure for Imposing Penalties
- (A) Major Penalties
- (1) No order imposing any of the major penalties specified in clause (e), (f), (g) and (h) of Regulation 61 shall be made except after an enquiry is held in accordance with this Regulation.
- (2) Whenever the competent authority is of the opinion that there are grounds for enquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself enquire into, or appoint any public servent (hereinafter called the enquiring authority) to enquire into the truth thereof.
- (3) Where it is proposed to hold an enough, the commetent authority shall frame definite charges on the basis of the allegations against the employee. The charges, together with a statement of the allegations on which they are based, it is of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of charges are proposed to be sustained, shall be communicated in writing to the employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the competent authority (not exceeding 15 days), a written statement whether he admits or denies any of or all the articles of charge.

Explanation:—It will not be necessary to show the documents listed with the charge sheet or any other document to the employee at this stage.

(4) On receipt of the written statement of the employee, or if no such statement is received within the time specified, an enquiry may be held by the competent authority itself, or by the officer appointed as enquiring authority under subclause (2) above:

Provided that it may not be necessary to hold an enquiry is respect of the charges admitted by the employee in his written statement. The competent authority shall, however, record its findings on each such charge.

- (5) Where the competent authority itself enquires or appoints an enquiring authority to hold an enquiry it may, by an order, appoint any public servant to be known as the presenting officer, to present on its behalf the case in support of the articles of charge.
- (6) The employee may take the assistance of any other employee of the Corporation, but may not engage a legal practitioner for the purpose. Provided that an employee shall not take the assistance of any other emuloyee who has two nending disciplinary cases on hand in which he is acting as Defence Assistant.
- (7) On the date fixed by the enquiring authority, the employee shall appear before the Enquiring Authority at the time, place and date specified in the notice. The enquiring authority shall ask the employee whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads quality to any of the charges, the Enquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee concerned thereon. The Enquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.
- (8) If the employee concerned does not plead guilty, the enquiring authority shall adjourn the case to a later date, not exceeding 30 (thirty) days, after recording an order that the employee concerned may, for the purpose of preparing his defence:
 - (i) inspect the documents listed with the charge-sheet;
 - (ii) submit a list of additional documents and witnesses that he wants to examine; and
 - (iii) be supplied with the copies of the statements of witnesses, if any, listed in the charge-sheet.
- Note: Relevance of the additional documents and the witnesses referred to in sub-clause 8(ii) above will have to be given by the employee concerned and the documents and the witnesses shall be summoned if the enquiring authority is satisfied about their relevance to the charges under enquiry.
- (9) The enquiring authority shall ask the authority in whose custody or possession the documents are kept, for the production of the documents on such dates as may be specified.
- (10) The authority in whose custody or possession the requisitioned documents are, shall arrange to produce the same before the enquiring authority on the date place and time specified in the requisition notice. PROVIDED that the authority having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interest of the Corporation. In that event, it shall inform the enquiring authority accordingly.
- (11) On the date fixed for the enquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge the proposed to be proved, shall be produced by or on behalf of the competent authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the presenting officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The presenting officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined but not on a new matter, without the leave of the enquiring authority. The enquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.
- (12) Before the close of the prosecution case, the enquiring authority may, in its discretion, allow the presenting officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case, the employee shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record; or to cross-examine a witness who has been so summoned.
- (13) When the case for the connectent authority is closed, the employee may be required to state he defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In other case, a copy of the statement of defence shall be given to the presenting officer, if any appointed.
- (14) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-

examination, re-examination and examination by the enquiring authority, according to the provision applicable to the witnesses for the competent authority.

- (15) The enquiring authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances annearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.
- (16) After the completion of the production of evidence, the employee and the presenting officer may file written briefs of their respective cases within 15 days of the date of completion of the production of evidence.
- (17) If the employee does not submit the written statement of defence referred to in Clause (3) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person, or through the assisting officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the enquiring authority may hold the enquiry ex-parte.
- (18) Whenever any enquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an enquiry cases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another enquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction the enquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself.

Provided that if the succeeding enquiring authority is of the oninion that further examination of any of the witness whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examin cross-examine and re-examine any such witness os hereinbefore provided.

- (19) (i) After the conclusion of the enquiry, report shall be prepared and it shall contain:—
 - (a) a gist of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (b) a pist of the defence of the employee in respect of each article of charge;
 - (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge; and
 - (d) the findings of each article of charge and the reasons therefor.

Explanation:—If in the opinion of the enquiring authority the proceedings of the enquiry establish any article of charge different from the original articles of charge, it may record its findings on such article of charge;

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

- (ii) The enquiring authority, where it is not itself the commetent authority, shall forward to the competent authority the records of enquiry which shall include—
 - (a) the report of the enquiry prepared by it under subclause (i) above;
 - (b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee referred to in Clause (13);
 - (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the enquiry;
 - (d) written briefs referred to in Clause (16), if any;
 - (e) the orders, if any, made by the competent authority and the enquiring authority in regard to the enquiring

(R) Action on the Engulry Report:

(1) The competent authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing authority the case to the inquiring authority for fresh or further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of sub-regulation (A) as far as may be.

- (2) The competent authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.
- (3) If the competent authority having regard to the findings on all or any of the articles of charge is of the opir that any of the penalties specified in Regulation 61 should be imposed on the employee it shall, notwithstanding anything contained in sub-regulation (C) make an order imposing such penalty.
- (4) If the competent authority having regard to the findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that no penalty is called for it may pass an order exenging the employee concerned.

(C) Minor Penaltles:

- (1) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in Clauses (a) to (d) of Regulation 61, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of misconduct or misbehaviour against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days. The defence statement, if any, submitted by the employeee shall be taken into consideration by the competent authority before passing the orders.
 - (2) The record of the proceedings shall include—
 - (i) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to the employee;
 - (ii) his defence statement, if any; and
- (iii) the orders of the competent authority together with the reasons therefor.
- (D) Communication of Orders:

Orders made by the competent authority under sub-regulations (A) and (C) shall be communicated to the employee concerned who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.

(E.) Special Procedure in certain cases:

Notwithstanding anything contained in sub-regulations (A), (B) or (C), the competent authority may impose any of the penalties specified in Regulation 61 in any of the circumstances given below:—

- (i) when the employee has been convicted on a criminal charge or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial; or
- (ii) where the competent authority is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an enquiry in the manner provided in this Regulation; or
- (iii) where the Board is satisfied that in the interest of the security of the Corporation, it is not expedient to hold any enquiry in the manner prescribed in this Regulation.
- (F) Employees on deputation from the Central Government or the State Government etc.
- (1) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an employee, who is on deputation to the Cornoration from the Central or State Government or another public undertaking, or a local authority, the authority landing his services (hereinafter referred to as the "Indiag Authority") shall forthwith he informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings as the case may be.
- (a) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee—
 - (a) If the Competent Authority is of the oninion that any of the minor penalties should be imposed on him, it may pass such orders on the case as it deems necessary after consultation

with the Lending Authority. Provided that in the vent of a difference of opinion between the Competent Authority and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority.

- (b) If the Competent Authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it should re-place his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.
- (3) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under clauses 2(a) it will be disposed of after consultation with the Lending Authority. Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it deems necessary.

63. Common Proceedings

Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common proceeding,

Note—If the authorites competent to impose a major penalty on such employees are different, an order for taking disciplinary action in common proceedings may be made by the highest of such authorities.

64. Suspension and Remuneration during Suspension

(A) Suspension:

- (1) The competent authority or any other authority empowered in that behalf by the Board by general or special order may place an employee under suspension—
 - (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
 - (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.
- (2) An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours, shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention by order of the competent authority, and shall remain under suspension until further orders.
- (3) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these Regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal and shall remain in force until further orders.
- (4) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the competent authority, on consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further enquiry, against him on the allegations on which the penalty or dismissal or removal was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the competent authority from the date of the original order of dismissal or removal and shall continue to remain under suspension until further orders.
- (5) An order of suspension made or deemed to have been made under this Regulation may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order.

(B) Remuneration durlong Suspension:

 An employee under suspension shall be entitled to draw subsistence allowance equal to 50 percent of his basic pay provided the competent authority is 9-239 GI/87 satisfied that the employee is not engaged in any other employment or business or profession or vacation. In addition, he shall also be entitled to draw Dearness Allowance admissible on such subsistence allowance and any other compensatory allowance of which he was in receipt on the date of suspension provided the competent authority is satisfied that the employee continue to meet the expenditure for which the allowance was granted.

Provided, however, that the total of subsistence and other allowances so calculated shall not be less than his substantive pay in case of employees in Class I and II categories. Class I and II categories. Provided that in the case of employee in Class III and IV, the subsistence allowance shall be equal to substantive pay plus 25% thereof for the first six months and substantive pay plus 50% thereof for next six months. If the enquiry proceedings are not completed within one year from the date the employee is placed under suspension, for the period beyond one year, the rate of subsistence allowance will be substantive pay plus 75% thereof.

(2) Where the period of suspension exceeds six months, in case of employee in Class I and II the Competent authority may vary the subsistence allowance for any period subsequent to period of first aix months as follows:—

Regulations after amendment

- (i) The amount of subsistence allowance may be increased to 75% of basic pay and allowance thereon if, in the opinion of the competent authority, the period of suspension has been prolonged for reasons (to be recorded in writing) not directly attributable to the employee under suspension.
- (ii) The amount of subsistence allowance may be reduced to 25% of basic pay and allowances thereon, if in the opinion of the competent authority, the period of suspension has been prolonged? due to reasons (to be recorded in writing) directly attributable to the employee under suspension.
- (3) If an employee is arrested by the police on a criminal charge & bail is not granted, no subsistence allowance is payable. On grant of bail, if Competent Authority decides to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance from the date he is granted bail. Fixation of pay on appointment on probation:—
 - (i) The pay of an employee on appointment on probation from one grade to another shall be initially fixed at the minimum in the scale of higher grade, the difference between the pay so fixed and substantive pay of the employee in the old scale, if the latter be more, being treated as personal pay;

- On confirmation

(ii) On confirmation in the higher grade, the pay of an employee shall be fixed at the stage in the higher grade which is next above his substantive pay in the old scale as on the date of confirmation if such pay be higher than the pay drawn by him at the time of confirmation.

(C) Treatment of the period of suspension:

- (1) When the employee under suspension is reinstated, the competent authority may grant to him the following pay and allowances for the period of suspension:—
 - (i) If the employee is exonerated and not awarded any of the penalties mentioned in Regulation 61, the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the subsistence allowance paid to him.
 - (ii) If otherwise, such probation of pay and allowances as the competent authority may prescribe.
- (2) In a case falling under sub-Clause (i) the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In a case falling under sub-Clause (ii), it will not be treated as a period spent on duty unless the competent authority so directs,

SECTION—II: APPEALS

65. Right to Appeal

Subject to provisions of Regulations 66 to 72 an employee shall be entitled to appeal to the appellate authority in the manner hereinafter provided against an order imposing on him any of the penalties specified in Regulation 61.

66. Appellate Authority

An appeal shall lie :-

- (a) to the Board, in the case of an employee holding a Class-I post,
- (b) to the Chairman, in the case of any other employee.

Provided that no appeal shall be addressed to the Directors of the Board of the Corporation personally and any such action shall be deemed to be a branch of discipline.

67. Period of Umitation for Appeals

No appeal shall be entertained unless it is preferred within a period of six months from the date of the order appealed against.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the concerned employee had reasonable or sufficient cause for not submitting the appeal within such period.

- 68. Conditions which an appeal should satisfy
- (1) Every Employee submitting an appeal shall do so separately and in his own name.

Provided that in the case of a consalidated order passed against two or more employees in pursuance of joint enquiry under Regulation 62, a joint appeal in the names of the employees concerned may be permitted at the discretion of the appellate authority.

- (2) Every appeal shall be addressed to the authority to whom the appeal lies, and shall comply with the following requirements:—
 - (a) it shall be written in the official language of the Corporation or if not written in that language be accompanied by a translated copy in the official language of the Corporation and shall be signed by the employee or employees concerned,
 - (b) it shall not contain any disrespectful or improper language, shall be concise and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage,
 - (c) it should be legible and intelligible,
 - (d it shall contain all material statements and arguments relied on and shall be complete in itself,
 - (e) it shall specify the relief desired,
 - (f) it shall be submitted through the proper channel.
- 69. When Appeals may be withheld
- (1) An appeal may be withheld by the competent authority if:
 - (a) it does not comply with or is not in accordance with the requirements of Regulations 67 and 68,
 - (b) it deals with a matter which does not concern the employee personally,
 - (c) it repeats an appeal which has already been duly decided and does not in the opinion of the competent authority, disclose and new facts or circumstances or points affording grounds for reconsideration of the case.
 - (d) it is an appeal in a case in which there is no right of appeal under these Regulations.
- (2) In every case in which an appeal is withhold under this Regulation, the competent authority shall inform the employee or employees concerned the fact of withholding the appeal and the reasons for withholding it:

Provided that if an appeal is withheld only on account of failure to comply with the provisions of Regulation 68, the appeal may be re-submitted within one month from the date on which the concerned employee had been informed

- of the withholding of the appeal and if so re-submitted, in a form which complies with the said provisions, it shall not be withheld.
- Appeal to be forwarded to appellate authority with due despatch

The competent authority shall, without any avoidable delay, forward to the appellate authority every appeal not withheld under Regulation 69. Every appeal so forwarded shall be accompanied by the comments or opinion of the competent authority in regard to the facts alleged and the grounds urged in support of the appeal.

71. Consideration of Appeals

- (1) In the case of an appeal against any order imposing any of the penalties referred to in clauses (b) to (g) of sub-regulation (1), of Regulation 61 the appellate authority shall consider:—
 - (a) Whether the procedure prescribed in these Regulations has been complied with, and, if not whether such non-compliance has resulted in failure of justice;
 - (b) whether the findings of the competent authority are justified;
 - (c) whether the penalty imposed is excessive, adquate or inadequate, and shall pass orders (i) setting aside, reducing, confirming or enhancing the penalty, or (ii) shall remit the case to the competent authority for a fresh or further enquiry and with such directions as may be deemed fit in circumstances of the case;

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the concerned employee is given an opportunity of making a representation against such enhanced penalty.

In the case of an appeal against any other order, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and pass such orders as it deems just and equitable.

- (3) The competent authority shall give effect to the orders passed under this Regulation.
- 72. No Appeal lies against order of appellate authority or order withholding appeal

An employee shall have no right of appeal against any order passed under Regulation 71 or against any order withholding an appeal under Regulation 69.

73. Joint Petitions

The provisions of Regulations 66 to 71 shall also apply to the extent they are relevant to petitions which concern more than one employee and are preferred jointly by a class or group of employees or by an association of employees recognised by the Corporation. A joint petition shall not be entertained if:—

- (a) it relates to a subject on which the Chairman or General Manager is competent to pass orders and no application for redress has been made to him;
- (b) it relates to a matter regarding the redress of which a specific procedure has been prescribed under any Regulation/order issued by the Corporation;

Or

- (c) it relates to an individual who has not joined in the petition.
- 74. Provisions when competent authority subsequently becomes appellate authority

Notwithstanding anything contained in these Regulations, where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of the appeal against such order, such person shall forward the appeal to the authority to which he is immediately subordinate and such authority shall, in relation to that appeal be deemed to be the appellate authority for the purposes of these Regulations.

75. Application of Chapter to temporary employee, employees on deputation etc.

Without prejudice to the other provisions of these Regulations or to the terms and conditions of their appointment, the provisions of this Chapter shall apply to temporary employees, part-time employees and employees on deputation from Central Government, State Government, Public undertakings, local authority etc.

CHAPTER V

PAY & ALLOWANCES, INCREMENTS, CONCESSIONS, FEES AND DUES ETC.

SECTION I-GENERAL CONDITIONS

76. Overriding effect of other Chapters

The provisions of this Chapter shall have effect subject to the other provisions of these Regulations.

77. Substantive appointments and holding of posts

Every employee shall by reason of his substantive appointment to a post or of his substantive position in a cadre, hold one of the posts specified, while on duty in that post or during joining time on transfer to another post and to which he shall revert when he is not—

- (a) under suspension, or
- (b) on leave other than casual leave or deputed to foreign service, or
- (c) holding a temporary post or officiating in another post,

Provided that if such an employee is transferred substantively to a lower post or to a post on lower pay or grade he will hold such a post from the day next to the date on which he is relieved of his duties in the post from which he is transferred.

- (2) On holding a post as provided by sub-regulation (1) the employee shall cease to hold any other post similarly held by him previously.
- (3) The grade attached to a post held by an employee as provided by this Regulation shall be considered his substantive grade for the time being.
- 78. Two persons not to draw pay and allowances of same post

Except as otherwise provided in these Regulations, no two persons may draw the pay and allowances of a particular post at the same time.

79. Pay and Allowances when not payable for purt of a month

No employee who leaves or discontinues his service during a month without due notice as required by Regulation 27 shall be paid any pay and allowance far part of a calendar month unless such notice has been waived by a competent authority.

SECTION II—PAY & ALLOWANCES

80. Pay and allowances

Except as otherwise provided in these Regulations, the pay and allowances of an employee shall be as may be decided by the Board from time to time and shall be payable only to those employees who are at the relevant time fulfilling the conditions subject to which they are admissible at that time.

- 80. When pay and allowances accrue and are payable
- (1) Subject to sub-regulation (2) and Regulation 82, the pay and allowances of an employee shall accrue with effect from the commencement of service of the employee, Pay and allowances are generally payable during each calendar month on the afternoon of the last working day of that month.

- (2) Unless otherwise specifically stated, where an employee is appointed to another post or is transferred from one post to another or is appointed to officiate in a higher grade or appointment or is deputed to serve in a post under another employer, his pay and allowances in the post to which he is so appointed or transferred or deputed shall commence to accrue from the date on which he takes over charge of that post if he assumed charge of the post before noon on that date and from the following working day, if he assumes charge in the afternoon of that date.
- 82. Pay and allowances how to be calculated

The pay and allowances for the period for which they are payable shall be calculated with reference to the service of an employee in a post for the time being held by him and the grade applicable to him during such service.

83. Pay and allowances of employees on trans?er etc.

Where an employee is transferred from one post to another he shall, during any interval of duty between the date of his handing over charge of the old post and the date of his taking over charge of the new post, draw the pay and allowances of the old or the new post, whicrever are less.

- 84. Refixation of pay on appoinment on probation
 - (i) The pay of an employee on appointment on probation from one grade to another shall be initially fixed at the minimum in the scale of higher grade, the difference between the pay so fixed and substantive pay of the employee in the old scale, if the latter be more, being treated as personal pay;

On confirmation

(ii) On confirmation in the higher grade, the pay of an employee shall be fixed which is next above his substantive pay in the old scale as on the date of confirmation if such pay be higher than the pay drawn by him at the time of confirmation.

84. A. Officlating pay

- (1) Subject to such special or general instructions as may be issued from time to time by the Corpn, the officiating pay of an employee shall be fixed in the manner indicated in sub-Regulations (2) and (3).
- (2) An employee who is appointed to officiate in a higher grade, shall, on such appointment, draw an officiating pay equal to the difference between his substantive pay in the old scale and the stage in the scale of pay of the post in which he is appointed which is next above his substantive pay in the old scale or if he is already officiating in an intermediate grade, he shall draw an officiating pay equal to the difference between the pay obtained by him in the intermediate grade and the stage in the scale of pay of the post in which he is now appointed which is next above the pay in the intermediate grade; provided that then the promotion is of a temporary nature and the circumstances of the promotion so justify, the Chairman may fix the pay of an employee at an amount less than that admissible under this Regulation.
- (3) If he reverts and is reappointed to officiate in that higher grade, his earlier officiating service in the higher grade will be taken into account for fixing his officiating pay and for permitting him to draw increments in the officiating grade in terms of Regulation 88.
- (4) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) to (3) of this Regulation the corporation may adopt a different procedure for fixation of pay as may be mutually agreed between the corporation and the Employees, Associatio, etc.

85. Next Below Rules.

Where an employee is prevented from officiating in a post in a higher grade for reason other than his inefficiency or unsuitability or his being on leave or lits foregoing officiating promotion on his own violation, he may be permitted to draw the pay and allowances applicable to such higher grade on each occasion on which, due to exigencies of service, the employee immediately junior to him in his cadre and group, or if that employee has been passed over by reason of his inefficiency or unsuitability or his being

on leave or his foregoing officiating promotion on his own violation, then the employee next junior to him not so passed over, is appointed to officiate in, and draws pay and allowances of such higher grade in a vacancy of not less than six months' duration;

Provided that all employees senior to the employee to whom the benefit under the substantive part of this Regulation is allowed, are also drawing, unless they have been passed for reasons aforesaid, the pay and allowances of such higher grade:

Provided further that not more than one employee may be permitted to draw under this Regulation the pay and allowances of such higher grade in respect of any one officiating vacancy.

- 86. Refixation of pay on transfer from one grade to another.
- (1) Where an employee is transferred from or appointed to another category or grade and the grades of his old post and new post are different, his substantive pay in the new post shall be fixed in such manner as the appointing authority may direct.
- (2) When an employee is transferred from one grade to mother and such transfer does not involve the assumption of duties or responsibilities of greater importance his initial pay in the new scale shall be at a stage which is equal to his substantive pay in the old scale, or if there is no such stage in the new scale, the stage next below that pay plus personal pay equal to the difference, such personal pay to be drawn until such time us it is absorbed by subsequent increments in the new scale,
- 87. Pay and Allowances when cease to accrue.

Pay and allowances of an employee shall cease to accrue and shall not be payable with effect from the cessation of his service:

Provided that, where the cessation of service:

- (a) is due to the employee leaving or discontinuing his service in the Corporation, and such cessation occurs, on or at the end of a holiday, his pay and allowances shall cease with effect from the close of business of the preceding working day;
- (b) is due to the dismissal of the employee, his and allowances shall cease with effect from the date of his dismissal;
- (c) is due to the death of the employee, his pay and allowances shall cease with effect from the day following that on which the death occurs.

Section III-Increments

68. Incements when accrue

(1) Subject to sub-regulation (4) and Regulation 57 in an incremental scale, the increment shall ordinarily accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service be substantive, probationary or officiating.

Provided that an employee shall draw the increment on the 1st of the month in which it would full due irrespective of the actual date of its accrual.

Provided however that-

- (1) an increment accruing during leave of any kind specified under Regulation 103 except Casual Leave will be granted only from the date of resumption of duty on return from such leave;
- (ii) an increment withheld as a measure of penalty will be granted only from the date of penalty ceases, and
- (iii) the date of an advance/enhanced increment granted due to passing of certain examinations, will be governed only by the relevant rules and regulations.
- (2) Where, consequent upon grant of extra-ordinary leave without pay and allowances and not counting for increment, the normal increment is postponed, such postponed increment will be granted from the first day of the relevant month irrespective of the day on which it actually falls due;

- and in the case of initial appointment and or promotion to a higher post, any increment in the substantive and/or the officiating post will be granted from the first day of the month in which it falls due even though thereby the normal incremental period of 12 months is not completed.
- (3) Where an employee is appointed to officiate in a higher grade, service in the higher grade will count for increments under sub-regulation (1) in the employee's substantive grade as well as in the higher grade and if between the two there is an intermediate grade in which he was officiating or would have been appointed to officiate had he not been so appointed in the higher grade, also in the intermediate grade.
- (4) The period during which an employe is on leave without pay will not count for increments unless otherwise specially authorised by the competent authority for reacons to be recorded in writing.
- 89. Adjustment of pay when employee degraded to a lower nost etc.
- (1) An order under these Regulations crosiding for the degradation of an employee to a lower rost or grade or to a lower stage in his incremental scale imposed as a disciplinary measure shall specify the period for which the decadation will be effective, the pay to be initially fixed in the lower post or grade, the time when increment will accrue in the lower post, grade or stage and whether, on restoration, it shall operate to postpone future increments.
- (2) where an order of penalty of delay or stoppage of increment of an employee or his degradation to a lower post or grade or to a lower stage in his incremental scale, is set aside or modified by virtue of these Regulations, the pay and allowances of the employee shall be regulated in the following manner:—
 - (a) if the said order is set aside, he shall be given, for the period such order has been in force the differonce between the pay and allowances to which he would have been entitled had that order not been made and the pay and allowances he had actually drawn.
 - (b) if the said order is modified, the pay and allowances shall be regulated and if the order so modified had been made in the first instance.

90. Increments in Officiating Grade

If an employee officiating in a higher grade proceeds on leave other than leave not counting for increments, such period of leave upto a maximum of 4 months at each time as is certified by the competent authority to be the period for which the employee would have continued to officiate in the higher grade but for his proceeding on leave shall count for purposes of increment in the higher grade as well as in any intermediate grade between his substantive grade and the higher grade in which he was officiating or would have officiated, in the same way as active service in the higher grade.

Explanation—Subject to the limitations or requirements of this regulation where the last day of leave, counting for increments under this Regulation, is immediately followed by any public holiday such holiday shall count for increment on condition that the holiday is treated as period of leave and the employee's leave account is debited accordingly.

91. Sanction for increments.

Sanction to draw increments shall be given by the competent authority or by such other authority as may be determined by the Board. At the discretion of the competent authority such sanction may be delayed if the employee is under suspension.

- 92. Withholding of increments, efficiency bar etc.
- (1) Subject to provisions of sub-regulation (2) to (4) of this Regulation and Regulation 89 no increment may be withheld except as a disciplinary measure. Each order withholding an increment shall state the period for which it is withheld and whether the postponement shall have the effect of postponing future increments.

- (2) If in an incremental scale there is an efficiency bar an employee shall not draw increments above that bar until he has been certified fit to do so by the competent authority in
- (3) On each occasion on which an employee is allowed to pass an efficiency bar which had previously been enforced against him, he shall be placed in the incremental scale at such stage as the authority competent to remove the bar may fix provided that such stage shall not be higher than that at which he would draw his pay if the bar had not been enforced against him and further that no increments granted on the removal of a bar shall have retrospective effect.
- (4) The provisions of sub-regulation (2) and (3) shall, so far as may be, apply also to any bar imposed in pursuance of a requirement that an employee should pass any departmental or other examination prescribed by the Corporation.

93. Premature increments

The Chairman may, in exceptional cases, grant premature increments to employees, provided that in case of Class I officers prior approval of the Board shall be obtained in each

Section IV-Concessions

94. Grant of Honoraria etc.

- (1) The Board of Directors may determine the terms and conditions under which an honorarium or special pay or special increment; as the case may be, may be granted to an employee of the Corporation for passing the examinations of the Institute of Bankers or such other examination/s the passing of which is considered necessary in the interest of the Corportaion's service.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, but subject to such conditions, restrictions or limitations as may be imposed in regard to the grant of honoraria, the Chairman, for reasons to be recorded in writing may grant an employee an honorarium as remuneration for special work performed which is occasional or intermittent in character and either so laborious or of such special merit as to justify a special reward.
- N.B. (1) Sanction to grant of an honorarium should not be given unless the work has been undertaken with the prior approval of the Chuirman and its amount has been settled in advance.
 - (2) No honoraria will be given for temporary increases in the work-load or where the special work, though occasional or intermittent in character, is legitimately considered as a part of the normal duties attached to the post held by an employee.
 - (3) Honoraria under the above sub-regulation may be paid to a Class IV employee when he is called upon to drive cars or operate a duplicating machine occasionally in the absence of the regular Staff Car Driver or Gesteiner Operator respectively provided the employee himself is not holding the post of an identical nature and no regular officiating arrange-ment for short period is considered necessary or desirable.

95. Leave fare and Retirement fare Concessions

The leave and retirement fare concession may be granted to the staff of the Corporation in accordance with the provisions in this behalf approved by the Board from time to time.

The staff of the Corporation may be permitted to draw advances (advances for construction of house purchase of conveyance, flood relief, etc.) interest-bearing or otherwise, subject to such terms and conditions as may be approved by the Board from time to time.

- 97. The decisions of the Board under Regulations 96 shall be circulated to the staff members in the form of Administration Circulars to be issued by the Corporation, and until fresh instructions are issued in this behalf, the existing orders shall continue to be in force.
- 98. Financial Assistance for Vindicating Official Position

The Board may prescribe the circumstances in which and the conditions and limitations subject to which financial assistance may be granted to an employee, or as the case may

be the defence of an employee may be authorised, if any legal proceedings are initiated by or against the employee in respect of matters arising out of or connected with his official duties or position.

Provided that nothing in this Regulation shall apply to proceedings in respect of matters not arising out of or connected with the employees' official duties or position.

99. No Concessions unless Regulations amended

No concessions, the grant of which is not covered by these Regultaions may be given except with the special sanction of the Board. Provided, however, the Chairman may grant such concessions-amenities, as are not covered by these Regulations, if in his opinion it was necessary or expedient to grant such concessions-amenities, but the same shall soon thereafter, be got approved by the Board ex-post-facto.

- 100. Concessions not to be deemed as conditions of service and misuse thereof to be taken as breach of discipline
- (1) The concessions authorised under this section or as may be authorised from time to time, may not be deemed under any circumstance a part of the conditions of the service of an employee and may be withdrawn or suspended, either wholly or in part, as determined by the Board.
- (2) Any breach by an employee of any of the terms and conditions relating to the grant of concessions authorised herein or as may be authorised from time to time, or any misuse of any facilities or amenities in pursaunce of such concessions as may be provided by the Corporation, shall be taken as breach of discipline within the meaning of these Regulations.

Section V-Recovery of dues, fees or other income 101. Recovery of Dues

Unless the Corporation specifically agrees otherwise, any money or monies due and payable by an employee to the Corporation shall be liable at the discretion of the competent authority, to be summarily recovered and adjusted from his pay and allowances or by any other amount due and payable by the Corporation to the employee either in one lump sum or in such number of instalments as the Competent authority may determine.

- 102. Fees and income derived in official capacity from other sources to be paid to the Corporation
- (1) Subject to the provision of these Regulations, any fee capacity from sources other than the Corporation or from the efforts aided by the knowledge acquired by the employee in course of his service in the Corporation should be credited to the Corporation either wholly or in part, as the competent supports many determine. authority may determine.

Provided that nothing in this Regulation shall apply to any income derived from the sale or royalty of a book or other work, if the same-

- (a) is not aided by the knowledge acquired by an employee in the course of his service in the Cor-
- (b) though aided by the knowledge acquired by the though aided by the knowledge acquired by the employee in the course of his service in the Corporation reveals, in the treatment of subject matter the employees' scholarly study of or research on the subject and is not a part or in pursuance of his normal duties and responsibilities attached to the post held by him.
- (2) Unless the Chairman by special order otherwise directs, the amount to be credited to the Corporation under sub-Regulation (1) shall be restricted to one-third of any fees received by an employee, in excess of Rs. 400/-, or, if of a recurring nature, of Rs. 200/-, in a year.

CHAPTER VI LEAVE AND JOINING TIME

Section I-General Rules and Relating to Leave

103. Kinds of Leave

Subject to the provisions of these Regulations, the following kinds of leave may be granted to an employee-

- (a) ordinary leave;(b) casual leave;

- (c) sick leave;
- (d) special leave;
- (c) extra-ordinary leave;
- (f) maternity leave;
- (g) study leave;
- (h) leave on account; and
- (i) special disability leave.

104. Authority empowered to grant leave

Except as otherwise specifically provided in these Regulations, the power to grant leave shall vest in the Chairman, or any officer of the Corporation who has been delegated the power in terms of section 40-A of the IFC Act, 1948. All applications for leave shall be addressed to the authority empowered to grant leave.

105. Power to refuse or revoke leave

Leave cannot be claimed as of right, When the exigencies of service so require, discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the authority empowered to grant it.

106. Power to recall employee on leave

- (1) The authority empowered to grant leave can also recall an employee who is already on leave when the same is considered necessary in the interests of the Corporation.
- (2) All orders recalling an employee to duty before the expiry of his leave should state whether the return to duty is optional or compulsory. If the return is optional, the employee is entitled to no concession; if it is compulsory, the employee shall be treated as on duty from the date on which he starts for the station to which he is ordered and shall be entitled to draw travelling allowance as applicable under the rules.

107. Earning and lapse of leave

Leave is earned by duty only and lapses on the date on which an employee ceases to be in service.

However in the case of an employee dying in harness, the leave salary admissible in respect of the ordinary leave standing to his credit will be paid to his nominec(s)/heir(s) the leave salary for this purpose being calculated only on the last pay drawn while on duty.

108. Earlier return from leave

An employee on leave may not return to duty before the expiry of the period of leave (other than casual leave) granted to him unless he is permitted to do so by the authority which granted him leave.

109. Commencement and terminaiton of leave

- (1) The first day of an employee's leave is the working day succeeding that upon which he makes over enarge or is last on duty; and the last day of an employee's leave is the working day preceding that on which he reports his return to duty.
- (2) On the expiry of his leave, an employee shall report his return to duty in the forenoon of the working day succeeding the day on which his leave expires unless he is permitted by the authority empowered to grant leave to report in the afternoon.
- (3) The authority competent to sanction leave may permit the prefixation and/or affixation of Sundays or other recognised holidays to leave under such circumstances and subject to such conditions as it may deem fit.
- 110. Obligations to furnish leave address and not to take up any employment during leave or setting up of a private professional practice
- (1) An employee shall, before proceeding on leave, other than casual leave, furnish to the competent authority his address while on such leave and shall keep the said authority informed of any change in the address previously furnished.
- (2) An employee on leave shall not take up any service or accept any employment including the setting up of a private professional practice as accountant, technical or industrial

consultant, financial expert or as a legal practitioner without obtaining the sanction of the authority empowered to appoint him.

111. Station to which an employee should report on return

An employee on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place at which he was last stationed.

- 112. Requirements of medical certificate of illness and fitness
- (1) The competent authority may require an employee who applies for leave on reasons of health to produce a medical certificate in support of his application.
- (2) The competent authority may require an employee who has availed himself of leave for reasons of health to produce a medical certificate of fitness from a qualified medical authority acceptable to the Corporation before he resumes duty even though such leave was not actually granted on a medical certificate.

Provided that in the case of an employee, other than an employee in Class I & Class II the production of a medical certificate shall not be insisted upon if sick leave to be granted does not exceed four days, and the competent authority is satisfied with the bonafides of the reasons for such a leave.

113. Leave not admissible to an employee under suspension

Leave will not be granted to an employee under suspension and against whom proceedings are pending under Chapter IV of these Regulations.

SECTION II—ORDINARY LEAVE

114. When applications should be submitted.

Applications for ordinary leave should be submitted by employees in class I before the commencement of the quarter previous to the quarter in which the leave is required or is to commence and by other employees before one month from the date from which the leave is required.

Explanation—'Quarter' means the respective periods of three months ending 31st March, 30th June, 30th September and 31st December in each year.

- 115. Scale on which ordinary leave is earned
- (1) The amount of ordinary leave shall be one-eleventh of the period spent on duty.
- (2) In calculating ordinary leave earned by an employee, an account shall be first taken of the complete periods of eleven calendar months, if any, during which the employee has been on duty since joining service in the Corporation or, as the case may be since the date of his last return from leave and the employee allowed credit in his leave account for one month for each period of eleven months of duty as shall be admissible to him under sub-regulation (1). If thereafter there is any balance of period of duty left over or if there is no such complete period of 11 months, an account shall be taken of such balance or, as the case may be, the actual period of duty and the employee shall be credited with one day for 11 days of duty rendered by him. Fraction of a day of earned leave shall be taken as full day, if amounting to half a day or more and shall be ignored if amounting to less than half a day. In the case of employees on probation in Class III & IV the entitlement for ordinary leave will be 1/22nd of the period of duty during the first year of service, and thereafter at 1/11th of the period.

116. Ordinary leave due.

The ordinary leave due to an employee is the period which he has earned diminished by the period of leave actually taken.

117. Limits to which ordinary leave may be earned and taken

The period of ordinary leave which can be taken at any one time is 180 days in the case of all employees and no further ordinary leave can be earned by an employee after he has such amount of leave due to him.

Provided that if, at least three months before the date on which an employee shall have earned leave for the maximum period, he has formally applied for leave and the leave has been refused or he has ascertained in writing that leave, if applied for, will not be granted, such an employee may be permitted to earn leave in excess of the maximum aforesaid, upto the date specified by the Competent Authority.

118. Casual leave.

- (1) Casual leave may be granted to an employee upto a maximum of 15 days in each year commencing from January and ending with December (hereinaster referred to in this Regulation as 'calendar year'), subject to the following conditions that—
- (a) the exigencies of work permit the grant of the leave and no appointment is required to replace the employee one leave: and
- (b) the period for which leave is required at any one time does not exceed 7 days and does not in combination with public holidays exceed 10 days, but when the limits referred to above are exceeded, the entire period except holidays prefixed or suffixed shall be treated as period spent on ordinary leave or such other leave as may be admissible to the employee.

Provided that in the cases of persons (with less than six months' service) one Casual leave will be granted for every month's service.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub regulation (1), the Chairman in the case of Class I employees and the General Manager in other cases, may permit the grant of special casual leave without being subject to all or any of the limits or conditions laid down in that sub-regulation when the absence from active duty is necessitated—
 - (a) by order not to attend office in consequence of an infectious disease as e.g. cholera, smallpox, diphtheria, plague, typhus fever, etc.;
 - (b) by reason of the employee having to attend as a delegate a meeting of an Association or other body recognised by the Corporation in this behalf.
 - (c) by reason of an employee having been permitted to join the Territorial Army, Auxiliary Force, India Home Guards or other civil defence organisation or any other official organisation of similar nature recognised by the Corporation in this behalf;
 - (d) by reason of participation in sporting events of international or national importance in cases where an employee is selected for such participation by any National Sports Federation, Association or other body approved by the Corporation in this behalf or as a representative on behalf of a State, Zone or Circle if the sporting events are held on an inter-state interzonal or inter-circle basis.
 - (e) by other circumstances of a special or exceptional nature as e.g.—
 - (i) undergoing a sterilisation operation under the Family Planning Scheme;
 - (ii) donating blood on a working day;
 - (iii) inability to attend office during civil disturbances, curfews or general strikes;
 - (iv) appearing for such examinations as may be approved by the Corporation;
 - (v) any other special situation which the Chairman by a general or special order may declare as special or exceptional;

Provided that the period-

- (i) of special casual leave granted under (a) and
 (c) together with casual leave granted under sub-regulation (1) shall in no case exceed thirty days in the aggregate in any one calendar year;
- (ii) of special casual leave granted under clause (b) shall in no case exceed 21 days in any one calendar year;
- (iii) of special casual leave granted under clause (d) shall in no case exceed forty-five days in any one calendar year.
- (iv) of special casual leave granted under clause (e) shall in no case exceed by such number of day or days as may be authorised by the Competent Authority depending upon the nature of the circumstances in each case.

- (3) where an employee applies for leave in the circumstances referred to in clauses (a) to (e) of sub-regulation (2) and the grant of special casual leave for the same will result in the total period of casual leave granted to him in any one calendar year being in excess of the limits specified in the proviso to that sub-regulation, any period of absence which is so in excess shall be treated at the request of the employee as period spent on ordinary, sick or special leave if such leave is otherwise admissible, and if no such leave is admissible as period spent on extraordinary leave. Any special leave granted under this sub-regulation may, notwithstanding any thing contained in Regulation 120 be availed of even if ordinary leave is admissible.
- (4) In computing casual leave and special casual leave for the purposes of this Regulation, intervening holidays shall not be reckoned as days of casual leave.

119. Sick leave

- (1) During the full period of his service an employee may be granted sick leave upto a maximum period of 18 months and ordinarily sick leave admissible to an employee at any one time shall be such period as bears the same proportion to the length of his service in the Corporation as the period of 18 months bears to 30 years of Service.
- (2) Sick leave in addition to the maximum period of such leave admissible under sub-regulation (1) may be granted only in exceptional circumstances with the approval of the Board in the case of employees in Class I and the Chairman in other cases.

120. Special leave

During the full period of his service an employee may, when no ordinary leave is due to him, be granted special leave on private affairs upto a maximum period of twelve months and ordinarily special leave admissible to an employee at any one time shall be such period as bears the same proportion to the length of his service in the Corporation as the period of twelve months bears to thirty years of service.

Provided that if no ordinary and sick leave (including leave on account) is available, a Class IV employee suffering from the following diseases requiring prolonged treatment shall be granted special leave on half pay and quarter pay:

Name of diseases

- 1. Tuberculosis
- 2. Cancer
- 3. Leprosy
- 4. Jaundice
- 5. Poliomyelitis
- 6. Mental derangement
- 7. Heart diseases

121. Absence on account of quarantine

In case an employee is absent from duty on account of quarantine, the Corporation may, at the request of the employee treat such absence up to a maximum of three months as period spent on ordinary, sick or special leave, if such leave is otherwise admissible. Any special leave granted under this Regulation, notwithstanding anything contained in Regulation 120 be availed of even if ordinary leave is admissible.

122. Extraordinary leave

- (1) Extraordinary leave may be granted to an employee when no ordinary leave is due to him and when, having regard to his length of service and other relevant circumstances sick or special leave is not considered justified by the authority empowered to grant leave.
- (2) Except in exceptional circumstances, the duration of extraordinary leave shall not exceed 3 months on any one occasion and 12 months during the entire period of an employee's service. Grant of extraordinary leave in excess of 12 months may be made with the sanction of the Board in the case of employees in Class I and the Chairman in other cases.

(Please see Regulation No. 130 for Pay During Leave.)

123. Maternity leave

- (1) Maternity leave may be granted to a married female employee for a period not exceeding four months on any one occasion and twelve months during the entire period of an employee's service.
- (2) Maternity leave can also be granted in cases of miscarriage including abortion subject to the condition that the period of leave does not exceed 6 weeks and the application for leave is supported by a medical certificate from a medical authority acceptable to the Corporation.
- (3) Maternity leave may be combined with leave of any other kind, but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request is supported by a medical certificate.

124. Study leave

- (1) Study leave, not exceeding 12 months at a time and not more than 2 years in the whole period of an employee's service, may be granted to an employee to enable him to prosecute or undergo, in or out of India, an approved course of study, training or instructions which has a direct bearing on his sphere of duties. The grant of study leave will require the sanction of the Chairman in each case, shall be subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time and will not ordinarily be granted to those employees who have not rendered at least 5 years service to the Corporation or to those who are to retire within 3 years.
- (2) Every employee who is granted Study leave shall execute a Bond for the better protection of the Corporation in such form as may be prescribed in this behalf agreeing 'inter-alia' to return to duty after the expiry or termination of the Study leave and any extension thereof and to serve the Corporation for a minimum period of 3 years after his return to duty.

125. Leave on account

Leave on account may be granted only when other kinds of leave are not due and admissible under the rules. During leave on account an employee is entitled to the same leave salary as during half pay leave, which, in effect, means that leave on account is half pay leave granted in advance.

Conditions necessary for the grant of "Leave on account".

- It will be admissible to permanent employees of the Corporation.
- (ii) It will be admissible only when no other kind of leave (other than extra-ordinary leave) is due and admissible.
- (iii) It will be granted only if the authority empowered to sanction leave is satisfied that there is a reasonable prospect of the employee returning to duty on the expiry of the leave and putting in sufficient service to wipe off the debit balance. Leave on account cannot, therefore, be given as leave preparatory to retirement and has to be limited to the half pay leave, i.e. special or sick leave, the employee is likely to earn on his return.
- (iv) Where an employee who has been granted 'Leave on account' applies for permission to retire voluntarily, 'Leave on account' shall, if the permission is granted, be cancelled. An undertaking to this effect should be taken from the employee who avails of 'Leave on account'. The question whether the employee should be called upon to refund the amount of leave salary drawn during the period of 'Leave on account' already availed shall be decided on the merits of each case, e.g. if the retirement is voluntary, refund shall be enforced; if it is unavoidable by reason of ill-health incapacitating the employee for further service, no refund will be insisted upon.
- (v) The total amount of 'Leave on account' that can be allowed to an employee during the entire period of his service is limited to 360 days, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all may be otherwise than on medical certificate.

(vi) Grant of leave on account to employees undergoing treatment for tuberculosis.

'Leave on account' may be granted to permanent and also to those temporary employees, who have been in continuous service for more than 3 years, suffering from tuberculosis subject to the condition that the authority competent to sanction the leave satisfied that there is a reasonable prospect of the employee (i) returning to duty on the expiry of the leave, and (ii) earning thereafter sick/special leave not less than the amount of 'Leave on account' availed of by him. The prospect of returning to duty on the expiry of leave should be assessed on the basis of the certificate given by the medical authority. The prospect of earning at least equivalent amount of 'Leave on account' should be assessed with reference to the fact whether the employee would have enough service after his return to duty within which he would be able to wipe off the debit balance.

The appropriate medical authority will be:-

- (a) The Medical Officer in charge of a recognised sanatorium in the case of an employee undergoing treatment in a recognised sanatorium;
- (b) Tuberculosis Specialist recognised as such, by the State Administrative Medical Officer concerned in the case of an employee receiving treatment at his residence; and
- (c) A qualified Tuberculosis Specialist or a Civil Surgeon in the case of an employee suffering from tuberculosis other than pulmonary tuberculosis.
- (vii) Grant of 'Leave on account' to employees undergoing treatment for Leprosy.

The concession in sub-para (vi) above, and on the same conditions laid down therein, will also be extended to employees suffering for Leprosy. The appropriate medical authority in such cases will be:—

- (a) The Medical Officer in charge of a recognised leprosy institution where the patient is undergoing treatment; or
- (b) A Specialist in Leprosy recognised as such by the State Administrative Medical Officer concerned.

126. Special Disability Leave.

Special disability leave may be granted to an employee, whether permanent or temporary who is disabled by injury inflicted or caused in, or in consequence of the due performance of his Official duties or in consequence of his official position. The Corporation may extend the grant of special disability leave to cases of accidental injuries also where the disability is so exceptional in character as to justify the grant of such leave.

The conditions to which the grant of special disability leave is subject are:—

- Special disability leave can be granted on the certificate of the medical officer attending on the employee concerned and to the extent certified by him to be necessary. It shall not be extended except on the certificate of that authority.
- (ii) The disability must have manifested itself within 3 months of the occurrence to which it is attributed but the Corporation may, subject to its being satisfied as to the cause of the disability, rermit leave to be granted in cases where the disability manifested itself more than 3 months after the occurrence of its cause.
- (iii) The total amount of special disability leave on account of any one disability is limited to 24 months, of which, the first 4 months may be on average pay and the rest on half average pay. Special disability leave on half average pay may be converted into leave on average pay at the em-

ployee's option, to the extent otherwise admissible to the employee concerned under his leave rules, but half of such leave on average pay should be debited to the ordinary leave account.

- (2) Special disability leave counts as service, and is not debited against the ord nary leave account. It may be combined with any other kind of leave.
- 127. Leave admissible to temporary employees
- (1) Except as otherwise directed by the Chairman, temporary employees may be granted leave as follows:—
 - (i) casual leave, including special casual leave, on the same basis as admissible to permanent employees provided that where an employee joins service during the course of a calendar year, only proportionate amount of casual leave will be admissible.
 - (ii) ordinary leave to the extent of one day for every twentl-two days of service during the first year of their service, and thereafter on the same basis as admissible to permanent employees;
 - (iii) sick leave to the extent of one day for every twenty-two days of service provided that when sick leave due to such employee is two months, no further sick leave can be earned by him;
 - (iv) extra-ordinary leave after one year of service on the same basis as admissible to permanent employees provided that the total period of such leave during the entire period of temporary service does not exceed three months;
 - (v) maternity leave to temporary female married employees after one year of service on the same basis as admissible to permanent employees.
- (2) Leave under sub-regulation (1) will be admissible subject to the same conditions or restrictions as are applicable to permanent employees.
- (3) Except otherwise provided in their service conditions, no leave of any sort may be granted to a part-time employee.
- 128. Combination of leave.
- (1) Special Casual Leave granted under clause (d) of sub-regulation (2) of Regulation 118 cannot be combined with or taken in continuation of casual leave granted otherwise than under that clause.
- (2) Except as otherwise provided in sub-regulation (3) of Regulation 118, or unless otherwise permitted in special circumstances of a case, casual leave cannot be combined, with or taken in continuation of any other kind of leave.
- (3) Subject to sub-regulations (1) and (2) the authority empowered to grant leave may grant any kind of leave in combination with or in continuation of any other kind of leave admissible to an employee and may commute retrospectively periods of absence withut leave into extraordinary leave.
- 129. Maintenance of Leave Account and record of leave availed of.

A regular leave account (other than for casual leave) shall be maintained for each employee serving at Head Office by the Manager-in-Charac of Administration Division at Head Office and by the Branch Manager at the Branch offices in such form and manner as may be prescribed. The leave record shall indicate, 'inter alia', the various killeds of leave granted and availed of by an employee the particulars of sanction or refusal of leave and signature and date of the authority attesting the entries made in the record.

130. Pay during leave,

(1) An employee on ordinary leave shall draw a leave pay equal to his average pay:—

Provided that the leave salary of an employee, who is permitted to avail of ordinary leave under sub-regulation (3) of Regulation 33 and is concurrently re-employed in the Corporation's service or is permitted to be re-employed outside the Corporation, shall be determined by the Chairman of the Corporation and in no case shall the amount of such leave

salary together with the salary on such re-employment exceed the amount of his salary together with half-everage pay and allowances reduced to the extent of the pension equivalent of gratuity as admissible to him as on the date of his retirement as prescribed by sub-regulation (1) of Regulation 33.

Explanation—For the purposes of this Regulation, 'Salary' includes pay and allowances of whatever nature.

(2) An employee on sick leave shall draw leave pay equal to half-average pay for the first period of 12 months and equal to quarter average pay thereafter.

Provided that where an employee has rendered at least 3 years' service in the Corporation he may, during the full period of his service be permitted to avail himself of sick leave on average pay upto a period not exceeding half the amount of leave on half average pay admissible under this clause and on half average pay unto a period not exceeding half the amount of leave on quarter average pay admissible under this clause, the period of leave so availed of on average pay or half-average pay being entered in his sick leave account as twice the amount of sick leave actually availed of.

Provided further that in the case of employees in class III and IV, during the entire period of service an employee shall be eligible for sick leave of 18 months, which will be on half leave pay, commutable to 9 months on full leave pay.

NOTE: 'Leave pay' shall mean the monthly pay which the employee would have drawn while on duty but for his/her proceeding on leave.

Further, the words 'temporary employees' or 'temporary employees' appearing in various Regulations of the Staff Regulations have been substituted by 'employees on probation'.

- (3) An employee on special leave shall draw leave pay equal to half-average pay during the first period of six months of such leave and equal to quarter average pay thereafter.
- (4) Λ_Π employee on study leave shall draw leave pay equal to half average pay.
- (5) An employee on maternity leave shall draw leave pay equal to average pay.
- (6) An employee on extra-ordinary leave shall during the period of such leave draw no pay and the period spent on such leave shall not count for increment—

Provided that ---

- (i) in cases where the authority empowered to sanction increments is satisfied that the extra-ordinary leave was taken on account of illness or for any other cause beyond the control of the employee, the authority may permit the period of such extraordinary leave to count for increments; and
- (ii) in case where extra-ordinary leave is forfeited for late attendance, the period of leave to forfeited shall not be deemed to be a period which does not count for increments or in respect of which no pay and allowances are admissible.
- (7) The term 'average pay' in this Regulation shall mean:—

In the case of an employee in any class proceeding on ordinary leave, the pay drawn by him immediately before proceeding on leave.

Note—In respect of any period spent on deputation or foreign service out of India, the pay which the employee would have drawn if on duty in the Corporation in India shall be substituted for the pay actually drawn while calculating average pay.

Explanation—For the purpose of sub-clause (ii) of sub-regulation (7) of this Regulation, the 'substantive pay' shall be deemed to mean:—

(i) the pay of the permanent post which the employee holds substantively (i.e. the post on which he has been confirmed) or on which he holds lien or

- would hold a lien, had the lien not been suspended and includes special pay shown as part of the scale of pay of the post;
- (ii) the pay of the post in which the employee has been promoted to officiate subject to the condition that he should be holding the officiating appointment continuously for more than three years at the time he proceeds on leave. The three year limit shall include:
 - (a) all periods of leave during which the employee would have officiated in the post but for proceeding on such leave; and
 - (b) all periods of officiating service rendered in an equivalent or still higher post but for appointment to which he would have officiated in the post.

Section IV-JOINING TIME

131. Joining Time.

Joining time may be granted to an employee to enable him:-

- (a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or
- (b) to join a new post on return from leave of not more than four months' duration; or
- (c) to join a new post on return from leave other than that specified in clause (b) if he has not had sufficient notice of his appointment to the new post; or
- (d) to join a post under a foreign employer when deputed to serve under such employer and to return to his appointment in the Corporation after such deputation,

Provided that joining time may not be granted when no change in the headquarters of an employee is involved.

132, Period for which joining time is admissible:

(1) Joining time which may be allowed to an employee shall not exceed seven days plus the number of days duly spent on travel 'or the purpose of Joining the post or appointment concerned,

Provided that when an employee is transferred from one post to another at his own instance, the period of join ng time may be curtailed at the discretion of the Corporation.

Explanation—For the purpose of calculating the time spent on travelling, a 'day' shall mean each period of 24 hours or any part thereof commencing from the time of departure.

- (2) Where an employee on transfer from one centre to another does not avail himself of the joining time or his joining time has been curtailed due to exigencies of the Corporation's service, he may be allowed to avail himself of the Special Casual Leave to the extent of unavailed joining time, subject to a maximum of 7 days at any time after the date of reporting at new centre but before the completion of period of six months or such other extended period as may be agreed to by the Corporation for submitting supplementary travelling allowance bill in respect of his family and personal effects, provided he has advised the Corporation to this effect before proceeding on transfer. Sundays/holdays prefixed to and/or intervening in such a special casual leave will be reckoned as Special Casual Leave.
- 133. Calculation of joining time.
- (1) In calculating joining time admissible to an employee, the day on which he is relieved from his old post shall be excluded.
- (2) When holiday(s) follow(s) joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holiday(s).
- (3) If any employee is relieved from his old post or is authorised to make over charge of his old rost elsewhere than at his headquarters, his joining time shall be calculated from the place at which he is relieved or makes over charge.

(4) If an employee on leave, other than casual leave, is appointed to a new post, his joining time will be calculated from the station from which he proceeded on leave or from the place in which he received the order of such appointment, whichever calculation will entitle him to the less joining time:

Provided that where an employee certifies that he had to return to his old headquarters for winding up his personal affairs, etc., his joining time will be calculated from the old headquarters irrespective of the place where he spent his leave or received posting orders.

134. Regulation off joining time in combination with leave

Joining time in combination with leave shall be regulated as follows:—

- (a) When casual leave is permitted to be combined with joining time, joining time will commence to run in.

 the first instance and casual leave will commence at the expiry of joining time and the period spent on travel. Any public holiday immediately preceding or after the period of such casual leave shall not be included in joining time or casual leave;
- (b) When any other kind of leave is permitted to be combined with joining time, joining time will commence on the expiry of the leave and any public holiday intervening thereafter otherwise than in continuation of joining time, shall be included in joining time.

135. Joining time in excess of limits

Joining time in excess of the limits prescribed in these Regulations may be granted in special circumstances with the sanction of the Chairman.

136. Overstayal of joining time

An employee who does not ioin his post on the working day immediately after expiry of joining time and the period spent on travel admissible or allowed to him for that purpose, or after the expiry of leave granted in continuation of such joining time and the period spent on travel, shall not be entitled to any pay and allowances for any period of absence after such expiry and shall be deemed to have committed a breach of Regulation 57 in relation to such absence.

137. Pay and allowances during joining time.

The pay and allowances of an employee on joining time shall be determined in accordance with Regulation 83.

CHAPTER VII-MEDICAL FACILITIES

138. Medical Facilities.

(1) The Corporation may provide for its employees and their families, medical facilities to such extent and in such manner as may be provided in any scheme approved by the Board from time to time,

Provided that such facilities shall ordinarily be comparable, as far as possible to those available to Central Government employees of corresponding status.

Explanation—For the purposes of this Chapter, the term 'family' shall include the employee's wife or husband, as the case may be, children, step-children and parents who are mainly dependent upon the employee concerned.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation
- (1), the employees of the Corporation to whom the benefits of Central Government Health Scheme (C.G.H.S.) have been extended or are extended shall abide by the rules and regulations as may be laid down by the Central Government in this behalf for the beneficiaries from time to time.
- (3) In the case of members of the staff not covered by the C.G.H.S., the medical facilities to be made available to them shall be on the lines of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

CHAPTER—VIII FOREIGN SERVICE

139. Deputation of employees to join military service.

The terms and conditions subject to which an employee may be permitted to join military service shall be determined by the Board.

- 140. Deputation of employees to other services
- (1) Without prejudice to the provisions of Regulation 139, no employee of the Corporation may be deputed to serve under any other employer without the approval of the Chairman, who shall determine the duration of such deputation and terms and conditions on which the deputation shall take effect:

Provided that no employee may be transferred to foreign service against his will.

- (2) When the services of an employee of the Corporation are placed at the disposal of a foreign employer, it shall be a condition of the deputation that the foreign employer shall, during the period of such deputation, bear the entire pay and allowances of the employee admisible under these Regulations, as amended from time to time, or in accordance with the terms and conditions applicable to his service in the Corporation or as the competent authority may otherwise determine and all other cost of the services of the composes under these regulations including 'inter alia' the following:
 - (a) pay and allowances during joining time;
 - (d) the employer's contribution to the employee's enable him to join his appointment under the foreign employer and to return to his appointment in the Corporation on the termination of his deputation;
 - (c) Icave earned during the period of deputation;
 - (d) the employer's contribution to the employee's account in the Corporation's Provident Fund;
 - (e) contributions towards gratuity or any other sum to which the employee be eligible on his retirement, on such scale as may be fixed by the competent authority:
 - (f) if the employee is entitled to any other retirement benefit under the Corporation, an amount sufficient to cover the Corporation's liability towards the same for the period the employee is on deputation as may be determined in this behalf;
 - (g) cost of leave fare concession proportionate to the period of deputation, as determined by the competent authority;
 - (h) cost of medical facilities provided under these Regulations unless such facilities are provided by the foreign employer.
- 141. No right of property in contribution paid by foreign employer.

An employee in foreign service may not elect to withhold contributions and to forfeit the right to count as duty in the Corporation's service the time spent in foreign employ. Neither the employee nor the foreign employer shall have any right of property in contribution paid and no claim for refund can be entertained.

142. Employee on foreign service not to adcept pension or gratuity from foreign employer.

An employee transferred to foreign service man net without the sanction of the Cornoration accept any pension or gratuity from his foreign employer in respect of such service.

143, Leave during foreign service.

An employee in foreign service may not be granted leave otherwise than in accordance with these Regulations and not take leave or receive leave salary from the Corporation unless he actually quits duty and goes on leave.

144. Pay in foreign service not to be taken into account when appointed to officiate in the Corporation.

An employee in foreign service, if appointed to officiate in a post in the Corporation will draw pay calculated on the pay of the post in the Corporation on which he holds a lien or would hold a lien had his lien not been suspended and

that of the post in which he officiates. His pay in foreign service will not be taken into account in fixing his pay.

- 145. Reversion from foreign service.
- (1) An employee reverts from foreign service to the Corporation's service on the date on which he takes charge of his post in the Corporation provided that if he takes leave on the conclusion of foreign service before rejoining his post, his reversion may take effect from such date as the competent authority may determine.
- (2) When an employee reverts from foreign service to the Corporation's service, his pay and allowances will cease to be paid by the foreign employer and his contributions will be discontinued with effect from the date of reversion.

CHAPTER—IX

MISCELLANEOUS

146. Obligation to subscribe to the provident or other benefit funds.

Unless otherwise directed by the Board or the Chairman, every employee required to do so by the Regulations of the relative fund shall become a member of the Industrial Finance Corporation of India Employees' Provident Fund and of other benefit funds; if any, and shall agree to be bound by the Regulations of those Funds.

147. Obligation to subscribe to Insurance Scheme or fund instituted by the Corporation.

It shall be incumbent on every employee bound by these Regulations to subscribe to any insurance scheme or fund that may be instituted by the Corporation for the benefit of its employees and their families, and to be bound by the rules of the said scheme or fund:

Provided that nothing contained in this Regulation shall serve to curtail any superannuation benefits which may otherwise be admissible to an employee:

Provided further that nothing contained in this Regulation shall require an employee to subscribe to the said scheme or fund if he is exempted from so doing under the rules of the said scheme or fund.

148. Regulations to supersede the existing regulations and connected orders, administrative instructions etc., except to the extent adopted.

These Regulations shall supersede the provisions of the existing Regulations and all connected orders, administrative instructions, etc., issued thereunder for regulating the duties, conduct, salary, allowances and conditions of service of the employees of the Corporation;

Provided that the Board or Chairman, as may have been authorised under these Regulations, may adopt such of the provision or provisions of Regulations, orders, administrative instructions and practices in force on the date preceding the date of commencement of these Regulations or may provide for such subsidiary matters as may not have been provided for in these Regulations or may permit such of the procedures, practices, policies, forms, etc., being continued, followed or retained under these Regulations till such time fresh instructions or procedures, practices, policies, forms etc., consistent with the provisions of these regulations are issued.

149. Transitory provisions

Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) of regulation 1 as also Regulation 148, where certain provisions, scales, rates, procedures, practices, forms, etc.. are to be adopted or laid down by the Board or the Chairman in respect of certain matters under these Regulations, or in respect of certain subsidiary matters which may not have been provided for in these Regulations, the provisions, scales, rates, procedures, practices, forms etc., as may be actually in operation at the time of commencement of these Regulations, shall, without prejudice to the powers of the Board or Chairman enioned by these Regulations, and in the absence of any orders to the contrary continue to so operate and remain in force with full validity for a period of six months from the date of commencement of these Regulations or until further orders, whichever may happen first.

150. Regulations not be invoked for re-opening past or otherwise disposed of cases.

Unless in any case it may have been otherwise distinctly provided, in no circumstances past or otherwise disposed of cases will be reopened for being regulated in accordance with the Provisions of these Regulations and the pending cases will be decided either in the light of the transitory provisions in force under Regulation 149 of the provisions of these Regulations as may be deemed fit.

151. Oath and declarations to be subscribed by the Employees.

Every employee to whom these Regulations apply as provided in Regulation 2, shall subscribe to an oath for bearing true allegiance to the country and to the Constitution as by law established in form 'A' as also to the declarations in Forms 'B' and 'C' given below:—

FORM 'A'

OATH FOR BEARING ALLEGIANCE TO THE COUNTRY AND CONSTITUTION

do swear

(So help me God)"

Signature)

Date :

FORM 'B'

Declaration to be bound by the Staff Regulations:

Place

I hereby declare that I have read and understood the Industrial Finance Corporation of India (Staff) Regulations, 1974, and I hereby subscribe and agree to be found by the said Regulations.

Name in full:	
Nature of appointment:	
Date of appointment:	
Signature :	
Witness:	

FORM 'C'

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the Corporation nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to or in the possession of the Corporation and relating to the business of the Corporation.

Signed before me.

Date:

(Signature)

APPENDIX

ALLOWANCES

- (1) The Corporation's employees shall be eligible to the following allowances, at the rates and subject to the conditions as applicable to the employees of the Reserve Bank of India/Industrial Development Bank of India, and as may be adopted by the Board from time to time:
 - (i) Dearness allowance.
 - (ii) House Rent Allowance.
 - (iii) Compensatory (City) Allowance.
 - (iv) Family allowance.
 - (v) Local Pay.
- (2) The employees of the Corporation shall also be eligible to travelling and halting allowances while on tour, as also travelling allowance on transfer. Until fresh rules are framed by the Board of Directors in this behalf, the rules in force prior to the promulgation of these Regulations shall continue to govern the payment of these allowances.